हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2020 को अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

11-03-2020/1100/वाई.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या 2131 (स्थगित)

श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज): अध्यक्ष महोदय, सरकार की अति महत्वपूर्ण मंशा है कि लोगों को एक ही छत के नीचे सभी कार्यालयों की सुविधा मिल सके और इसके लिए सरकार व्यवस्था कर भी रही है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र भोरंज के बारे में बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भोरंज में जल शक्ति विभाग का डिवीज़न दिया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का तहदिल से आभार व्यक्त करती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बराड़ा, बगवाड़ा, दरबियार, पंजौत, दाड़ी, टिक्कर, भुल्ला और कंज्यैण कुल आठ पंचायतों का सब-डिवीज़न ऊल पड़ता है जोकि सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत है और इनका डिवीज़न हमीरपुर में है जोकि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। इन पंचायतों के लोगों को डिवीज़न लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है और जो नया डिवीज़न भोरंज में दिया गया है वह केवल 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं कि इन आठ पंचायतों को भोरंज डिवीज़न में सम्मलित किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोरंज की 17 पंचायतें ऐसी हैं जिनका ब्लॉक टोणी देवी है जोकि सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और उनका एस.डी.एम. ऑफ़िस हमीरपुर में पड़ता है व उनका पुलिस स्टेशन भोरंज में पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र या कोई लाइसेंस बनाने जैसे छोटे से काम के लिए 3-3 विधान सभा क्षेत्रों का चक्कर लगाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि छोटे से काम के लिए 3-3 विधान सभा क्षेत्रों का चक्कर लगाने से लोगों को निजात दिलाने के लिए क्या सरकार द्वारा इन पंचायतों को भोरंज डिवीज़न में ही सम्मलित किया जाएगा?

मुख्य मंत्री, श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

11/03/2020/1105/MS/YK/1

प्रश्न संख्याः 2131 क्रमागत---

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, वैसे तो प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया हुआ है। जहां तक माननीय सदस्या जी ने प्रश्न पूछा है कि इनके विधान सभा क्षेत्र का कुछ क्षेत्र; हालांकि इनका मूल रूप से प्रश्न तो यही है कि बी0डी0ओ0 ऑफिस, तहसील, एस0डी0एम0 ऑफिस और जल शक्ति विभाग का डिवीजन इत्यादि जो मेन-मेन ऑफिसिज हैं, वे एक छत के नीचे होने चाहिए। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अधिकांश जगह ये ऑफिसिज बने हुए हैं और जहां भवन बनकर तैयार हैं, उनका वर्षों से उपयोग भी कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्या ने कहा है यदि ऐसा करते हैं तो उस भवन का क्या करेंगे, एक प्रश्न यह भी आता है। हम इस बात से सहमत हैं कि जब सभी चुनाव क्षेत्रों की डिलिमिटेशन हुई, उसके कारण हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, राजस्व यूनिट्स और डवलपमैंट यूनिट्स सब आगे-पीछे हुए हैं क्योंकि विधान सभा क्षेत्र की सीमाएं परिवर्तित हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यावहारिक दृष्टि से जहां-जहां भी संभव हो पा रहा है; जैसे जहां मिनि सचिवालय दे सकते हैं ताकि एक छत के नीचे एस0डी0एम0 ऑफिस, लोक निर्माण विभाग का डिवीजन या सब-डिवीजन या तहसील इत्यादि ये सारी चीजें एक जगह कर सकते हैं तो हमने करने की कोशिश की है और अनेक जगहों में काम भी शुरू किया है। लेकिन सभी जगह यह संभव नहीं हो पा रहा है। जहां तक माननीय सदस्या का प्रश्न है और उसमें इनकी मंशा जो मैं समझ पाया हूं, वह यह है कि इनकी 8 पंचायतें जो भौगोलिक दृष्टि से, जैसे जल शक्ति विभाग का डिवीजन जो ऊहल में पड़ता है या अन्य हैं, उनको ये चाह रही हैं कि उन्हें भोरंज में शामिल किया जाए। जब हम इस प्रकार से 8 पंचायतों को वहां से काटकर करके दूसरे डिवीजन में डालने की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उस डिवीजन को जिस पंचायत से हम निकालते हैं, उस डिवीजन की जस्टिफिकेशन ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी कहा है कि भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक है कि ये 8 पंचायतें भोरंज में जोड़ी जाएं। इसमें मेरा यही कहना है कि आप इस बारे में लिखित रूप में दे दें, इसको हम करेंगे। इसमें ज्यादा कठिनाई वाला काम मुझे लगता है कि नहीं है। दूसरे, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने एस0डी0एम0 ऑफिस से संबंधित कुछ बातें कहीं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसा है कि कुछेक एरिया एस0डी0एम0 गोहर के पास पड़ता है और कुछेक एरिया एस0डी0एम0 थुनाग के पास पड़ता है। मेरे विधान सभा

क्षेत्र में बिजली के तीन डिवीजन डील करने पड़ते हैं जिनमें एक करसोग में पड़ता है, दूसरा थलौट में और एक जाकर गोहर में पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक बिजली बोर्ड के अलावा

11/03/2020/1105/MS/YK/2

अगर दूसरे डवलपमैंट ब्लॉक की बात कहें तो उसमें भी तीन ब्लॉक पड़ते हैं। जैसे गोहर ब्लॉक में 13 पंचायतें पड़ती है, उसके बाद बालीचौकी में 21 पंचायतें पड़ती है और लगभग 35 पंचायतें हमारे जंजैहली ब्लॉक में पड़ती हैं। अतः भौगोलिक दृष्टि से जहां लोगों को आने-जाने की सुविधा नज़दीक हो, उस दृष्टि से जो सुझाव यहां दिए हैं, उन पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों भारत सरकार के जनगणना विभाग ने नोटिफिकेशन कर दी है जिसके अनुसार सभी रेवेन्यू यूनिट्स को अब फ्रीज कर दिया गया है। अभी हम पटवार सर्कल को यहां से काटकर दूसरी जगह नहीं डाल सकते हैं। नया पटवार सर्कल नहीं बना सकते हैं। कानूनगो सर्कल नहीं बना सकते हैं। सब-तहसील, तहसील और एस0डी0एम0 का ऑफिस नहीं बना सकते हैं। कुछ जगह तो हमारी पब्लिक एनाउंसमैंट्स हैं लेकिन उनको भी हम तब तक पूरा नहीं कर सकते, जब तक हमारा जनगणना का काम पूरा नहीं हो जाता है। यह काम अप्रैल, 2021 में शायद पूरा होने की संभावना है। उसके बाद इन सारी चीजों को देखेंगे लेकिन आपने जो सुझाव दिये हैं इन दोनों सुझावों को आप लिखकर दे दें। हम निश्चित रूप से इन पर विचार करेंगे। हमारी सरकार की मंशा है कि लोगों को अपने काम करवाने के लिए दूर न जाना पड़े। लोगों को अपने कामकाज से संबंधित सुविधाएं अपने नज़दीक के ऑफिस में मिल सकें, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे।

11/03/2020/1105/MS/YK/3

प्रश्न संख्याः 2269 माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह (अनुपस्थित)

11/03/2020/1105/MS/YK/4

प्रश्न संख्याः 2594

श्री अनिल शर्माः अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने सूचना दी है उसके हिसाब से कलस्टर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का काम चल रहा है। वह काम मण्डी में 30 परसेंट, बासा में 80 परसेंट, दरंग में 5 परसेंट और सुन्दर नगर में 60 परसेंट हुआ है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न रहेगा कि रूसा के माध्यम से कलस्टर यूनिवर्सिटी की वर्ष 2014 से ही डी0पी0आर0 बननी शुरू हो गई थी

जे0के0 द्वारा----

11.03.2020/1110/JK/AG/1

प्रश्न संख्याः 2594

श्री अनिल शर्माः ---क्रमागत

और उसकी डी.पी.आर. के माध्यम से, जब मुख्य मंत्री जी मण्डी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो मुकेश जी ने भी कहा था कि ऊना क्यों नहीं? क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ज़वाब देंगे कि इसकी जो डी.पी.आर. गई थी, वह शिमला, धर्मशाला और मण्डी की गई थी। उन तीनों डी.पी.आर्ज़. में मण्डी की डी.पी.आर. रूसा के माध्यम से एक्सैप्ट की गई थी। वर्ष 2016 में इसके लिए 90:10 की रेशो से पैसा आया था। वर्ष 2018 में जो एक्ट बना, उससे पहले टेण्डर प्रोसैस हो चुके थे और बिल्डिंग के काम में गति उसके बाद आई है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इस 90:10 को, क्योंकि ग्रांट जो हमें आई है, वह 49.5 करोड़ की आई है बाकी इसमें 10 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश की ग्रांट है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अन्दर जो डी.पी.आर. में हमने प्रावधान किया था उसमें 4 जिलों को हमने शामिल किया था। उसमें कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर और लाहौल-स्पिति के कॉलेजिज़ शामिल किए थे। 10 कॉलेजिज़ को और इसमें शामिल किया गया था तथा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगले साल और कॉलेजिज़ शामिल करेंगे। तो क्या वही कॉलेजिज़ हैं और डी.पी.आर. के अन्दर प्रावधान किया गया

था कि 100 कॉलेजिज़ एफिलिएट किए जा सकते हैं। 100 कॉलेजिज़ की एफिलिएशन की वज़ह से क्या और भी जिले इसमें शामिल किए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, दूसरे, का 90:10 की ग्रांट इसमें और केन्द्र सरकार से ले रहे हैं, क्योंकि 50 करोड़ से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती है? पिछली सरकार के समय में भी प्रश्न आता था, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि जो रैकरिंग एक्सपैंडिचर इन यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए होगा, वह रैकरिंग एक्सपैंडिचर प्रदेश सरकार के माध्यम से वहन किया जाएगा। क्या अभी तक यही है कि रैकरिंग एक्सपैंडिचर प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जाएगा और दूसरा आपने जो अपने प्रश्न के ज़वाब में, बी-पार्ट के उत्तर में कहा है कि अन्य विषयों के अतिरिक्त इंटर डिसिप्लेनरी विषयों को भी आरम्भ करना

11.03.2020/1110/JK/AG/3

चाहिए, जिसे आप नहीं कर पाए और डी.पी.आर. में प्रावधान किया गया है, क्या आप वह भी करने की बात यहां पर करेंगे? इसमें सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का भी है कि अभी तक आर्डिनैंस नहीं लाए हैं। जब तक आर्डिनैंस नहीं आएगा तब तक आप इसको कैसे शुरू करेंगे? जो एक्ट लाया गया था वह 24 मई, 2018 को लाया गया था। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस एक्ट में सैक्शन-5 के अन्दर प्रावधान किया गया था which provides that the cluster college affiliated to the H.P. University shall stand automatically de-affiliated from the H.P. University from the date of commencement of this Act and such college shall become the cluster college of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, H.P. इसका मतलब आपके एक्ट के हिसाब से वर्ष 2018 को जो 4 कॉलेजिज़ इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अन्दर हैं, वे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से डी-एफिलिएट हो चुके हैं। उन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या होगा, क्योंकि आपने केबिनैट में इस एक्ट का प्रावधान किया था? उनके अभी तक दो सैशन हो चुके हैं, उसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही हैं?

शिक्षा मंत्री, श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

11.03.2020/1115/SS-AG/1

प्रश्न संख्या : 2594 क्रमागत

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दोनों सरकारों में रहे हैं इसलिए इनको मुझसे दुगुनी जानकारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय का गठन 2018 के ऐक्ट के अनुसार हुआ है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में केवल चार कॉलेजिज रखे गए थे। जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज मंडी है, राजकीय महाविद्यालय बासा है, राजकीय महाविद्यालय दरंग ऐट नारला है और महाराणा लक्ष्मण सेन मैमोरियल महाविद्यालय, सुन्दरनगर है। उससे पूर्व क्या चर्चा हुई? शिमला, मंडी या ऊना में यह क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनानी थी या नहीं बनानी थी तो फिर वे सब जगह अलग-अलग यूनिवर्सिटियां बनानी होतीं। लेकिन वह सारी स्कीम 2017 से पूर्व ऐबंडन हो चुकी थी। परन्तु मंडी की जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का पैसा था वह कॉलेजिज़ को दे दिया गया था। इसलिए जब माननीय ठाकुर जय राम जी की अध्यक्षता में सरकार बनी तो आपकी ही उपस्थिति में कैबिनेट ने इस यूनिवर्सिटी का ऐक्ट एप्रूव किया और विधान सभा में उसे पारित किया। उसके अनुसार इन चारों कॉलेजिज़ में काम चला है जोकि मैंने प्रश्न के उत्तर में दिया है। कहीं पर 5 प्रतिशत काम हुआ है, कहीं 30 प्रतिशत हुआ है और कहीं 80 प्रतिशत काम हुआ है। काम निरन्तर चला है और इनको पैसा जो पुराना दिया हुआ था, 5-5 करोड़ तीन कॉलेजिज़ को था और मंडी कॉलेज को ज्यादा पैसा दे रखा था। उसका काम भी ज्यादा तेज़ी से चल रहा है। बाकी पैसा अभी इनको आबंटित होना है। **जैसे-जैसे काम में प्रोग्रैस होगी, पैसा इनको जाता रहेगा।** अभी तक यह क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। इसमें प्रावधान है कि इसको Affiliating University बनाया जा सकता है। वे ऑलरेडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोविजन्ज़ हैं। इस बार के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम इसमें अन्य कॉलेजिज़, जो कुल्लू इत्यादि तीन-चार जिले आपने बताए हैं, जो मंडी के इर्द-गिर्द के महाविद्यालय होंगे उसी में affiliating कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यह सिर्फ बजट की घोषणा है। जब बजट पर चर्चा होगी तो इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे। लेकिन अभी तक यह क्लस्टर यूनिवर्सिटी है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ये सारे काम

पूरे किये जा रहे हैं। इन कॉलेजिज़ को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पार्ट एंड पार्शल के रूप में बनाया जा रहा है। इसमें इस बार हम 6 विषय प्रारम्भ करने वाले हैं। इंटर-डिसीप्लनरी विषय के बारे में भी आपने पूछा है, वह भी उसमें एक प्रोविजन है कि उनको भी प्रारम्भ किया जा सकता है। लेकिन उसमें क्रम और समय निर्धारित नहीं है। जैसे ही हम ये 6 विषय शुरू करेंगे, उसके बाद जैसे-जैसे हमारे पास सुविधा होगी हम इंटर-डिसीप्लनरी विषय भी

11.03.2020/1115/SS-AG/2

इसमें प्रारम्भ करेंगे। मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी एक उदाहरण है क्योंकि इससे पूर्व सैंट्रल यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज़ बनीं लेकिन उनको चलने में अनेकों वर्ष लग गए। **लेकिन यहां एक वर्ष के अंदर-अंदर हमने इतनी प्रोग्रैस कर ली है कि हम आने वाले समय में इसमें बाकायदा यूनिवर्सिटी की क्लासिज़ शुरू कर देंगे। स्टैच्यूट्स कम्प्लीट हो गए हैं, बन करके तैयार हैं, बहुत जल्दी उनको एप्रूव कर दिया जायेगा और वे अस्तित्व में आ जायेंगे।** उसके बाद यूनिवर्सिटी का कार्य सुचारू रूप से चल पड़ेगा।

श्री अनिल शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने सैक्शन-5 के अंदर जो उल्लेख है उसके बारे में माननीय मंत्री जी साइलैंट हैं। इसका मुझे जवाब चाहिए। इस ऐक्ट के अनुसार इसके अब तक दो सत्र चल जाने चाहिए थे, मुझे उसके बारे में बताया जाए।

दूसरा, एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि जो लीड कॉलेज मंडी है और Constituent College तीन हैं, क्या इसमें सरकार ऐसा सोच रही है कि इनको क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बीच में शामिल कर दिया जायेगा? क्योंकि ऐसी जो चर्चा चल रही है

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2020/1120/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2594 जारी---

श्री अनिल शर्मा जारी---

और उसमें यदि हम इसको करेंगें, एक तो डी.पी.आर. से हम डेविएट कर जाएंगे। जो डी.पी.आर. में प्रावधान किए गए हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एक हमारा लीड कॉलेज होगा और तीन हमारे Constituent College होंगे। यदि इसको यूनिवर्सिटी के अंदर ही शामिल करने की कोई बात सरकार के ध्यान में हो तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इसके अंदर कोई भी आगे व्यवधान पैदा हो सकता है क्योंकि डी.पी.आर. से आप डेविएट करेंगे और जो मैंने सेक्शन-5 की बात की है, मंत्री जी इसका जवाब दें कि जो बच्चे डिएफिलिएट कर दिए गए हैं, इस एक्ट के माध्यम से उनका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि उनकी क्लासिज़ अभी तक हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंडर ही चल रही हैं। जो आपने एक्ट में प्रावधान किया, उसमें इन कॉलेजों को डीएफिलिएट कर दिया गया है।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य डिएफिलिएट करने की बात कर रहे हैं, जब तक स्टैच्यूट्स एग्ज़िस्टैंस में नहीं आते और यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग प्रारम्भ नहीं होती, तब तक कॉलेजों की एफिलिएशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही रहेगी। अब वहां पर जब स्टैच्यूट्स बन जाएंगे, डेट फिक्स हो जाएगी कि इस डेट से अब ये यूनिवर्सिटी डिएफिलिएट हो रही है, ये कॉलेज हिमाचल यूनिवर्सिटी से डिएफिलिएट हो जाएंगे और क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसका एग्ज़ाम लेगी। अब हमने कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, रजिस्ट्रार व अन्य पद सृजित कर दिए हैं और बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने बाकी भी पोस्टें तैयार कर दी हैं उसके बाद ये डिएफिलिएट हो कर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ही पूरे चार कॉलेजिज़ का ध्यान रखेगी।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 12 या 13 निजी विश्वविद्यालय हैं। एक एच.पी. यूनिवर्सिटी है, एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक टैक्निकल यूनिवर्सिटी है और एक

11.03.2020/1120/केएस/एएस/2

मैडिकल यूनिवर्सिटी हैं। मण्डी की जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, जिसको कि आप एफिलिएट यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है? सरकार इन यूनिवर्सिटीज़ की बजाय, जो लेटैस्ट कोर्सिज़ आ रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन को मज़बूत करने की ओर ज्यादा ध्यान दें न कि इनको एफिलिएट और डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ ध्यान दें, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से विश्वविद्यालयों का नाम लिया। इन्होंने दो यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दीं। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर और एक होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, सोलन। ये अलग-अलग विषयों की हैं। यह ठीक है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। शायद जब यह यूनिवर्सिटी बनी थी, तब कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी। 1970 में पूरे हिमाचल प्रदेश में 19 या 20 कॉलेज थे जबकि आज यह संख्या संस्कृत कॉलेजों को मिलाकर 139 हो गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। टैक्निकल, एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। सिर्फ एक हिमाचल यूनिवर्सिटी है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ बढ़ें। हमारे जितने संसाधन होंगे उसके अनुसार इन यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है, वह हमने एक प्रोविज़न के अंतर्गत मण्डी में बनाई है जिसमें प्रावधान है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी को एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है। तो इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, इसको एफिलिएटिंग बनाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती हैं परन्तु वर्तमान में सिर्फ मण्डी को ही शिमला के अतिरिक्त एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। ...(व्यवधान)

11.03.2020/1120/केएस/एएस/3

मुख्य मंत्रीः मुकेश जी, अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपके ऊना में हो गई होती, तो ऊना करते। ...(व्यवधान) क्यों का प्रश्न तो नहीं करना चाहिए। आख़िरकार मण्डी भी हिमाचल का ही एक हिस्सा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः मुकेश जी, मंत्री जी ने इसका बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया है।

अगला प्रश्न श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2020/1125/av-as/1

प्रश्न संख्या : 2595

श्री सतपाल सिंह रायजादा : अध्यक्ष महोदय, लाल सिंगी गांव में बन्दोबस्त का कार्य पिछले लगभग 40 वर्षों से चल रहा है। इस बारे में विधान सभा सत्र के अंदर हर बार प्रश्न उठता आया है। पहले भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र से रहे विधायक ने इस प्रश्न को विधान सभा के अंदर बार-बार उठाया है। लेकिन जब-जब इस बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण होने वाला होता है उस वक्त पटवारी या कानूनगो को बदल दिया जाता है और वहां पर जो नये पटवारी तथा कानूनगो आते हैं वे उस काम को दोबारा से शुरू करते हैं। इस काम को शुरू हुए लगभग 40 साल का समय हो गया है और यह मेरा अपना गांव है। अब तो मेरे गांव के लोग ही मुझे यह कहने लग गये हैं कि अगर आप अपने गांव का बन्दोबस्त भी करवा लेंगे तो वह एक बड़ी बात होगी। जब से जिला ऊना और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं तब से लेकर इसका बन्दोबस्त नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं इस विधान सभा के अंदर विधायक बनकर आया था तो मैंने उस वक्त भी यह प्रश्न किया था और मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि इस कार्य को 6 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा। वहां पर 2-3 पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार नियुक्त हो गये तथा काम स्पीड से शुरू कर दिया मगर अब वहां पर कानूनगो नहीं है। पहले वहां 2 पटवारी थे परंतु अब 1 ही पटवारी रह

गया है जिसके कारण काम की स्पीड दोबारा से कम हो गई है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो मार्च, 2021 तक इस कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है क्या यह डैड लाइन है कि इस समयावधि के अंदर यह काम समाप्त हो जायेगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि जिला ऊना में बन्दोबस्त का कार्य चला हुआ है। वहां पर वर्तमान में 847 महालों का बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा मात्र 19 महालों में बन्दोबस्त का कार्य चला हुआ है। माननीय विधायक जहां तक लाल सिंगी गांव की बात कर रहे हैं तो उस बारे में मेरा केवल इतना कहना है कि यह गांव पहले पंजाब के होशियारपुर जिला में

11.03.2020/1125/av-as/2

होता था और वर्ष 1996 में हमारे पास आया है। यह गांव जब हिमाचल प्रदेश में आया तो उस समय यहां के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहुत खराब थी और उसको पढ़ना बहुत कठिन था। माननीय विधायक ने सही कहा है कि यह कार्य बहुत वर्षों से चला हुआ है और लाल सिंगी का बन्दोबस्त का कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। लेकिन अब यह अंतिम रूप से सुनिश्चित कर लिया गया है कि यह कार्य 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। आपने जहां तक पटवारियों और कानूनगो का ज़िक्र किया है तो स्थानांतरण रूटीन में होते ही रहते हैं। किसी के आने या जाने से काम रुकता नहीं है, हां; थोड़ी देर के लिए प्रभावित जरूर होता है क्योंकि जो नया आदमी आता है उसे काम को समझने और आगे बढ़ाने में कठिनाई जरूर होती है। **मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह कार्य 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा**। आपने जहां तक कानूनगो की बात कही है तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ऐसा भी नहीं है कि वहां बहुत कम है।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2020/1130/TCV/DC-1

प्रश्न संख्याः 2595 .. क्रमागत्

मुख्य मंत्री .... जारी

वर्तमान में इन महालों के बन्दोबस्त के कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु निम्न कर्मचारी वहां पर हैंः- नायब तहसीलदार-1, कानूनगो-5, पटवारी-24, चैनमेन-10 और चपड़ासी-1 हैं। इस कार्य को करने में विलम्ब अवश्य हुआ है **लेकिन हम इस कार्य को शीघ्र पूरा करेंगे। इसका राजस्व रिकॉर्ड बहुत खराब स्थिति में था, उसको ठीक करते-करते समय लग गया और अब उसको ठीक कर लिया गया है। मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि लालसिंगी गांव का बन्दोबस्त शीघ्र ही कर दिया जाएगा।**

अध्यक्षः वैसे तो माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य, आप कुछ और पूछना चाहते हैं?

श्री सतपाल सिंह रायजादा : मैं मुख्य मंत्री जी से इतना कहना चाहूंगा, यह आपकी सरकार की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यह शहर से सट्टा हुआ गांव है। यदि किसी ने मकान बनाना है तो टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि इस बन्दोबस्त का कार्य जब पूर्ण होने वाला होता है तो वहां से पटवारी या कानूनगो को बदल दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह कार्य पूर्ण न हो जाये तब तक वहां से पटवारी और कानूनगो को न बदला जाए। ऐसा न हो कि जिस तरह से पिछले 40 सालों से यह काम चला आ रहा है, आगे भी इसी तरह से चलता रहे तो यह ठीक नहीं रहेगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। **माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, हम इनको ध्यान में रखेंगे और यह**

सुनिश्चित करेंगे कि आपका यह काम प्रभावित न हों और आपका बन्दोबस्त समय पर पूर्ण हो जाए।

प्रश्न समाप्त

11.03.2020/1130/TCV/DC-2

प्रश्न संख्याः 2596

श्री विनोद कुमार (नाचन) : अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री, आदरणीय जय राम ठाकुर जी का और माननीय परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बस अड्डा गोहर के लिए 79.00 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके साथ ही बस अड्डा चैल चौक के निर्माण हेतु 55.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो लैंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चली है, वह कहां तक पहुंची है?

अध्यक्ष : माननीय परिवहन मंत्री जी कृपया उत्तर दें।

वन **मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गोहर बस अड्डे के निर्माण हेतु 79.00 लाख रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इस बस अड्डे के निर्माण के लिए महाल हरहली-66, खसरा नम्बर- 633/1 और कुल 5-8-14 बिघा वन भूमि का चयन किया गया है। इसका एफ.आर.ए. का केस एस.डी.एम., गोहर के द्वारा जिलाधीश मण्डी को भेजा गया है। अभी तक वहां से एफ.आर.ए. का सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही यह लैंड परिवहन विभाग के नाम हो जाएगी तो इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया जाएगा। दूसरा, जो चैल चौक है

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

11.03.2020/1135/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 2596... जारी

वन मंत्री.... जारी

वित्त वर्ष 2019-20 में चैल चौक के लिए 55 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। खसरा नं0 157/1 में लगभग 8 बीघा भूमि चयन की गई है। इसका एफ.सी.ए. केस Chief Conservator of Forest के ऑफिस भेजा जा चुका है। जब यह भूमि हस्तांतरण का मामला सैटल हो जाएगा तो यह काम प्रारम्भ कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें छोटा-सा इशू यह है कि गोहर और चैल चौक के बीच 4 किलोमीटर एरिया वन भूमि में पड़ता है जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है लेकिन उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि गोहर और चैल चौक की कुल दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर है। विभाग द्वारा जो आपको सूचना दी गई है, वह गलत है। एफ.सी.ए. और एफ.आर.ए. की क्लीयरैंस के लिए दो वर्ष हो गए हैं परंतु यह मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाए ताकि विभाग द्वारा जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसे बस-स्टैंड के निर्माण कार्य हेतु प्रयोग किया जा सके।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमने 'लगभग' कहा है, यह सटीक सूचना नहीं है। मेरा कहना है कि माननीय विधायक अपने स्तर पर जिलाधीश कार्यालय से इन चीजों को तेज गति से चलाएं और भूमि हस्तांतरण का मामला जल्द हल हो ताकि यह काम शीघ्र शुरू करवाया जा सके।

11.03.2020/1135/RKS/DC-2

<u>प्रश्न संख्याः 2597</u>

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर)ः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है क्या सरकार द्वारा इनके duty hours फिक्स किए गए हैं या प्रदाता के साथ कोई ऐसा एग्रीमैंट हुआ है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को इतने घंटे अपनी सेवाएं देनी हैं? जो प्रदाता ने पार्ट-टाइम आउटसोर्स कर्मचारी रखे हैं उनसे कितने समय तक काम लिया जा रहा है? दूसरा, जो आज के परिवेश में महंगाई और पारिवारिक जिम्मेवारियों को देखते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन, भत्ते दिए जा रहे हैं, क्या वे वेतन, भत्ते पर्याप्त हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सीधेतौर पर यह कहना चाहूंगा कि आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। ये कंपनी के माध्यम से अंगेज किए जाते हैं और कंपनी के कर्मचारी हैं। दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारी रेग्यूलर कर्मचारियों के लिए बने हुए आर.एंड पी. रूल्ज को फॉलो नहीं करते। चाहे ये कर्मचारी पार्ट-टाइम में लगे हों या फुल टाइम में, उन्हें मिनिमम वेजिज के आधार पर वेतन दिया जाता है। जहां तक आपने स्पेसिफिक जानकारी चाही है उसके अनुसार जो पार्ट-टाइम कर्मचारी हैं उन्हें निर्धारित घंटों के मुताबिक काम करना होता है

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

11.03.2020/1140/बी.एस./एच.के./-1

प्रश्न संख्याः 2597 क्रमांगत...

मुख्य मंत्री जारी...

और जो पूरे समय के लिए लगे होते हैं उन्हें उतने धण्टे काम करना पड़ता है। उनके लिए नियमानुसार वैसे ही वेतन की व्यवस्था भी की गई होती है। इसके अतिरिक्त मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि समय-समय पर हमने जब दैनिक वेतन बढ़ाया है तो इनके वेजिज भी बढ़ाए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के दो वर्ष के कार्यकल में ही इसे दो बार नहीं अपितु तीन बार इनक्रीज किया गया है। हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन लोगों का शोषण न हो। मैं देख रहा हूं माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी प्रश्न पूछने वाले हैं। इनका मूल प्रश्न यही होता है और इनकी बात भी सही है।

जल शक्ति मंत्री : इनकी राजनीति ही इसी से चलती है।

मुख्य मंत्री : यह बात सही है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। इस बात को ले करके हमने सुनिश्चित किया है और हमने 13.08.2019 को नोटिफिकेशन भी की है। उसमें यह कहा गया है कि हर महीने की पे स्लिप भी देनी पड़ेगी ताकि इन लोगों का शोषण न हो। उससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। माननीय सदस्य ने मोटे तौर पर जो प्रश्न पूछे थे, मुझे लगता है कि मैंने उनके उत्तर दे दिए हैं और अन्य इसके अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो अवश्य प्रश्न करें।

श्री राकेश सिंघा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बिल्कुल सहमत हूं। जो आउट सोर्स कर्मी हैं they will be governed by the minimum wage rules. मैं इनसे सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि इसमें कुछ जिक्र जरूर किया है। नम्बर एक अप्वायंटमैंट लेटर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाए? नम्बर दो wage slip का जिक्र उसमें जरूर किया गया है। जो भी मिनिमम वेज के तहत govern होगा उसके सारे मिनिमम वेज के रूल्ज लागू होंगे। To the extent पांच साल बाद उसको ग्रेच्युटी देनी है। लोक निर्माण विभाग का जो हमारा मजदूर है जो आउट सोर्स हैं उसे भी ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आउट सोर्स का तो 100 प्रतिशत शोषण हो रहा है।

11.03.2020/1140/बी.एस./एच.के./-2

मैं अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहूंगा कि चम्बा में जो मजदूर है। जो बिजली बोर्ड ने डिप्लाए किए they have been removed. उनकी redeployment तब की जा रही है जब वे 5-5 हजार रुपया जमा कर रहे हैं। This is the reality. हमें जब इसे चैक करेंगे तो इससे सरकार की साख बढ़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो सरकार की साख गिरेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य आदरणीय राकेश सिंघा जी बहुत टैक्निकली आदमी हैं। आप हम से अप्वायंटमैंट लैटर के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने पहले ही बात को स्पष्ट कर दिया है कि आउट सोर्स में जितने भी लोग लगे हैं ये सीधे तौर पर सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ये कंपनी के कर्मचारी हैं। इसलिए सरकार की ओर से इन्हें अप्वायंटमैंट लैटर देने की गुंजाइश नहीं है। उन्हें अप्वायंटमैंट लैटर कंपनी देती है। परंतु आप चाह रहे होंगे की उन्हें सरकार की ओर यह लैटर मिले और वह कानूनी आधार उन लोगों के लिए बन जाए तो यह संभव नहीं है। यह बात सही है कि आप उनके हित की बात कर रहे हैं। आपकी सोच अच्छी है लेकिन सोचने के बाद जो करने में कठिनाई है उसे आप भी भली-भांति समझते हैं। यह सब बातें आपके ध्यान में हैं। उसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक आपने शोषण की बात की है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

11.03.2020/1145/DT/HK-1

प्रश्न संख्याः 2597 क्रमांगत...

मुख्य मन्त्री जारी

हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि शोषण न हो। कही भी इस प्रकार की शिकायत अगर हमकों आती है तो उसमें कार्रवाई के अनेक प्रावधान हमनें बनायें हैं। जहां तक इनकी मदद करने की बात है, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इनको अकास्मिक अवकाश दिया जाता है, आरम्भ में यह प्रोविजन नहीं थे लेकिन अब अकास्मिक अवकाश का प्रावधान इसमें हैं उसके साथ ही महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान भी उसमें किया गया। जो शोषण की सम्भावनाऐं होती थी उसमें भी निश्चित रूप से अब कमी आई है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहें हैं कि अगर मिनीमम वेजिस के उल्लंघन की जानकारी कही से हमें मिलती है तो उस पर हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे और हमने कार्रवाई की भी है और आने वाले समय में भी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार में ही लगभग 2000/- रूपये प्रतिमाह की दिहाड़ी में बढ़ौतरी हुई है। यह भी एक साईजेबल इनक्रीज है जो हमारी सरकार के दो साल के कार्यकाल में हुआ है। जहां तक ग्रेज्यूटी का सम्बन्ध है, इसको हम एग्जामिन करेंगे की उसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से अभी नहीं बोला जा सकता क्योंकि न यह उचित है और न ही यह व्यवहारिक ही है, जब तक इसका अध्यनन न किया जाये। इसके क्या इम्पैक्टस रहेंगे? क्या व्यवहारिक रूप से यह सम्भव हो पायेगा? जहां तक उन्हें सुविधाऐं उपलब्ध करवाने का सवाल है, इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। आउट सोर्स का प्रचलन आपकी कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। आज केन्द्र सरकार भी लार्ज-सकेल में आउट सोर्स के द्वारा काम कर रही है। बहुत सी प्रदेश सरकार भी आउट सोर्स के माध्यम से ही काम चला रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दो साल के कार्यकाल में, अगर हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की बात करें, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने साईजेबल नम्बरज़ में नौकरियां दी हैं और यह आज तक का शायद हाइएस्ट नम्बर होगा।

11.03.2020/1145/DT/HK-2

मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान सरकार द्वारा 17,707 सरकारी नौकरियों दी गई हैं जिसमें में विभाग में 15,945 और बार्ड और निगमों 1762 नौकरियां दी गई हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष के लिए जो सरकार द्वारा सरकारी पद भरने के लिए अनुमति दी गई है 15315 पदों के लिए दी गई है जिनमें से 4000 पद बोर्ड और निगमों के लिए है। 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरकारी कर रही हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो लोग आउट सोर्स में लगें हैं उनके पास बहुत सारी ऑपोरचुनिटीज़ इस प्रकार से भी रहती है कि विभागों में भर्ती के लिए निकाले गये नियमित पदों को आउट-सोर्स में लगे लोग प्रतियोगिता परिक्षा को पास कर सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकतें है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पहले आउट-सोर्स में थे और प्रतियोगिता पास कर अब सरकारी नौकरी में लगें हैं। अपने करियर के बारे में वह स्वयं भी चिन्तित है और हम भी उनके लिए चिन्तित हैं। प्रतियोगिता की ऑपोरचुनिटी हमेशा उनके लिए रहेगी। आज कल प्रतियोगिता का जमाना है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पोस्ट क्रीऐट कर सकती हैं लेकिन क्वालीफाई तो उन्हीं को करना है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

11-03-2020/1150/वाई.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या 2597 जारी.....

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल(बड़सर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है लेकिन मेरा यह कहना है कि इन्होंने जिम्मेवारी से उत्तर नहीं दिया, सरकार उनकी जिम्मेवारी ले। जो आऊटसोर्स कर्मचारी हैं वे कौन-सी सरकार में, कब लगे, किसमें लगे यह चर्चा का विषय नहीं है। जब देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब से यह प्रथा शुरू हुई है और उसके बाद यह लगातार चला हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि 3,500 रुपये में एक आऊटसोर्स कर्मचारी 12 से 15

घण्टे काम कर रहा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी सुरक्षा कौन देखेगा? ...(व्यवधान) आपने 2 साल में यदि 10-15 हज़ार नौकरियां दे भी दी तो नौजवानों पर कोई एहसान नहीं किया।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपका प्रश्न आ गया है कृपया बैठ जाएं।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए कि आऊटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य के बारे में क्या-क्या करेंगे। आज के समय में कोई 3,500 रुपये में अपने घर का खर्चा चला कर दिखाए और अपने बूढ़े मां-बाप की सेवा करके दिखाए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपका प्रश्न आ गया है, कृपया बैठ जाएं।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो आऊटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी देख-रेख कौन कर रहा है और सरकार की कौन-सी संस्था है जो कम्पनी पर चैक रख रही है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनकी चिंता वाज़िब है।...(व्यवधान) मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के बजट में हमने कहा था कि आऊटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा और हमने इस बात को सुनिश्चित भी किया है। उन्हें सैलरी हर माह मिलेगी और उनको पे-स्लिप देनी पड़ेगी, पैसा सीधा उनके खाते में जाएगा, इसे सुनिश्चित

11-03-2020/1150/वाई.के.-एन.जी./2

किया गया है। हमने हमेशा कहा है कि जहां भी शोषण की बात आएगी हम उसके ख़िलाफ खड़े होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इन्हें यह सारा विषय अभी याद आ रहा है।...(व्यवधान) जब आपका कार्यकाल था और आपने उस समय कुछ नहीं किया और अंतिम दिनों में...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, आप बैठ जाएं और सुनें।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि शोषण की कोई गुंजाइश न हो और मिनिमम वेज़स के हिसाब से हमने जो व्यवस्था की है उसे हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, शोषण तो तब हुआ था...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, आप बैठ जाएं।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शोषण तो तब हुआ था जब इनकी विदाई की शहनाई बज रही थी और पीटर हॉफ में सबको एकत्रित किया...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, कृपया आप बैठ जाएं।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शोषण तो तब हो रहा था जब हमारे मित्रों की सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला था और विदाई की शहनाई बज रही थी, 'बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले'।...(व्यवधान) आपने सबको पीटर हॉफ में एकत्रित किया और बोला कि राजा साहब ने बुलाया है, यह सब उनके खास आदमियों ने ही आयोजित किया था, वहां पर सबसे नारे लगवाए 'सातवीं बार, राजा साहब'। सभी ने नारे तो लगाए लेकिन उसके बाद आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया।...(व्यवधान) शोषण इसे कहते हैं जो आप लोगों ने किया। हम आपको कह रहे हैं कि हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हम कह रहे हैं कि एक आऊटसोर्स कर्मचारी के नाते उनके लिए जो भी व्यवस्था बनती है वह हम उन्हें दे रहे हैं।...(व्यवधान)

11-03-2020/1150/वाई.के.-एन.जी./3

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज भी जो बात हो रही है यह शोषण से सम्बन्धित ही है।...(व्यवधान) शोषण आप लोगों ने किया है और यह आपकी पुरानी आदत है।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य बैठ जाएं। अगला प्रश्न...(व्यवधान) मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं।...(व्यवधान) माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं।...(व्यवधान)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

11/03/2020/1155/MS/YK/1

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री आशीष बुटेल जी। ...(व्यवधान)मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं। माननीय सदस्य बैठिए।
प्रश्न संख्याः 2598- श्री आशीष बुटेल ऑथोराइज्ड टू श्री विनय कुमार **अनुपस्थित**

11/03/2020/1155/MS/YK/2

प्रश्न संख्याः 2599 - श्री मोहन लाल ब्राक्टा **अनुपस्थित**
...(व्यवधान)
(कांग्रेस विधायक दल के सभी माननीय सदस्यगण नारेबाजी करने लगे)
(कांग्रेस विधायक दल के सभी माननीय सदस्यगणों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनकी अन्दर आकर बाहर जाने की आदत बन गई है। जो हम जवाब दे रहे हैं, वह तथ्यों पर आधारित जवाब दे रहे हैं। हमने स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार के बाद हिमाचल प्रदेश में किसी भी वर्ग के लिए कहीं भी शोषण की गुंजाइश नहीं

है। लेकिन इनकी और तरह की परेशानी है। इन्होंने पहले इस बात को लेकर आउटसोर्स वालों को सुनिश्चित करवाया, फिर उनको घुमाते रहे और जब चुनाव के अंतिम दिन आए तो इन्होंने पीटरहॉफ के मैदान में उन सबको खड़ा कर दिया। वहां पर उस समय के प्रदेश के मुख्य मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाया गया और वहां पर कहा गया कि ऐसे नारे लगाओ कि सातवीं बार फिर राजा साहब। अगर आउटसोर्स के मामले में सही मायने में इनके मन में कोई भाव होता तो ये समाधान करते लेकिन इन्होंने कोई समाधान नहीं किया और केवल राजनैतिक मकसद से उनको कहा कि हम आपके लिए यह करेंगे, वह करेंगे। इनकी प्रदेश से विदाई हो गई लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने सरकार में आते ही इस बात को सुनिश्चित किया कि यह वर्ग सेवाओं में बहुत बड़ा योगदान देता है यानी जो सरकारी कर्मचारी स्थाई रूप से नौकरी में लगा है, ये उसके बराबर का काम करते हैं। इस परिस्थिति में हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनका शोषण किसी भी तरह से कहीं भी न हो। इसके लिए जो कदम उठाने थे, वे कदम हमने उठाए हैं। विपक्ष की परेशानी यह है कि इन्होंने बाहर जाना ही था और मुझे इस बारे में सूचना मिल गई थी। इनके बाहर जाने की वजह यह है कि ये होली खेलकर आए हैं और मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, उसके कारण भी इनको परेशानी है। इनकी पार्टी के एक नेता खुद ही बोल रहे हैं कि मैं इस दल में रहते हुए देश और समाज की सेवा करने में असमर्थ हूं क्योंकि इस दल में इस तरह के कोई भी भाव नहीं रह गए, जहां देश या समाज की सेवा की गुंजाइश हो। अंततः उन्होंने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा कि मैं आपके दल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। इनकी परेशानी यह है। मुझे ये आते ही परेशान लग रहे थे और यहां आते हुए भी ये कुछ-कुछ धीमें-धीमें आपस में बोल रहे थे। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं

11/03/2020/1155/MS/YK/3

यह कहना चाहता हूं कि वहां की परिस्थिति वहां की है और यहां की परिस्थिति के मुताबिक ये यहां पर बात करें। जो प्रश्न पूछे गए, उनका हमने एक-एक का जवाब दिया है और जो वाजिब और सही जवाब है, वही हमने दिया है। ये अगर वहां खड़े होकर कहें कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा और आपको ऐसा बोलना पड़ेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात जिसे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं वह यह है कि चेयर के प्रति इनका व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बात कीजिए, निवेदन कीजिए और आपको जहां अपनी

बात कहने का मौक़ा मिलता है, आप बोलिए। ...(व्यवधान) विपक्ष ने अपनी छवि एक झगड़ु विपक्ष की बना दी है। ...(व्यवधान) तो आप आराम से भी बोल सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा इतना ही निवेदन है कि ये थोड़ा संयम और सब्र रखें, वह इनके काम आएगा। जो मध्य प्रदेश में होना था, वह हो गया। ...(व्यवधान) अब आपको छोड़कर लोग जा रहे हैं और खुलेआम छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनकी परेशानी वाजिब है। मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन इसका समाधान इस प्रकार से नहीं होगा।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी माननीय सदस्यगण सदन के अन्दर आए)

अगला प्रश्न जे0के0 द्वारा----

11.03.2020/1200/JK/AG/1

प्रश्न संख्याः 2600

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे रूल्ज़ के मुताबिक पहले अप्वाइंटमैंट होती है या बच्चों की एडमिशन होगी? दूसरे, वहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की अप्वाइंटमैंट की है या नहीं की है?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब किसी जगह को साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम दी जाती है तो साथ में पोस्ट सेंक्शन होती है लेकिन जब किसी स्कूल को फंक्शनल किया जाता है तो एनरोल्मैंट के हिसाब से वहां पर पर टीचर्ज़ भेजे जाते हैं। वहां पर जितने भी स्ट्रीम्ज़ अभी चल रहे हैं, उन सबके लैक्चरर्ज़ वहां पर अप्वाइंटिड हैं, इसमें भी अगर एनरोल्मैंट हो जाएगी, क्योंकि वर्ष 2019 में होनी थी लेकिन कोई एनरोल्मैंट नहीं हुई है इसलिए वहां पर कोई साइंस स्ट्रीम का टीचर नहीं लगा। इस बार यदि एनरोल्मैंट हो जाएगी तो वहां पर टीचर्ज़ भेजेंगे, चाहे कहीं से भी भेजेंगे क्योंकि नई अप्वाइंटमैंट्स भी हो रही हैं, उससे भी भेज देंगे। अगर ट्रांसफर करके भेजना होगा तो उस तरह से भी भेज देंगे लेकिन यदि वहां पर विद्यार्थी ही न हों तो लाखों रुपया बिना विद्यार्थी के टीचर की अप्वाइंटमैंट करने पर वेस्ट नहीं किया जा सकता ।

प्रश्नकाल समाप्त।

11.03.2020/1200/JK/AG/2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री बुधवार, 11 मार्च, 2020 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जोकि इस प्रकार हैः-

बुधवार, 11 मार्च, 2020 1. शासकीय/विधायी कार्य
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021-सामान्य चर्चा।

वीरवार, 12 मार्च, 2020 1. शासकीय/विधायी कार्य
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021-सामान्य चर्चा।

शुक्रवार, 13 मार्च, 2020 1. शासकीय/विधायी कार्य
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021-सामान्य चर्चा।

शनिवार, 14 मार्च, 2020 1. शासकीय/विधायी कार्य
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021-सामान्य चर्चा का समापन।

11.03.2020/1200/JK/AG/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, पर्यवेक्षक (स्टाफ कार), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याःपर0(ए0आर0)बी(15)-1/2018 19.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2019 को प्रकाशित; और

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वर्ग-III व वर्ग-IV के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता, नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी)-सी-सी(17)-2/2018 दिनांक 19.11.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.11.2019 को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब माननीय जल शक्ति मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

जल शक्ति मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रक्रिया अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याःआई0पी0एच0-ए-ए(3)-7/2017 दिनांक 27.09.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.10.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

11.03.2020/1200/JK/AG/4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

अध्यक्षः अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 8वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल प रखता हूं :-

11/03/2020/1155/MS/YK/5

समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 7वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित

i. सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 9वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है।

11.03.2020/1200/JK/AG/6

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन एवं इंडस विश्वविद्यालय बाथू जिला ऊना के द्वारा फर्जी डिग्रियां बनाने के सन्दर्भ में इस माननीय सदन में स्टेटमैंट देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोगों के लिए यह चिन्ता का विषय है और चर्चा का भी विषय बना है कि हिमाचल प्रदेश में, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

11.03.2020/1205/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

यहां पिछले काफी अरसे से फर्जी डिग्रियां प्राइवेट यूनिवर्सियां बेच रही हैं और दे रही हैं। हमने जैसे ही सारे विषय का अध्ययन किया तो तुरन्त इसमें सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमने कहा कि पीछे जो होता रहा होगा, वह होता रहा होगा लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर यह विषय ध्यान में आया है तो इसमें जितनी भी सख्त कार्रवाई करने की गुंजाइश बनती है वह कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में हमने जो कार्रवाई की है और हमारे तक जो जानकारी पहुंची है उसके बारे में एक स्टेटमैंट देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन एवं ईन्डस विश्वविद्यालय बाथू, जिला ऊना के द्वारा फर्जी डिग्रियां बनाने के सन्दर्भ में मैं इस माननीय सदन को संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। फर्जी डिग्रियों के मामलों से संबंधित जिला सोलन में तीन अभियोग एवं जिला ऊना में एक अभियोग दर्ज किया गया है। अभियोग संख्या 22/20 दिनांक 03.03.2020 जेरधारा 420, 467, 468, 471, 120बी आई0पी0सी0 थाना धर्मपुर, जिला सोलन में श्रीमती ममला निवासी चरखी दादरी की रिपोर्ट पर पंजीकृत किया गया। जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने इसे मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर विषय में दाखिला लेने के बावजूद फर्जी डिग्री प्रदान की।

मानव भारती विश्वविद्यालय सुल्तानपुर के प्रशासनिक ब्लॉक में दिनांक 06.03.2020 को रेड की गई तथा कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क, लैपटॉप, पैन ड्राईव, मोहरे व अन्य दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया गया। तलाशी के दौरान मानव भारतीय विश्वविद्यालय के ई0 ब्लॉक के गोदाम से रद्दी के नीचे दबी हुई वर्ष 2009 से 2015 तक कुल 305 डिटेल मार्क कार्ड, जिनमें कुछ हस्ताक्षरित हैं तथा 15 डिग्रियां भी बरामद हुई हैं जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है।

मानव भारती विश्वविद्यालय से जो दस्तावेज़ पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए हैं उनके आधार पर अभियोग संख्या 26/2020 दिनांक 07.03.2020 अधीन धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आई0पी0सी0 थाना धर्मपुर में पंजीकृत किया गया है।

11.03.2020/1205/SS-AG/2

गुप्तचर विभाग, शिमला द्वारा थाना धर्मपुर में भेजे गये 103 जाली डिग्रियों की शिकायत पर अभियोग संख्या 27/2020 दिनांक 08.03.2020 अधीन धारा 420, 462, 468, 120बी आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया है।

मानव भारती विश्वविद्यालय के मामलों में सहायक पंजीयक, मनीश गोयल को दिनांक 08.03.2020 को गिरफ्तार किया गया है जोकि तीन दिन की पुलिस हिरासत में है।

मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा के द्वारा राजस्थान के अबू रोड माउंटआबू में खोले गए माधव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की भी हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा तलाशी ली गई। जहां से तलाशी के दौरान 1376 खाली डिग्रियां, 14 मोहरें, 4 डिस्पैच रजिस्टर, 50 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 199 खाली एनवेलपर, 485 खाली पत्र हेडज, 319 खाली डिटेल मार्क्स कार्ड, 2 कम्प्यूटर, 6 भरी गई डिग्रियां एवं अन्य दस्तावेज मिले, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है तथा माधव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को सील कर दिया गया है। दौराने तलाशी जो भी दस्तावेज़ एम0बी0यू0 से बरामद हुए हैं

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2020/1210/केएस/एएस/1

मुख्य मंत्री जारी---

उनसे ज़ाहिर होता है कि इस यूनिवर्सिटी में काफी समय से जाली डिग्रियां जारी करके विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। दिनांक 9 मार्च, 2020 को श्री आशुतोष निवासी बढ़ाला, जिला ऊना की शिकायत पर अभियोग संख्या 27/2020 धारा 420, 468,471, 120-बी आई.पी.सी. थाना हरोली में पंजीकृत किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इंडस विश्वविद्यालय बाथुर ने तीन लड़कियों को अपने विश्वविद्यालय में नौकरी दे कर नौकरी में हाज़री लगाकर भी उन्हें नियमित छात्राओं के रूप में दाख़िल दिखाकर डिग्री प्रदान की गई तथा उन डिग्रियों के आधार पर की गई नौकरी का अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया।

उपरोक्त चारों अभियोग का अन्वेषण हर पहलू को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ए.पी.जी. विश्वविद्यालय, शिमला के संदर्भ में मिली शिकायत की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा गठित विशेष अन्वेषण टीम द्वारा अमल में लाई जा रही है तथा ठोस सबूत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, यह एक या दो साल का विषय नहीं है, यह हमको स्पष्ट होना पड़ेगा क्योंकि जब से ये यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टैंस में आई हैं, ऐसा लग रहा है, अभी और फैक्ट्स निकलेंगे और जो जानकारियां मिलेंगी, उनको हम आपके साथ सांझा करेंगे लेकिन काफी अरसे से यह काम चल रहा था और वर्ष 2017 में एक शिकायत आई थी, उसमें मामला सी.आई.डी. के लिए रैफर हुआ था लेकिन उस सारे मामले में भी प्रगति नहीं हो पाई। अब इस सारे मामले को हमने बहुत गम्भीरता से लिया है और तय किया कि इसको निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्ज़ हैं, खासकर जितने भी प्राइवेट कॉलेज और युनिवर्सिटीज़ हैं, उनके संदर्भ में अगर ऐसी कहीं से भी शिकायत आएगी, उसमें पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद उसमें मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। इस प्रदेश में ऐसी चीजों के लिए आने वाले समय में कोई गुंजाइश नहीं होनी

11.03.2020/1210/केएस/एएस/2

चाहिए। यह प्रदेश देव भूमि के नाम से जाना जाता है, इसकी छवि को किसी प्रकार से नुक्सान न हो, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवसाय कतई भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को देना चाह रहा था। धन्यवाद।

11.03.2020/1210/केएस/एएस/3

वन मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः पिछले कल चम्बा में एक बस दुर्घटना हुई है। इस बस दुर्घटना के बारे में मंत्री जी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पिछले कल चम्बा में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जो कि बहुत ही दुखद व दर्दनाक है और उस सम्बन्ध में आपने मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी, आपका धन्यवाद।

महोदय, दिनांक 09.03.2020 को बस संख्या एच.पी. 73-4621 चालक श्री नरेश कुमार चतुर्थ अनुबन्ध व परिचालक श्री सुनील कुमार चतुर्थ अनुबन्ध पर कार्यरत थे, ने चण्डीगढ़ से वाया बद्दी-नालागढ़-ऊना-पठानकोट-बनीखेत सांय के लिए 06:30 बजे चम्बा के लिए प्रस्थान किया व जिसकी बुकिंग बस अड्डा चण्डीगढ़ काउंटर पर श्री लोकेश कुमार खेपन लिपिक द्वारा की गई। बुकिंग में कुल 26 यात्रियों की बुकिंग हुई जिसमें से 22 यात्री चम्बा के, 1 यात्री तलवाड़ा का, 1 यात्री बनीखेत का व 1 यात्री राजा का तालाब का था। इसके अतिरिक्त इस बस की ऑनलाइन बुकिंग भी हुई थी जिसमें 8 यात्री चम्बा के 6 यात्री तलवाड़ा के 2 यात्री बनीखेत के व 1 यात्री रेहन का था।

यह बस दिनांक 10.03.2020 को प्रातः 6:45 बजे के लगभग चेहली नामक स्थान से लगभग 1 किलोमीटर चम्बा की तरफ आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जो कि चम्बा से लगभग 20 कि0मी0 है। बस की दुर्घटना की जानकारी मिलते ही श्री शुगल सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक पठानकोट को पहले ही मौके के लिए रवाना कर दिया गया और श्री अनूप राणा मण्डलीय प्रबन्धक, श्री राज कुमार जरयाल, उप-मण्डलीय प्रबन्धक, जसूर व श्री कुलवंत सिंह फीटर, मौके के लिए रवाना हो गए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2020/1215/av-as/1

वन मंत्री--------- जारी

इस बस में कुल 42 यात्री यात्रा कर रहे थे जिसमें से 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी व 1 यात्री ने चम्बा अस्पताल में आकर दम तोड़ दिया बाकी 34 यात्रियों का चम्बा

मैडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था व इनमें से 3 यात्रियों को मैडिकल कॉलेज चम्बा से मैडिकल कॉलेज टाण्डा के लिए रैफर कर दिया गया है। (मृतक व घायल यात्रियों की सूची संलग्न है।)

बस संख्या एच0पी073-4621 जो कि नवम्बर, 2014 मॉडल की है व इसमें 47 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। इस बस के द्वारा दिनांक 8.3.2020 तक 697484 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और दिनांक 6.3.2020 को इस बस के कर्मशाला यानी शाखा में निम्नलिखित डिफैक्ट दर्ज़ करवाये गये थे :-

1. आगे तथा पीछे एक टायर की रबड़ निकल गई है।
2. गाड़ी की खिंचाई कम है।
3. फॉग लाइट का स्विच डाला।
4. चारों कमानियों के बुश डालें।
5. ब्रेक बहुत कम लगती है।
6. गाड़ी धक्का स्टार्ट है।

उपरोक्त त्रुटियों को लाँग रूट की टीम श्री सुरेश कुमार मैकेनिक, श्री सौरम सिंह जे0टी0, श्री सुरेश कुमार जे0टी0 व श्री रवीन्द्र कुमार पीस मील द्वारा श्री दलीप सिंह यांत्रिक की देख-रेख में दूर करवाया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 8.3.2020 को भी इस बस के अगले परिचालक की तरफ ब्रेक लाइनिंग डाले गये थे व रूटीन चैकिंग की गई थी। प्रथम दृष्टि से दुर्घटना का निरीक्षण करने पर पाया गया है कि चालक की तेज रफ्तारी व लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हुई है। इस बारे में मैजिस्ट्रेटीयल जांच करवाने के आदेश ज़ारी कर दिए हैं तथा इससे संबंधित अन्य कागज़ात मैं सभा पटल पर रखता हूं।

समाप्त

11.03.2020/1215/av-as/2

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमानों वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा

अध्यक्ष : आज से वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ हो रही है तथा इसका समापन दिनांक 14 मार्च, 2020 को माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर के साथ होगा। समय की उपलब्धता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष को 45 मिनट तथा अन्य सदस्यों को अधिकतम 15 मिनट का समय सुनिश्चित किया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वे अपना-अपना भाषण बजट तक ही सीमित रखकर निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करें।

सर्वप्रथम मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को चर्चा आरम्भ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 6 मार्च, 2020 को जो यहां पर बजट अनुमान प्रस्तुत किए, उस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मेरा विशेष तौर से यह आग्रह रहेगा कि हमें बोलने दें और हम जो बात रख रहे हैं उसका समय आने पर ही जवाब दें। ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा तो संबद्ध बनाने का होता है बाकी आपकी इच्छा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर बजट अनुमान प्रस्तुत किए और कहा गया कि पेपरलैस बजट पेश किया गया है जबकि यह भी साथ ही कह देना चाहिए था कि यह पेपरलैस व डायरैक्शनलैस बजट भी है। हिमाचल प्रदेश में किस ढंग से वित्तीय अराज़कता का माहौल चल रहा है और किस ढंग से मौजूदा सरकार ने पूरी व्यवस्था तहस-नहस कर दी है; यह बजट पूरी स्थिति साफ कर रहा है। इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब यहां पर बजट अनुमान रखें तो इस बजट से जुड़े जो अहम बिन्दु हैं

टी सी द्वारा जारी

11.03.2020/1220/TCV/DC-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री .... जारी

वे सब गायब कर दिए। वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिए था कि जब सदन में बात रख रहे थे तो मुकम्मल बात रखते और साफ कहते कि कांग्रेस ने यहां तक कर्ज़ लिया था और मैंने यहां तक कर्ज़ लिया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 9 फरवरी, 2019 को वायदा किया था कि 5068 करोड़ रुपये का शुद्ध कर्ज़ा लिया जाएगा और यह कर्ज़ एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लिया जाएगा। इन्होंने Fiscal Responsibility & Budget Management Act (FRBMA) की धज्जियां उड़ा दीं। उसमें जो 3 प्रतिशत की बंदिश लगाई गई थीं, उसको भी इन्होंने तोड़कर फैंक दिया और लगभग 4 प्रतिशत के आस-पास कर्ज़ लिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैं आपको डेट-वाइज़ बताता हूं। इन्होंने 9 अप्रैल को 400 करोड़ रुपये, 9 जुलाई को 500 करोड़ रुपये, 6 अगस्त, को 250 करोड़ रुपये, 20 अगस्त को 250 करोड़ रुपये, 29 अक्तूबर को 400 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया और जनवरी के बाद तो इन्होंने पूरे जोर-शोर से कर्ज़ा लेना शुरू कर दिया। इन्होंने 9 जनवरी को 1000 करोड़ रुपये, 15 जनवरी को 500 करोड़ रुपये, 4 फरवरी को 500 करोड़ रुपये, 20 फरवरी को 1000 करोड़ रुपये और 5 मार्च को 1160 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया। अध्यक्ष महोदय, इधर बजट पेश करने आ रहे थे और बीती रात को 1160 करोड़ रुपये का कर्ज़ा ले रहे थे। यहां हमें अटैची दिखाई जा रही थी लेकिन यह नहीं बताया कि बीती रात को मैं बैंक में गया था और वहां से 1160 करोड़ रुपये का कर्ज़ा लेकर आया हूं। इसका मतलब है कि आपने जो सदन में कहा उससे 1092 करोड़ रुपये का ज्यादा कर्ज़ा लिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी छुपा किस लिए रहे हैं? ये आपकी किताबें हैं, आज हम कुछ भी अपनी ओर से नहीं बोलेंगे, फिर श्री महेन्द्र सिंह जी बोलेंगे कि कागज़ दिखाओ। ये आपकी किताब है 'Budget in brief' क्या ये भी जाली है? ...(व्यवधान) विनोद जी आप सीनियर मैंबर हैं, ज़रा ध्यान से

सुनें। अध्यक्ष महोदय, पेज़ नम्बर-11 पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब इनकी सरकार आई तो इनके पास 47,906 करोड़ रुपये का कर्ज़ा था। उसके बाद वर्ष 2018-19 में 50,773 करोड़ रुपये और अब 2020-21 में आपने 61,302 करोड़ रुपये की प्रोजैक्शन की

11.03.2020/1220/TCV/DC-2

है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में भविष्यवाणी कर देता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के अब तक रहे सभी मुख्य मंत्रियों में से सबसे महंगे मुख्य मंत्री साबित होने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा कर्ज़ लेने के लिए अपना नाम यहां पर अंकित करवाएंगे। ...(व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कर्ज़ को डाक्युमैंट में मैंशन क्यों नहीं किया? आपने विधान सभा में बजट पढ़ा, आपने उसमें क्यों नहीं लिखा कि आपने कितना कर्ज़ा लिया है? आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने सदन से छिपाया कि आपने कितना कर्ज़ा लिया है? ...(व्यवधान) राकेश जी ओपन सीक्रेट नहीं होता है। यह दस्तावेज़ इस सदन में इसीलिए आता है,

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

11.03.2020/1225/RKS/DC-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री... जारी

यह दस्तावेज़ इस सदन में इसीलिए आता है। जब बुक्स में है तो आपको यहां भी लिखना चाहिए था। आपने इस दस्तावेज़ में क्यों नहीं लिखा कि आप एक वर्ष में कितना कर्ज लेंगे? जब आप वर्ष 2019 के दस्तावेज़ में लिख सकते हैं कि हम 5,068 करोड़ रुपये का कर्ज लेंगे तो आप इस वर्ष के दस्तावेज़ में क्यों नहीं लिख रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी आपने इस सदन से बेईमानी की है। आपने गैप फंडिंग का ज़िक्र नहीं किया है। मुझे लगता है आप श्री महेन्द्र सिंह जी के झांसे में आ गए। आप 9वें वित्तायोग की बात करते हैं। आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हम ' भारत सरकार के सहयोग से, अंतराष्ट्रीय फंडिंग एजैंसी से और युक्तिकरण यानी जुगाड़बाजी से' इसको पूरा करेंगे। आपको केंद्र सरकार से क्या मिल

रहा है? हवाई अड्डे के लिए तो आप कोई पैसा नहीं ला पाए। आपको इसके लिए स्टेट से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली से पैसा लाएंगे। आपने पिछले वर्ष लिखा था कि '10,330 करोड़ रुपये External Aided Projects के माध्यम से जुटाए जाएंगे' और जब हम यह बात कह रहे थे तो माननीय मंत्री जी को गुस्सा आ गया था। जबकि हकीकत यह है कि इनमें से एक भी प्रोजैक्ट सीरे नहीं चढ़ने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने गैप फंडिंग फर्जी सोर्सिज से दिखा दी और इस तरह आपने इस सदन के साथ फ्रॉड किया है । आप इस सदन में यह कहें कि मैं अगले वर्ष एक फूटी-कौड़ी कर्ज़ा नहीं लूंगा या फिर इस दस्तावेज को रिवाइज करें कि हमसे यह चूक हुई और यह चीज़ हमने सदन से छिपाई है। आपको एक्चुअल लॉन का ज़िक्र करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, 'राजकोषीय घाटा 7272 हो गया,' गैप फंडिंग की बात नहीं आ रही है और विकास दर 7.1 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत पहुंच गई है। लेकिन मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बहुत विकास कर रहा हूं। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी यह पहली बार हुआ है। ...(व्यवधान) आप पूरे वर्ष शोर मचाते रहे कि बहुत विकास हो रहा है लेकिन विकास दर 7.1 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत पहुंच गई है। आपको इसके लिए प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पहले यह होता था कि कर्ज बढ़ता था और साथ में विकास भी होता था।

11.03.2020/1225/RKS/DC-2

लेकिन पिछले 20 वर्षों में यह पहली बार हुआ कि विकास दर इतने नीचे आ गई। कर्ज़ बढ़ा, विकास गिरा यह आपकी उपलब्धि है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपने गैप फंडिंग का फर्जी सोर्स दिखाया है, उसके लिए आपको हमेशा जाना जाएगा। अभी मेरे साथी माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी यह बात उठाना चाहते थे कि Yes Bank डूब गया और उसकी आंच हिमाचल में आ रही है। यह प्राइवेट बैंक, यह रिस्किंग बैंक जिसका सारी दुनिया में शोर मचा है कि यह डूब जाएगा लेकिन कांगड़ा सैंट्रल को-ओपरेटिव बैंक उसमें 150

करोड़ रुपये फिक्स डिपोजिट रख रहा है। सारी दुनिया ने वहां से पैसे निकाल दिए लेकिन कांगड़ा सैंट्रल को-ओपरेटिव बैंक 150 करोड़ रुपये फिक्ट डिपोजिट करवा रहा है? किसके कहने पर यह फिक्स डिपोजिट करवाया गया, क्या मजबूरी थी और कौन लोग हैं जिन्होंने इस बैंक को प्रमोट किया?

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

11.03.2020/1230/बी.एस./एच.के./-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी....

आप समार्ट सिटी की बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय,स्मार्ट सिटी का 179 करोड़ रुपया 75 प्रतिशत यश बैंक में पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी का पैसा किसने इस बैंक में जमा करवाया? क्या हिमाचल प्रदेश में दूसरे राष्ट्रीय बैंक नही थे जो वहां जा करके पैसा जमा करवा गया। आर.बी.आई. ने कह दिया कि 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकल सकता। सरकार को इस संदर्भ में सबसे पहले स्टेटमैंट देनी चाहिए कि यश बैंक में हिमाचल प्रदेश का किन-किन अदारों का पैसा लगा हुए है? सहकारी बैंक में कितना पैसा है? कोई कह रहा है कि आरट्रैक का पैसा वहां पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है कि ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का पैसा उसमें है। सच्चाई तो माननीय मुख्य मंत्री जानते होंगे या वित्त के अधिकारी जानते होंगे या फिर जमा करवाने वाले जानते होंगे, जिन्होंने अखबार में कहा है कि उस बैंक में थोड़ा ब्याज ज्यादा था। क्या सरकारें ब्याज का लालच करने लग पड़ी कि उन्हें प्राइवेट बैंकों तक जाना पड़ा। जैसे ही यश बैंक की सच्चाई सामने आई थी सब लोगों ने पैसा निकाल लिया था। लेकिन यहां पर सब सोए रहे। जब एक वर्ष पहले से पता लग रहा था कि क्या हो रहा है तो आप क्या नहीं जागे।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ माननीय सदन को यह जानकारी दी जाए कि हिमाचल प्रदेश में वह कौन सा प्रभावशाली आदमी है जिसने यश बैंक को प्रमोट किया, जिसने सरकारी पैसा यश बैंक में रखवाया है। इससे पहले आई.एल.एफ.एस. डूब गई। आई.एल.एफ.एस. में भी कोई कह रहे थे कि पी.एफ. का पैसा है। दूसरे लोगों का पैसा है, सरकार का पैसा है। कितना पैसा है कृपया बताने की कृपा करें। सच्चाई को तो यहां पर पता चले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अंतिम क्षण में यहां पर 7 हजार करोड़ रुपए सप्लिमेंटरी डिमांड रख दी है। किस ढंग से प्रदेश में फिजूलखर्ची हुई है, किस ढंग से 3500 करोड़ रुपए का ओवर ट्राफ्ट हुआ है। हमेशा सप्लिमेंटरी डिमांड 3,000/- या 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं जाती थी। इस बार 7000/- करोड़ पर पहुंच गई। पिछले बजट में राजस्व प्राप्तियां जो दिखाई गई थीं उसमें 33,747/- करोड़ रुपए और प्राप्तियां हुई 32,330/- करोड़ रुपए की। यह इनकी बुक में से है। आपका 1,317/- करोड़ रुपया तो यही पर फर्क आ गया। जो आपने लेना था वह भी नहीं आया है। पिछला बजट प्लस सप्लिमेंटरी डाल लें तो 51 हजार करोड़ रुपए का था। अभी वाला बजट 49 हजार करोड़ रुपए का आया है। पिछले बजट के मुकाबले में 2 हजार करोड़ रुपया कम हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बारे में चिंतित होना चाहिए।

11.03.2020/1230/बी.एस./एच.के./-2

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी यहां पर यश बैंक का मुद्दा लाए हैं। बेहतर होता यदि बजट पर ही यह चर्चा होती। यह सही है कि यह आर्थिक तौर से जुड़ा हुआ मसला है। मैं वर्ष 2004 की बात करना चाहता हूं, उस वक्त आप की ही यू.पी.ए. सरकार ने इस बैंक को लाइसैंस दिया था। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : तब यह स्थिति नहीं थी, जब आपको पता चला कि बैंक डूबने वाला है आपने पैसा क्यों नहीं निकाला।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी केन्द्र की सरकार ने, आर.बी.आई. ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो पैसा है उसे डूबने नहीं दिया जाएगा। बात ठीक है कि इस बैंक में जो हुआ है वह सचमुच में गलत हुआ है, दुभाग्यपूर्ण हैं। बहुत बड़ा नुकसान आर्थिकी को हुआ है। यह बात सच है कि स्टेट का और प्राइवेट सैक्टर का बहुत सारा पैसा इसमें है और सरकारी सैक्टर का भी पैसा है। मेरी पास यह सारी सूची है। **ऐसा नहीं है कि यह हमारे समय से ही शुरू हुआ है, यह आपके समय से भी हुआ है। मैं आपको इसकी सूची प्रदान कर दूंगा।**

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

11.03.2020/1235/DT/HK-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हुए थे तो बेहतर रहता की बता देते कि येश बैंक में हिमाचल सरकार का कितना पैसा फंसा हुआ है? एक साल में जब सब ने निकाल लिया तो सरकार कहां सोई रही? अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्य मन्त्री जी ने लिखा है कि फाईनेन्स कमीशन का धन्यवाद करें, जो आपको ठीक लगता है वह आप करें और आप सब का धन्यवाद करो। लेकिन आपने फाईनेन्स कमीशन से कर्ज माफी मांगी थी, आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर जितना भी कर्ज है उसे माफ कर दिया जाये। उसका का स्टेटस क्या है? क्या आपको कर्ज माफी के बारे में कोई सूचना आई?- आपने जो मेमोरेंडम दिया था या जो आपने बात की थी, उसकी क्या स्थिति है? विधान सभा के लिए आपने पैसा मांगा था उसकी क्या स्थिति है? आपने इण्डस्ट्रीयल पैकेज की बात लिखी है, उसकी क्या स्थिति है? केन्द्र से आपने मदद मांगी आपको मदद नहीं मिली। आपने इसमें लिखा है की प्रधान मन्त्री जी तीन बार हिमाचल आये, आये जरूर, वह देश के प्रधानमन्त्री हैं उनका स्वागत है। आपने कहा कि उन्होंने कहा की आप मेहमान हो मैं घर वाला हूं। लेकिन आप यह बता दें की माननीय प्रधान मन्त्री जी ने अपने तीन दौरों के दौरान हिमाचल प्रदेश को दिया क्या? कुछ तो बतायें? ऐसे में फोरन फण्डिंग और भारत सरकार को आप इस बजट का बेस बना दें तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय मुख्य मन्त्री जी बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अगले साल भी कर्जा लेंगे और ठोक-बजा कर लेंगे। जो प्रोजेक्शनज़ हैं, दस हज़ार करोड़ रूपये आपने इस साल लिया। आप जब से सत्ता में आये हैं, आप दस हज़ार करोड़ ले चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, 6160 हज़ार करोड़ आपने पिछले साल लिया। तीसरी बात अगले साल

के लिए 61000 करोड़ की प्रोजैक्शन दी है, जबकि वह 65000 करोड़ रूपये तक जायेगी। आप जब सत्ता से जाने वाले होंगे तब आप 75000 करोड़ रूपये से ऊपर निकल चुके होंगे। आप ने यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा कर दी है। आपने पूरे बजट में रेवन्यू जनरेट करने की एक भी बात नहीं लिखी है। पूरा बजट साइलेन्ट है। यह स्मार्ट सीटि और के0सी0सी0 बैंक को लेकर ट्रीब्यून में कितनी बड़ी-बड़ी ख़बरें छप रहीं हैं। इसमें सरकार

11.03.2020/1235/DT/HK-2

को संज्ञान लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह फोरन फण्डिंग की बात करते हैं, जिनको इन्होंने बेस बनाया है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ए0डी0बी0 के जो टूरिज्म के प्रोजेक्ट हैं उनकी क्या स्थिति है? ट्रेन्च-1 में 210 करोड़ का था और ट्रेन्च-3 में यह 450 करोड़ का हो गया है। हमारे समय जब टूटीकण्डी पार्किंग आदी बननी थी, हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में भारतवर्ष में बेस्ट स्टेट एडजज किया गया था। आज क्या स्थिति है। आप जंजैहली के लिए लगभग पच्चीस-तीस करोड़ रूपये ले गये क्योंकि वहां आपने क्लचर सेंटर बनाना है। आप यह बतायें की उसकी क्या स्थिति है? उस प्रोजेक्ट को तो आप मॉनीटर कर लो, वह भी 20-25 प्रतिशत से ऊपर नहीं है। पैसा तो आप इस के लिए ले गये पर वह भी टाइमली नहीं बन पायेगा। आप ए0डी0बी0 के प्रोजेक्ट का 70 से 75 करोड़ रूपया सरैंडर कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने जवाब में बता देना कि हमने नहीं किया है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

11-03-2020/1240/वाई.के.-एन.जी./1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी...

जब आप जवाब देंगे तो पता चल जाएगा कि आपने पैसा सरेंडर किया है। वैसे तो पहले से ही इस पर काम चल रहा था लेकिन जब आपकी सरकार बनी और फरवरी-2018 में ए.डी.बी. के 1,892 करोड़ रुपये का जो प्रोजैक्ट था उसका प्रोजैक्ट नोट बनाने के लिए आपको कितना समय मिला था। आप उस टाइम लाइन को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप यहां पर बताएं कि यह 1,892 करोड़ रुपये क्या हिमाचल प्रदेश को मिलेंगे? क्या आपको ए.डी.बी. ने यह नहीं कहा कि आपकी प्रथमिकता टूरिज्म की है या आई.पी.एच. की है या होर्टीकल्चर की है या स्किल डैवलपमैंट की है। आप क्या करना चाहते हैं यह आपको ही मालूम नहीं है और इसके लिए ए.डी.बी. आपसे पूछ रहा है। जल शक्ति मंत्री जी ने बीच में अपने प्रोजैक्ट फंसा दिए, आपने अपने किए हुए हैं और अब ए.डी.बी. आपको कहा रहा कि आपका रास्ता क्या है कम-से-कम स्पष्ट तो करें कि आप किस सैक्टर में...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्रीः सरकार के सारे प्रोजैक्ट पास हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहे हैं। माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी, 1,892 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट दांव पर है यह आपकी वज़ह से ही दांव पर लगा है क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट फंसा दिए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का एक प्रोजैक्ट जो सैंक्शन हो रहा था वह भी फंस गया है। अध्यक्ष महोदय, बागवानी के प्रोजैक्ट का क्या हाल है, फिर माननीय मंत्री जी आप नाराज हो जाएंगे यदि मैं इलेबोरेट करूंगा, आप अभी तक पौधों में ही फंसे हुए हैं। कल्सटर्स की बात, पानी देने की बात ये सब तो अभी शुरू भी नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर ब्यान दे रहे थे कि फोरैस्ट में 500 करोड़ रुपये फंडिंग आ रही है। आपने फोरैस्ट का वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजैक्ट था Forests for Prosperity Project यह 1,000 करोड़ रुपये का था और इसमें ऊना भी शामिल था।

11-03-2020/1240/वाई.के.-एन.जी./2

आपने यह सरेंडर कर दिया क्योंकि इसमें ऊना का नाम था। आपने 1,000 करोड़ रुपये सरेंडर करके 500 करोड़ रुपये ले लिए, यह आपकी कैसी मानसिकता है?...(व्यवधान) आप बताएं कि क्या आपने यह प्रोजैक्ट सरेंडर किया की नहीं?...(व्यवधान) बिलकुल सरेंडर किया है। मैं आपको इसके दस्तावेज़ भी दे दूंगा। जब आपके तीनों प्रोजैक्ट फंसे पड़े हैं तो आप फोरेन फंडिंग का बेस कहां से बना रहे हैं? हमने तो पहले ही आपको कह दिया था कि इन प्रोजैक्टस की बात ही न करें। पुरानी सिंचाई योजनाओं के नवीनीकरण का प्रोजैक्ट जो 4,070 करोड़ रुपये का था वह फंसा हुआ है, बाढ़ एवं नदी प्रबंधन (ए.आई.आई.बी.) का Asian Infrastructure Investment Bank का प्रोजैक्ट जो 3,350 करोड़ रुपये का था वह फंसा हुआ है, Disaster Risk Reduction and Preparedness Project का प्रोजैक्ट जो 2,420 करोड़ रुपये का था वह फंसा हुआ है, बस्तियों को पूर्ण पेयजल योजना न्यू विकास बैंक का प्रोजैक्ट जो 3,267 करोड़ रुपये का था वह फंसा हुआ है, बागवानी विकास परियोजना, जोकि प्रदेश के निचले इलाके के लिए है, का प्रोजैक्ट जो 1,688 करोड़ रुपये का था वह भी फंसा हुआ है। आप इस माननीय सदन में स्टेटमैंट दे दें कि इनमें से एक भी प्रोजैक्ट की फोरेन फंडिंग हुई है और आप फोरेन फंडिंग को आधार बना रहे हैं।...(व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं कि आपने इस बजट में इसका बेस बना दिया है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह बात माननीय मंत्री जी को नाराज करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम इन्हें स्थिति ब्यान कर रहे हैं क्योंकि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिख दिया कि फोरेन फंडिंग इस बजट का बेस होगा और फोरेन से पैसा आएगा तो होर्टीकल्चर, टूरिज्म और फोरैस्ट का हाल देख लो और इन पांच प्रोजेक्टों का भी हाल देख लो।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 3-4 बातें की हैं। जनमंच तो इन्होंने करना ही होता है, इनवैस्टर मीट भी इन्होंने करनी होती है, गैस चुल्हा भी इन्होंने देना होता है। इस बार इन्होंने हवाई अड्डे की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, 1,013 करोड़ रुपये का मण्डी का हवाई अड्डा...(व्यवधान)माननीय मुख्य मंत्री जी हम सब जानते हैं...(व्यवधान)वह कुछ नहीं है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

11/03/2020/1245/MS/YK/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी---

...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, ऐसा है मण्डी के हवाई अड्डे की घोषणा करके मुख्य मंत्री जी फस गए हैं। हवाई अड्डे के लिए केंद्र ने पैसा नहीं दिया, यह सच्चाई है। वित्त मंत्रालय ने भी पैसा नहीं दिया जबकि आप वहां गए थे और इस बारे में खबरें भी छपी थीं। आपको रक्षा मंत्रालय ने भी पैसा नहीं दिया, इसकी भी खबरें छपी थीं कि उनसे आपने पैसा मांगा। आप फाइनैंस कमीशन के पास गए लेकिन उन्होंने भी आपको पैसा नहीं दिया। अभी तक उस अड्डे की न कोई डी0पी0आर0 बनी है और न कोई एन्वायरनमैंट क्लीयरेंस है यानी अभी तक कुछ नहीं है। वह आपका एक सपना है और सपने पर आपने 1013 करोड़ रुपये तीसरे साल निर्धारित किए। तीसरे साल में जाकर ज़मीन की एक्वीजिशन पर 2000 करोड़ रुपया लगेगा। उसकी बाकी डवलपमैंट कौस्ट कितनी आएगी, वह 1000-1200 करोड़ रुपये आएगी। फिर उसके बाद उसके बनने की बात आएगी। मतलब 4000-5000 करोड़ रुपये का वह हवाई अड्डा बनेगा। आप बनाएं, हम स्वागत करते हैं लेकिन आपको दिल्ली में कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। यह क्या बात हो गई जबकि आप डबल इंजन की सरकार है? मुख्य मंत्री जी, यह पैसा कर्मचारियों का पैसा था। यह पैसा आशा वर्कर्ज और आंगनबाड़ी कर्मचारियों का पैसा था। आपने कर्मचारियों को वेतन आयोग जो लागू होना है उसके लिए कोई पैसा नहीं रखा। आप उन्हें पैसा कहां से देंगे क्योंकि आपने वह पैसा हवाई अड्डे के लिए रख दिया है? यह वही पैसा है। वैसे कोई भी राज्य की सरकार एयर पोर्ट्स बहुत कम बनाती है। अगर कोई सरकार घोषणा करके फस जाए तभी बनाती है। आपको 90:10 की फण्डिंग नहीं हो रही है और आपका यह फॉर्मूला टूट गया है। आपने 51:49 में एयरपोर्ट ऑथोरिटी के साथ एग्रीमैंट कर लिया। ...(व्यवधान) हिमाचल के लिए तो 90:10 है। आप सदन में मानो कि वह 90:10 का फॉमूला टूट गया और स्मार्ट सिटी के लिए भी टूट गया इसलिए आप 51:49 पर आ गए। अब अगर आपने शिमला का एयरपोर्ट एक्सपेंड करना है तो वह 400 मीटर बढ़ेगा। कांगड़ा का बढ़ाना है तो वह 3050 मीटर बढ़ेगा और एक्विजिशन उसमें शामिल है। अभी से वहां झण्डे दिखाए जा रहे हैं। सबसे आसान तो

आपको कुल्लू वाला ही था, जहां चैनेलाइजेशन सिर्फ़ 80-85 करोड़ रुपये की थी। ...(व्यवधान)

11/03/2020/1245/MS/YK/2

मुख्य मंत्रीः वहां पर 700 करोड़ रुपये से ज्यादा रिवर के पोर्शन को डायवर्ट करने के लिए वह पैसा खर्च हो रहा है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मुख्य मंत्री जी, वह कुल्लू है, मण्डी नहीं है इसलिए वे 700 करोड़ रुपये नहीं लग सकते हैं। यहां हैलिपोर्ट की आपने बात की है लेकिन इसका पैसा तो दिल्ली से आना है। चाहे वह कंगनीधार, बद्दी, रामपुर, संजौली या जो एक-आध आप चम्बा में बनाना चाहते हैं, वे हों। यह पैसा दिल्ली ने देना है। आपने कहा हैलिपोर्ट बनाएंगे। वह 1013 करोड़ रुपये का मसला नहीं है। ...(व्यवधान) वह दिल्ली का ही है। यह 27-28 करोड़ रुपये की बात है। कहां 1013 करोड़ रुपये में आप उनको फसा रहे हो। यह सिर्फ़ एक आड़ है और कुछ नहीं है।

अध्यक्ष जी, ये इन्वैस्टर मीट और इण्डस्ट्री की बात करते हैं। आज तक हिमाचल प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये की इण्डस्ट्री है। आप कहते हैं कि आज से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपके सारे लोग एक इम्प्रेशन देते हैं कि यहां पर 50 हजार करोड़ रुपये की इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। मुख्य मंत्री जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष को हमेशा इसी नज़र से मत लो कि यह विपक्ष है। 31 मार्च को एक्साइज का पैकेज समाप्त हो रहा है और आप इन्वैस्टर्ज की बात कर रहे हैं; 97 हजार करोड़ रुपये के प्रौजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 31 मार्च को एक्साइज का पैकेज समाप्त हो रहा है और इन्कम टैक्स का तो 5 साल पहले समाप्त हो गया था। आपको पैकेज की एक्सटैंशन नहीं मिली है। इसके इम्पैक्ट की स्टडी लगा लेना कि कितना हो रहा है। अध्यक्ष जी, इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पलायन हो गया है। आपको मालूम है कि बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ से सारे चूल्हे के यूनिट भाग गए हैं और मिक्सी के सारे यूनिट्स जा रहे हैं। जो भी यहां पर स्क्रयूड्राइवर से काम करता था; वे सभी लोग जैसे ही यह पैकेज खत्म हुआ तो

जारी जे0के0 द्वारा----

11.03.2020/1250/JK/AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः------जारी-----

500 करोड़ रुपये के ये यूनिट्स चले गए और आप अपने तरीके से पता करवा लें। लगभग 8 हजार कर्मचारी इनमें काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया। अब लोग यहां आना नहीं चाहेंगे क्योंकि वह पैकेज नहीं है फिर वे हिमाचल क्यों आएंगे? वे दिल्ली के आस-पास काम करेंगे। आप पहले यह देख लें कि जो आपके हाथ में है, उसको कैसे बचाना है। यह 97,000 करोड़ रुपया एक ढकोसला है। मुख्य मंत्री जी अपने आपको धोखा मत दो। क्या आपको पता है कि 36 हजार करोड़ रुपये के इन्वैस्टर मीट में प्रोजैक्ट्स आए हैं और जिनको आपके ऑफिसर्ज़ फोन कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमने कोई प्रोजैक्ट नहीं लगाना है। वे 36 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट्स हैं, जिनके लिए आपकी सरकार के लोग पीछे भाग रहे हैं कि आपने तो यहां पर रजिस्टर करवाया था। वे कहते हैं कि ठीक है, सरकार का दबाव था, इसलिए रजिस्टर कर दिया लेकिन आपने कैसे किया? 15 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट्स हैं, जिन्होंने आपके पास भी दिए और उससे डुप्लिकेसी हो गई। वह तो आपके अडिशनल सैक्रेटरी का बयान है कि यहां पर 15 हजार करोड़ रुपये की डुप्लिकेसी है। उसके बाद आपने 34 हजार करोड़ रुपये के बिजली प्रोजैक्ट्स के इकरार करवा दिए उन कम्पनीज़ के जिनमें आप खुद भागीदार हैं। आपने एस.जे.वी.एन.एल.,एन.टी.पी.सी. आदि कम्पनीज़ से इकरार करवा दिए। इसको कहते हैं वज़न बढ़ाओ। मुख्य मंत्री जी, अब कुछ नहीं होगा। हम भी यहीं हैं। जिस दिन आप लाहौल-स्पिति के प्रोजैक्ट्स बना देंगे, हम उस दिन आप से पूछ लेंगे। यह झांसेबाजी जो आप लोगों ने की है, कल ही जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे कुछ लोग मिले। वे कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी ने इन्वैस्टर मीट की और उसके बाद हम लोगों से राय मांगी कि मुझे बजट में क्या करना है? बजट में आपने इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल साइलैंट कर दिया। आपने इसके लिए कोई बात नहीं कही। वे कह रहे थे कि ज्यादा नहीं तो हम लोगों ने जो प्रेजैंटेशन दी, उन

कागजों को ही हमारे वापिस करवा दो, हम काफी समय से मुख्य मंत्री जी के पास जा रहे थे, उनकी कहीं पर भी चर्चा नहीं आई। इलैक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी

11.03.2020/1250/JK/AG/2

आप 2.35 टाइम बढ़ा रहे हो। बिजली के रेट पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बराबर आ गए। एक ही फायदा हिमाचल प्रदेश में था कि बिजली की वजह से लोग हिमाचल में इन्डस्ट्रीज़ लगाने आते थे। आज पंजाब व हरियाणा के रेट बराबर आ गए। वहां पर कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब आप हकीकत को समझना शुरू कर दें। पंजाब IGST रिफंड के लिए 70 देता है और आप 50 में SGST देते हैं। जबकि सारे एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, उनको IGST चाहिए लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा फार्मा उद्योग में भी मंडरा रहा है। 40 प्रतिशत सॉल्ट चाइना से आ रहा है, उससे 40 प्रतिशत दवाइयां बनती हैं। आपने इम्पैक्ट स्टडी करवाई कि कितनी फार्मा कम्पनीज़ पर यह असर होने वाला है। फार्मा उद्योग पर बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा है। आप कहते हैं कि हमने क्या बेच दिया? आप यहां पर पीछे से बोल रहे थे कि पंडोह का इंडस्ट्रियल एरिया तो जांच का विषय है। इधर मंत्री जी भी कागज ले कर घूम रहे थे कि आप भी बोलो, माननीय सदस्य, विनोद कुमार के पास भी गए थे कि आप भी बोलो लेकिन क्या बोलो, सारे रिकार्ड आपके सामने हैं। अगर हम में बेईमानी होगी तो आपने हमें टांग देना। आप अपने ढाई साल का भी समय देखो कि इसमें क्या हो रहा है? हमारे समय तो इंडस्ट्रियल एरिया बना। यहां पर राकेश पठानिया जी ने कहा कि 35 करोड़ रुपया हमने जमीन पर लगा दिया। जो 35 करोड़ रुपया लगाया वह सदा के लिए है। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बना और सारा बिक गया। आपका एक दिन का तम्बू 18 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ रुपया मुख्य मंत्री जी की पब्लिसिटी में, 3 करोड़ रुपया 1835 कमरे किराये पर लेने के लिए, एक दिन के लिए इतना खर्च किया गया लेकिन वह हमेशा के लिए व्यवस्था कायम नहीं हुई। राकेश जी, आप यहां पर बोल रहे थे इसलिए आप देखिये

दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। अध्यक्ष महोदय, हमने बद्दी ट्रेड सेंटर 15 करोड़ रुपये की लागत से बनाया। ठीक है, हमारी सरकार बदल गई उसके बाद इनकी सरकार आ गई।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

11.03.2020/1255/SS-AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागत :

अध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ रुपये का खूबसूरत बद्दी ट्रेड सैंटर बना और उसके बाद उसमें 35 बीघा ज़मीन है। वहां की ज़मीन लगभग 35 करोड़ रुपये की होगी या उससे थोड़ी कम होगी, रेट आपको मालूम होगा। आपने एक लाले को पौने दो लाख रुपये महीने में बद्दी ट्रेड सैंटर दे दिया। यह लाला कौन है? किस वजह से आपको एक लाले को बद्दी ट्रेड सैंटर देना पड़ा? 15 करोड़ रुपये में सरकार ने उसे बनाया और आपको पौने दो लाख रुपये में उसे देना पड़ गया। पौने दो लाख रुपये का मतलब यह हुआ कि साल में 20 लाख रुपया मिल गया। 10 साल के लिए आपने लाले को दे दिया तो 2 करोड़ रुपया हो गया। लाले को 15 करोड़ रुपया लगा हुआ पैसा और साथ में 20-25 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अगर 2 करोड़ रुपये में मिल जाए तो उसके लिए इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि हमने दो इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाए। एक पंडोगा बनाया और दूसरा उधर (कंदरोड़ी में) बन रहा है। हम 150-150 करोड़ रुपया लेकर आए। आप बताएं कि आप कौन-सा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं और उसके लिए कहां से पैसा आया है? आप कह रहे हैं कि इंवैस्टमैंट प्रॅमोशन सैल बनाना है। मैं आपको कह रहा हूं कि यह आपके 15वें वित्तायोग का दस्तावेज़ है, उसने कहा है कि मंदी का ऐसा दौर है कि कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। सारे सैक्टर खासतौर पर इंडस्ट्रियल सैक्टर डूब रहे हैं और यह आपकी दूसरी किताब है जिसके अनुसार हिमाचल में मैनुफैक्चरिंग सैक्टर गिर गया है तथा आप कह रहे हैं इंवैस्टमैंट प्रॅमोशन एजेंसी बनानी है। मुझे आपसे यह कहना है कि आप कोई इंवैस्टमैंट रिटेंशन पॉलिसी ले आओ कि जो 50 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है उसको कैसे बचाना

है। इन लोगों से डायलॉग करो और अपने लेवल पर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि किस ढंग से यह इंडस्ट्री बचानी है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ी रोचक-सी बात हो गई है। पावर सैंटर हैं, मुख्य मंत्री तो मुख्य मंत्री हैं, मालिक हैं, पूरी सरकार हैं। आप कह रहे हैं कि मंडी का हवाई अड्डा बनेगा और आप फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से मिले हैं। आपके केन्द्रीय मंत्री, अनुराग ठाकुर जी धर्मशाला में बयान दे रहे हैं कि गग्गल का हवाई अड्डा बनेगा और वे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से मिले हैं। अरे भाई, फैसला तो कर लो कि कहां बनेगा। केन्द्रीय मंत्री कह रहा है कि मैं भी फाइनेंस कमीशन के

11.03.2020/1255/SS-AG/2

चेयरमैन से गग्गल हवाई अड्डे के लिए मिला हूं और आप कह रहे हैं कि मैं मंडी के लिए मिला हूं। अनुराग जी कह रहे हैं कि ऊना-हमीरपुर रेल लाइन बनानी है और उसके लिए जो 5-6 हजार करोड़ रुपया लगना है उसका आधा पैसा सरकार दे, उसके लिए वे आपके पीछे पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन बनानी है। आप कम-से-कम इकट्ठे क्यों नहीं बैठते? फैसला कर लो कि कौन-सी रेल लाइन बनानी है और कौन-सी नहीं बनानी है। आप पूरे प्रदेश में उलझन जैसी क्यों डाल रहे हो कि कौन-सी रेल लाइन बनानी है और कौन-सी हवाई पट्टी बनानी है? इसमें कोई फैसला कर लो। ...(व्यवधान) नहीं, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, यह रेल लाइन 5821 करोड़ रुपये की बननी है और आधा पैसा आपने देने से इंकार कर दिया। आपने केन्द्र को कह दिया है कि खुद ही पैसा लगाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। वे कह रहे हैं कि अगर मंडी हवाई अड्डे के लिए पैसा है तो इस रेल लाइन के लिए पैसा क्यों नहीं है। उनका बयान अखबार में आया है। ...(व्यवधान) बिल्कुल दिखा देंगे। मंत्री जी, इतने अनभिज्ञ होने की कोशिश मत करो।

मैं आपसे रोड्स की बात करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी, ऐसी क्या बात हो गई कि जो 71 नेशनल हाईवेज़ बनाने थे उसकी आपने बजट भाषण में बात भी नहीं की? ऐसी क्या नाराज़गी हो गई? आपके अफसर कहते थे कि 25 नेशनल हाईवेज़ बनने हैं और फिर कह रहे हैं कि वह लिस्ट मुख्य मंत्री ने चयन करनी है। फोरलेन्स पर आपकी कमिटमैंट थी।

आपने फोरलेन्स के लिए इसमें लिखा है कि बद्दी-नालागढ़ लैंड एक्विजिशन भी हुई थी, छोड़ दी गई। आपने कहा कि बनायेंगे लेकिन आपने बजट की कोई बात नहीं की। पठानकोट-घट्टा-मंडी और नेशनल हाईवे-88 शिमला से मटौर के बारे में भूमि अधिग्रहण और डी0पी0आर0 की बात की है। आपने कहीं पर यह नहीं कहा है कि इस पर कितना पैसा है, कैसे मंजूर हुई, मंजूर हुई या नहीं हुई, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये बनेंगे? ...(व्यवधान) आपके (माननीय जल शक्ति मंत्री) कहने से बनेंगे। आप तो इसलिए बना देंगे, यह आपका आज का सवाल है। जल शक्ति में हमने आपको कहा था कि आप सही बात करें

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2020/1300/केएस/एएस/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी---

आज आपने कह दिया कि जल शक्ति में 148 करोड़ रु0 आए हैं। मंत्री जी, नाराज़ मत होना, टेंडर लगा दिए 2896 करोड़ रुपये के और आप कह रहे हैं कि एडवांस टेंडर नहीं लगाए जाएंगे। आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन भी दे दी और एक्सपैंडिचर सेंक्शन भी दे दी। आपके यहां से छूटा हुआ तीर है और एक्सीअन धड़ाधड़ टेंडर कर रहे हैं और साथ में टैंडर लगा भी दिए कि किसका कितने का टेंडर है। आप हमें कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंडर नहीं लग रहा है। 148 करोड़ रुपये के मुकाबले में 2896 करोड़ रुपये के टेंडर लगा दिए और जल शक्ति मंत्री जी, यह आप ही कर सकते हैं। ...(व्यवधान) जब आप जाओगे तो पता नहीं कितने एक्सिअन और एस.ई. की बली ले जाओगे, जिन्होंने वहां पर बिना पैसे के टेंडर किए होंगे। फाइनैंस वालों ने आपको यह चिट्ठी लिखी है कि ऐसा मत करो। यह चिट्ठी आपको ही आई है और फाइनैंस ने लिखा है कि accord administrative approval for the scheme approved under Jal Jivan Mission. ये जो चिट्ठियां हैं, आपके पीछे पूरी सरकार पड़ी है, खुदा के वास्ते रहम करो, ऐसा मत करो। ...(व्यवधान) आप कर क्या रहे हैं? आप किस ढंग से कर रहे हैं? इतने बड़े

पैमाने पर आपने टेंडर कर दिया लेकिन अध्यक्ष महोदय, चलो, यह बात तो अलग है। मुख्य मंत्री जी, एक बात का विश्वास करना कि यह जो बड़सर-जाहू-कलखर सड़क है, घुमारवीं-सरकाघाट, द्रमण-सिंहुता, कोटला-मुबारकपुर या मरिंडा-जयसिंहपुर, ये सड़कें बनी हुई हैं। ये नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड को मीट करती हैं। इनको सीधे ही नोटिफाई मत करा देना कि इनको हमने नेशनल हाईवे कर दिया। वो वाला नेशनल हाईवे करना जिनमें आप पैसा ले कर आओगे। पी.डब्ल्यू.डी. के लोग कह रहे हैं कि इनको नोटिफाई करके कहेंगे कि ये 10 नेशनल हाईवे मंजूर हो कर आ गए।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात, देखो सरकार कैसे चल रही है, बंदरबांट कैसे हो रही है, ये कैसे पक्षधर हो रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, 466 करोड़ रुपये का सैंट्रल रोड़ फंड आया और इसमें से 225 करोड़ रुपये अकेले मुख्य मंत्री जी के हलके

11.03.2020/1300/केएस/एएस/2

को चले गए। यह क्या हो रहा है? मुख्य मंत्री जी, थलौट-पंजौन-थाची-नरैन-गालू-शैटधार, 75.70 करोड़, ...(व्यवधान) पहले आप हमारी बात सुन लें। जब आपकी बारी आएगी, आप बोल लेना। पहले हमारी बात सुन लें। लम्बा थैच-शीलगाड़ी-कलैनी-कशोड़-पांडली-बाथली-पंडोह, 50.70 करोड़। थलोट-कांडा-थाची-सोमगढ़ सड़क 25.82 करोड़, पंडोह-कांडा, 25 करोड़, लम्बा थाच-शिलाबागी-कलाणी-कशैड़ पांडली, ...(व्यवधान) यही तो मैं आपको कह रहा हूं, आपने इस सड़क के दो पैकेज करा दिए। एक 37 करोड़ रुपये का और एक 50 करोड़ रुपये का कराया। 225 करोड़ रुपये के आसपास आप अकेले सराज को ले गए। ....(व्यवधान) सुनिए, मैं बताता हूं। मैं वह भी बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल रोड़ फंड कभी ऐसा होता है? मुख्य मंत्री कोई विधायक नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी, आप इस मानसिकता से निकलो। आप प्रदेश के मालिक हैं। आप सैंट्रल रोड़ फंड अगर अपने ही चुनाव क्षेत्र को ले जाएंगे, ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुकेश जी पता नहीं आंकड़े कहां से लाते हैं? ...(व्यवधान) एक तो बहुत सारी इन्फार्मेशन लोन्ज़, ए.डी.बी. के प्रोजैक्ट्स से सम्बन्धित ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए बीच में नहीं बोला। आप बोले ही जा रहे हैं मुकेश जी, आपको सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुकेश जी, आप बैठें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2553 है और इसमें 21,22,23,24 और 25 ये सारे मुख्य मंत्री जी के हलके के हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2020/1305/av-as/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागत

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य से आग्रह रहेगा कि मैंने जब इस बारे में विस्तृत उत्तर देना है तो उस वक्त आप चुपचाप बैठे रहना। क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम जब जवाब देते हैं तो आप यहां पर बैठते नहीं है। मेरा विस्तृत उत्तर बाद में आयेगा परंतु जहां तक अभी आप आंकड़ों व तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं, आप बोल रहे थे कि ए0डी0बी0 के प्रोजैक्ट में यह हो गया, वह हो गया और आप जिस प्रकार से ऋण के आंकड़े बता रहे हैं, ...(व्यवधान) आपको इसमें क्लीयर होना पड़ेगा कि ग्रॉस क्या लिया है और नैट क्या लिया है। मगर आपने उसको नहीं देखा तथा सारा गोल-मोल कर दिया। आपको जो आंकड़े या बातें सूट करती थीं; यहां पर कही हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आपको बोलने का समय दिया जायेगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इन्हें सुनने की आदत नहीं है। ...(व्यवधान) मेरे पास आंकड़े हैं। मैं आपको अपने आप आंकड़े दूंगा। ...(व्यवधान) आपको मालूम है कि नाबार्ड के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र की कितनी डी0पी0आर0 बनी थी। ...(व्यवधान) हां, अब बनी हैं, मगर आपकी सरकार के कार्यकाल में कितनी बनी थीं? मेरा विधान सभा क्षेत्र प्रदेश के सबसे पीछड़े हुए क्षेत्रों में आता है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जहां विकास की ज़रूरत होगी वहां उसको पूरा करेंगे। ...(व्यवधान) आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाबार्ड और सी0आर0एफ0 के अंतर्गत कितनी फंडिंग हुई है; अपने कार्यकाल में तो आप लोग इन सारी चीजों का पता ही नहीं लगने देते थे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आजकल ये बाज़ार के मालिक है और हमारी कोई भी कीमत लगा सकते हैं।

11.03.2020/1305/av-as/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है इसलिए अपनी बात जल्दी पूरी करें। ...(व्यवधान) आपके लिए निर्धारित किया गया समय समाप्त हो रहा है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, बीच में इतनी टोका-टोकी हो रही है।

अध्यक्ष : हमने तो कोई टोका-टोकी नहीं की है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष से हो रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी ने तो स्पष्टीकरण दिया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर ब्रिक्स की बात करना चाहता हूं, फिर मंत्री जी यहां पर गुस्सा हो जाते हैं। यह (हाथ में कागज़ दिखाते हुए कहा।) ब्रिक्स की सैंक्शन है तथा विधान सभा का प्रश्न है। इसमें ब्रिक्स के अंतर्गत 78.86 करोड़ रुपये और 62.26 करोड़ रुपये यानी इतनी हैवी डी0पी0आर्ज0 बनी हैं कि लगभग 141 करोड़ रुपये

सीधे मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र को, 28 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री को और 20 करोड़ रुपये सुन्दरनगर के विधायक को बाकी जय श्री राम। यह (हाथ में कागज दिखाते हुए।) क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) यह ब्रिक्स में है तथा यह मंत्री जी का जवाब है। ...(व्यवधान) नहीं, वह आपने डाइवर्ट किया होगा तो अलग बात है। मुख्य मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो सब कुछ किया जा रहा है; ऐसा मत कीजिए। आप पूरे प्रदेश पर रहम करो और बाकियों को भी हिस्सा दो। अगर कर्मचारियों की बात करें तो आप 7वें वित्तायोग के लिए भी पैसा रख देते। आप जब हवाई अड्डे के लिए रख रहे थे तो कर्मचारियों के लिए भी रख देते परंतु उस पर आप चुप हो गये। डी0ए0 की किस्त देना तो रूटीन में आता है मगर आप उसको इसमें मैंशन कर रहे हैं। अब तो अगली किस्त भी ड्यू हो चुकी होगी। इसके अतिरिक्त आपको 7वें वित्तायोग के एरियर्ज भी देने पड़ेंगे इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके; जैसे केंद्र सरकार ने चार साल पहले दिया हुआ है आप भी दे देते। इसके अलावा आउटसोर्स का मामला तो आज आपके सामने आ ही गया है। आप उनके लिए कोई सर्विस रूल या नीति बना दो; आपने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है। ...(व्यवधान) प्रदेश में हो क्या रहा है? हम बोलते हैं तो मंत्री जी यहां पर नाराज़ होते हैं। इन्होंने कहा है कि एक्सियन के थ्रू भर्ती होगी। हमने कहा ठीक है, एक्सियन के थ्रू करो।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2020/1310/TCV/DC-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री.... जारी

अकेले सुन्दरनगर सर्कल में 350 भर्तियां हुई बाकी सारा प्रदेश कहां जाएं? क्या आपने उसकी डिटेल देखी? ये आप कैसी भर्तियां कर रहे हैं? ...(व्यवधान) लेकिन आप एक सर्कल में 350 भर्तियां कर रहे हैं और बाकी किसी में 30, 25 या 20 की जा रही हैं। कांट्रैक्ट कर्मचारियों को 2 साल में नियमित करने का वायदा भी आपने पूरा नहीं किया। (घण्टी)

अध्यक्ष : मैंने आपको पूरा समय दिया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मंत्री जी के कहने पर न रोकें।

आप वीडियो निकाल लो। मुख्य मंत्री जी ने इशारा किया और आपने घण्टी बजा दी। ये नहीं होगा। ...(व्यवधान) यह नहीं होगा ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जी, आपका जो 45 मिनट का निर्धारित समय था, वह दे दिया गया है। ...(व्यवधान) इसमें आप यह कह रहे हैं कि किसी ने कहा। आप वाइंड अप करे। आपको पूरा समय दिया गया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट में वाइंट अप कर दूंगा।

अध्यक्ष : मुकेश जी, 10 मिनट नहीं, आपको जो समय दिया गया है, उसमें वाइंड अप करे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, एस0एम0सी0 शिक्षकों को निकालने की बात आ रही है। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, ये इशारा वीडियो में निकल आएगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए ।

11.03.2020/1310/TCV/DC-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहीं भी इशारा नहीं करता हूं। मेरा कहना है कि इनको बोलते-बोलते सवा घंटा हो गया है और इस सदन में विपक्ष के नेता को कभी भी 30-40 मिनट से ज्यादा समय बोलने के लिए नहीं दिया गया। पूर्व मुख्य मंत्री, माननीय वीरभद्र सिंह जी और धूमल जी भी विपक्ष के नेता रहे हैं and I never saw them कि उनको बोलने के लिए 30-40 मिनट से ज्यादा समय दिया गया। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मैंने इशारा किया । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका जो निर्धारित समय था, वह पूरा हो गया है। आप 2 मिनट में वाइंड अप करे। आप अपना समय देखें, आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गये हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, ऐसे नहीं रोका जा सकता है। 3-4 मिनट तो ऐसे ही खराब हो गये हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बेरोज़गारी बढ़ रही हैं। आप आंकड़े दे रहे हैं कि पिछले साल और इस साल 20,000 नौकरियां दी गई लेकिन यहां पर सरकारी नौकरियों का आंकड़ा घट गया और बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो बदनामी हो रही है, उसको रोकने की कोशिश करें। आपने यहां पर स्टेटमैंट दी कि फूड के लाइसैंस पर ड्रग्ज़ की फैक्टरी चलाई जा रही थीं। ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ से मामला आया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। इसके बाद डिजिटल विज़न, काला अम्ब की फैक्टरी की दवाइयों से जम्मू में 9 बच्चे मर गये। (घंटी) एक मिनट अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल गलत हो रहा है।

अध्यक्ष : मैंने आपको कुछ गलत नहीं कहा है। आपको जो समय निर्धारित था ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं होता है। यह आपको ही मॉनिटर करना है कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष : मैं मॉनिटर ही कर रहा हूं, इसीलिए आपको 45 मिनट दिए हैं।

11.03.2020/1310/TCV/DC-3

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, श्री राकेश पठानिया जी ने फेक डिग्रीज़ के बारे में क्या-क्या नहीं बोला? आज मुख्य मंत्री जी की स्टेटमैंट आ गई है। ...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि मुकेश सैंसेशन फैला रहा है, ऐसा नहीं है, आज ट्रिब्यून की ख़बरों की प्रति मेरे पास हैं। सस्ती शराब पर भी आपने यही कहा था और अब आप खुद ही रोल-बैक कर गये हैं।

...(व्यवधान) कलस्टर यूनिवर्सिटी ऊना और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनानी थी । एक आख़िरी बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपके महकमें से जुड़ी बात है।

अध्यक्ष : मेरा कौन-सा महकमा है? मेरा कोई महकमा नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आपका पुराना महकमा रहा है। मुख्य मंत्री जी आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न लगा था, सी0एम0ओ0 के माध्यम से एक अरब, 27 करोड़, 99 लाख, 98 हजार, 693 की दवाइयां ली गई। ...(व्यवधान

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

11.03.2020/1315/RKS/DC-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री... जारी

सी.एम.ओ. के माध्यम से 125 करोड़ रुपये की दवाइयां खरीदी गई। कांगड़ा और ऊना में साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये की दवाइयां खरीदी गई। आई.जी.एम.सी. में 7 करोड़ रुपये और टांडा मैडिकल कॉलेज में 11 करोड़ रुपये की दवाइयां खरीदी गई हैं। ये सारी दवाइयां सी.एम.ओ. के माध्यम से खरीदी गई हैं और इनमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ होगा। 125 करोड़ रुपये की दवाइयां सी.एम.ओ. के माध्यम से नहीं खरीदी जा सकती। यह बहुत बड़ी बेईमानी है। ...(व्यवधान) माननीय राकेश पठानिया जी यह आपकी भी चिंता होनी चाहिए। ...(व्यवधान) इतना तो राशन नहीं आता जितनी आप दवाइयां खा गए। विजिलैंस के लोग इंडस्ट्री के ऑफिसर्ज को फोन कर रहे थे कि मुख्य मंत्री पूछ रहे हैं कि उस दौरान मुकेश ने क्या किया? मुकेश अग्निहोत्री फोरन कहां गये थे? आप सारा पता करवाइए। आप मुझ से पूछ लो मैं आपको आपके चैम्बर में आकर सब बता दूंगा कि मैं कहां गया था। आप कहां गये थे और आप और आपके मंत्रियों ने अढ़ाई साल में क्या किया है, हम यह सब आपको बता देंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हम आपको बताएंगे की माइनिंग की आय 10 प्रतिशत क्यों घटी। । ...(व्यवधान) आप भी इस सदन में हैं और मैं भी इस सदन में हूं। जो आपका दिल कर रहा है, वह आप दिल खोलकर करें। जो बात होगी वह आमने-सामने होगी। अगर हमने गलत किया होगा तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा विकास और कल्याण की राजनीति की है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको चुप करवा देंगे, तो ऐसा सम्भव नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

11.03.2020/1315/RKS/DC-2

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो विपक्ष के नेता ने अधिकारियों को फोन करने की बात की है, उसे स्पष्ट किया जाए कि हमने किस अधिकारी को ऐसा कहा है। आप बहुत सारी चीजों को सैंसेशनल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ...(व्यवधान) माननीय मुकेश जी राज यहां दिल में रहने दीजिए, अच्छा रहेगा। । ...(व्यवधान) आपको हर जगह घोटाला नजर आ रहा है। मरीज के लिए दवाइयां उपलब्ध न हों तो आप कहेंगे कि मरीज बिना दवाई के मर गया। मरीजों के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाई होंगी तो उससे मरीज की जान ही बची होगी। । ...(व्यवधान) 'स्टेटहुड मारो ढुड' यह आपके हर भाषण में होता है। यह किस नेता ने कहा? क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? ऐसा किसी नेता ने नहीं कहा है। अगर कहा है तो हमें इसका रिकॉर्ड बताइए। यह घोटाला हुआ, यह घपला हुआ इन सभी चीजों से मुझे लगता है कि आप अपनी सरकार के दौर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दो वर्षों से सरकार बदल गई है और यहां पर घोटालों और घपलों की कोई जगह नहीं है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

11.03.2020/1320/बी.एस./एच.के./-1

मुख्य मंत्री जारी...

अगर आप किसी बात को तथ्यों के साथ बोलेंगे तो हम अवश्य कार्रवाई करेंगे ऐसी बातें कहने से कुछ नहीं होता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय ने चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहा था, खैर मैं तो अब मंत्री नहीं हूं परंतु आपके ध्यानार्थ यह बात लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को बड़ा स्पष्ट कर दिया है। जब यह विभाग मेरे पास था तो ई-टैंडरिंग के माध्यम से ये टैंडर लगते थे और इस बार के जो टैंडर हैं वे डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. अप्रूव टैंडर हैं। रेट कंट्रैक्टर वहां पर होता है और उसी के अनुसार दवाइयां खरीदी जाती हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बाद में इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप अधिकृत हैं।

सदन में सूचना

माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि कल दोपहर 01.00 बजे माननीय सदस्यगण सामुहिक चित्र के लिए गेट नम्बर- 1 पर एकत्रित होने की कृपा करें।

अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनोवकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है धन्यवाद।

11.03.2020/1420/DT/yK-1

माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोवकाश उपरांत 02.20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर): अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है और आज माननीय मुकेश जी ने बड़े विस्तार से इसका जवाब भी दिया है। ...(व्यवधान) जितनी कलाकारी के साथ आपने आंकड़ों को यहां पर नचाया, घूमाया, फिराया और जिस तरह से वातावरण खड़ा करने का प्रयत्न किया कि जो मुख्य मंत्री ने दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसमें कुछ भी नहीं है। जो आंकड़े हैं वह मेरे भाई मुकेश जी के पास ही हैं। जिस तरीके से आपने हर बात के लिए सेंसेशनल खड़ा किया है उसके लिए मैं आपके सरकार के अंतिम दो वर्षों के बजट की कॉपियां लेकर आया हूं। मैं अपने बजट पर दो मिनट के बाद कहूंगा। वर्ष 2016-17 के बजट में आपकी घोषणा है कि "that we have opened more than 1,000 schools opened or upgraded. 28 New Degree Colleges opened making the total more than one hundred. College of Fine Arts has also been opened. We have opened or upgraded more than 130 Health Institutions in the State. We have opened 24 new ITI's and two new Engineering Colleges opened. 7 Revenue Sub Divisions, 31 Tehsils/Sub/Tehsils opened". इस पूरी किताब में इंफ्रास्ट्रक्चर्ज के लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं है। आप करें ठीक, हम करें झूठ। आप करें तो सच, हम करें तो पाप। यह कहां का इंसाफ है? How far it will go. मैं आपके अगले बजट पर बात करता हूं। राजा वीरभद्र सिंह जी का यह 20वां बजट था। इसमें जो आपने ओपनिंग्स की हैं,

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

11-03-2020/1425/वाई.के.-एन.जी./1

श्री राकेश पठानिया जारी.....

मैं इसके अगले साल की घोषणा कह रहा हूं। 14 न्यू सब-डिवीज़न, 16 तहसीलें, 31 सब-तहसीलें और मैंने पिछली छोड़ दी हैं और ये अगले साल और लास्ट ईयर वाली हैं। 'New Medical Colleges opened at Nahan and coming up at Chamba and Hamirpur. ESIC Medical College Mandi taken over by the State Government. 21 Civil Hospitals, 34 CHCs, 96 PHCs and 29 Health Sub-Centers opened and 5

Health institutions notified as ESI institutions. 45 Ayurvedic Health Centers opened. 42 new Government Colleges opened'. आपने 119 कॉलेज कर दिए, 1,328 नए स्कूल अपग्रेड कर दिए इसके अलावा 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 40 वेटनरी हॉस्पीटल की घोषणा, 2 वेटनरी पॉलटेक्निक की घोषणा, 47 वेटनरी डिस्पेंसरी की घोषणा और 5 पंचायत वेटनरी डिस्पेंसरी की घोषणा। आपने 2 सालों में जिस प्रकार बंदर बांट किया है...(व्यवधान) पंडित जी मैंने कुछ नहीं बोला आप मुझे सुन लीजिए। 'अपनी कुरतुतां भी सुन लिया करो सानु सुनांदे रहंदे हो'। कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लिया करो कि आपने अंतिम 2 साल में क्या किया। यह बजट बुक आपकी है मेरी नहीं है और यह आपके मुख्य मंत्री की 20वीं बजट बुक है हमारे मुख्य मंत्री की तो केवल तीसरी है। आप दोनों बजट बुक में तुलना करो। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और इस बजट बुक में हम नए स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नए कॉलेजों की बात नहीं कर रहे हैं परन्तु हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, हम नए मैथेमैटिक्स लैब्स की बात कर रहे हैं, हम 1,000 नए बच्चों को लैपटोप देने की बात कर रहे हैं, हम नई साइंस लैब्स खोलने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा विभाग की दिशा बदलने की बात कर रहे हैं और बच्चों को सुविधा देने की बात कर रहे हैं। आपके 2 भाषण केवल राजनीतिक गिमिक्स थे and nothing else. उसके बाद आप आंकड़े रखते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और मेरी समझ से तो बाहर है कि आप क्या कर रहे हैं? माननीय श्री मुकेश जी बार-बार कह रहे थे कि प्रधान मंत्री जी आए तो क्या देकर गए? 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वावलंबन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन योजना, मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री जन-धन योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना,

11-03-2020/1425/वाई.के.-एन.जी./2

आयुष्मान भारत योजना, Doubling of Farmer's Income Programme, स्वच्छ भारत मिशन योजना', और कितने पैसे देंगे प्रधान मंत्री जी।...(व्यवधान)

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): हिमाचल को कितना दिया?

श्री राकेश पठानियाः इस सब में हिमाचल को भी शेयर मिला है। माननीय सुक्खु जी सुन लीजिए, आपको बैठ कर बोलने की बीमारी है, जब आपकी बारी आएगी तब खड़े होकर बोल लेना। यदि मेरे मुहं से कुछ निकल गया तो फिर आप चींखेंगे। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो इतनी सारी योजनाएं आई हैं माननीय प्रधान मंत्री जी ने ये सभी मुफ्त में नहीं भेजी हैं। इन सभी योजनाओं के तहत करोड़ों-अरबों रुपये प्रदेश में आए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी सुनें और बैठे-बैठे न बोलें।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, यह फिर से बीच में बोल रहे हैं और मैंने कुछ बोल दिया तो प्रोबलम हो जाएगी। मेरे बड़े भाई और निकट मित्र हैं पर ऐसे मत बोलें, श्री मुकेश जी बोल रहे थे तब हमने कुछ नहीं बोला। हम आपकी बात सुन रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी कृपया सुनीए।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे और केन्द्रीय योजनाओं पर आपने बहुत कुछ बोला। Our Government is successfully coordinating with the Central Government and making attempts to get more funds under centrally sponsored schemes and also additional securing new projects, externally aided projects. इसके ऊपर हमारी सरकार बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लीयर है, बड़ी क्लीन है। आपने बहुत बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स की बात की और मैं होर्टीकल्चर मिशन से शुरू करता हूं। आपने कहा कि होर्टीकल्चर मिशन में बेड़ा गर्क हो गया। आपने इस प्रोजैक्ट में केवल 23 करोड़ रुपये खर्च किया और हमने 2 साल में 150 करोड़ रुपये खर्च किया। अभी तो केवल 150 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं इस साल we will cross Rs.500 crores और

इसमें strengthening of PCDs किया है, development of new orchards किए हैं, irrigation facilities को दिया है एग्रीकल्चर बिज़नेस सैक्टर को प्रमोट किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ल्ड बैंक की चिट्ठी लेकर आया हूं और यह वर्ल्ड बैंक के राष्ट्रीय हैड की चिट्ठी है। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि "The mission concludes that the high-level monitoring by the Government of Himachal Pradesh (GoHP), has resulted in encouraging implementation progress in project implementation in the past twelve months.

To be continued by AG in English.....

11/03/2020/1430/MS//1
श्री राकेश पठानिया जारी----

This is significantly reflecting in the improvement, ownership and coordination with the participating departments, especially the Horticulture Department. Additionally we also note that many of the pending procurement related issues have been resolved and the project is now well placed to be completed in the coming years. They have given a clean chit. मैं इसको सभा पटल पर रखना चाहता हूं। यह वर्ल्ड बैंक की एजैंसी हमें लिखकर दे रही है कि हम हॉर्टिकल्चर मिशन में क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे भाई साहब ने बहुत लम्बी-लम्बी बातें कीं कि मुख्य मंत्री जी अपने चुनाव क्षेत्र में सब कुछ ले गए हैं। ...(व्यवधान) अपनी सच्चाई भी सुन लो। वर्ष 2013-17 तक एक वर्ष में 4 से 5 करोड़ रुपये हरोली में केवल मुख्य मंत्री राहत कोष से गये। इस तरह आपने 25 करोड़ रुपये पांच साल में मुख्य मंत्री राहत कोष में से लिये हैं। ...(व्यवधान) मैं अपने साथ आपका डाटा लेकर आया हूं। आपको पूरा डाटा देंगे। मुकेश जी, ऐसे ही हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको सब कुछ देंगे, आप बिल्कुल भी टैंशन न लें। हम यहां पर कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं। आपको पूरा डाटा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनमें से 10 परसेंट भी बीमार थे बाकी पैसा तो आपने मित्रों को बांटा। इसको अध्यक्ष महोदय घोटाला बोलते हैं which needs to be probed by this Government.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपा करके सुन लीजिए।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष जी, ये इनकी नाबार्ड की डिटेल मेरे पास है। पांच में से नाबार्ड में पहले तीन चुनाव क्षेत्र में आते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया। आपकी 70-80 करोड़ रुपये की पर-ईयर की एवरेज है और 5 सालों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की एवरेज आती है। ...(व्यवधान) मेरे पास आपकी सैंक्शन्ज की कॉपी है और इसको मैं आपको दूंगा। इसके अलावा, इस साल मुख्य मंत्री जय राम जी की सरकार के अंदर भी आपके लिए 80 करोड़ रुपये दिए हैं। मुकेश जी, इसको मैं सभा पटल पर रख रहा हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी बैठें।

श्री राकेश पठानियाः मुकेश जी, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। मैं कागजों पर बोल रहा हूं और यह प्रिय प्रेम पत्र आपका बोल रहा है, यह मेरा नहीं है। ये आपके कागज बोल रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप चेयर को सम्बोधित कीजिए।

11/03/2020/1430/MS/2

श्री राकेश पठानियाः इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें कीं कि रेल लाइन के लिए इतना पैसा सैंक्शन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया और अनुराग ठाकुर यह बोलता है और जय राम ठाकुर यह बोलता है। आप दोनों आपस में क्यों नहीं बैठ लेते? आपसे यह सलाह मांगने की प्रथा कब से शुरू हो गई? अगर मुकेश जी आप ऊना के हितैषी होते तो अभी हफ्ता पहले जयपुर-चण्डीगढ़-ऊना ट्रेन शुरू हुई। यह ट्रेन शुरू हुई है या नहीं? अगर थोड़ा सा भी प्यार आपको ऊना के प्रति होता तो जो आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते और बोलते कि आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऊना-चण्डीगढ़ से लेकर जयपुर तक एक नई ट्रेन जो अनुराग ठाकुर जी ने चालू करवाई है, उसका आप धन्यवाद करते। यह बड़ी शर्म की बात है। अध्यक्ष जी, बहुत से केन्द्रीय प्रायोजित प्रोजैक्ट्स की इन्होंने बात की। मुकेश जी, मैं आपके साथ प्यार भरी बातें कर रहा हूं, यदि आप सुन लेते तो मैं आपका धन्यवादी होता। आपका सुक्खु जी ने कभी सगा नहीं होना है। ...(व्यवधान) आप अनुराग जी और जय राम जी के बारे में कुछ भी बोलें लेकिन अगर हम बोलते हैं तो आपको तकलीफ होती है? ...(व्यवधान) आदरणीय मुख्य मंत्री जी का मैं

धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने रोपवे कारपोरेशन बनाया। यह पहली मर्तबा एक सोच आई कि हम स्काईवेज को भी यूज करें। हमारी 3000 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 फाइनल स्टेज पर है। Speaker, Sir, I think it is a matter of pride for the State. आज प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी एक डी0पी0आर0 आज फाइनल स्टेज पर है और उस फाइनल स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम इसमें शुरू होने वाला है।

आपने कहा कि यहां पर दवाइयों में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। The State Government is committed to provide free medicines under the Mukhyamantri Nishulak Davai Yojna. These medicines are being provided free to all patients through all health institutions. These are being purchased by the Indenting Officers e.g. CMOs, MS of the hospitals at the rate contract or from other identified resources i.e. CPSUs or IGMC rate contract etc. Everything is followed by the book. अध्यक्ष जी, यह बहुत वैलिड प्वाइंट है। रेट कॉन्ट्रैक्ट में एक-एक बात है जिसके लिए आज मैं जय राम जी की सरकार को और अध्यक्ष महोदय आपको भी बधाई देना चाहूंगा।

जारी जे के द्वारा----

11.03.2020/1435/JK/AG/1

श्री राकेश पठानियाः-----**जारी**-----

क्योंकि आज सिविल हॉस्पिटल से लेकर मैडिकल कॉलेज तक 50 दवाइयां मुफ्त में दे रहे हैं, आप उस समय क्या देते थे? ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज सुन लीजिए। आप लोग बैठिए। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपका मतलब नहीं समझते। सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी अपने को कांग्रेसी नहीं मानते है। सुखविन्द्र सिंह सुक्खु की अलग ही पार्टी है। मैं कांग्रेस एक्स बोल दिया करूंगा। मैं सुखविन्द्र सिंह सुक्खु को अलग से एड्रैस करूंगा, आप चिन्ता न करें। मैं समझता था कि यह सारी कांग्रेस एक है लेकिन सुखविन्द्र सिंह सुक्खु की

कांग्रेस अलग है। इसका मुझे बाद में पता चला। ...(व्यवधान) To enquire quality now rate contract fresh is being finalized to make WHO, GMP as a mandatory condition. अब इसमें कहां से घोटाला हो गया? मुकेश अग्निहोत्री जी आपने तो गला फाड़-फाड़ कर कह दिया कि घोटाला है, कौन सा घोटाला है? I told you then also that please prove this scam. यहां पर मैं एक-एक बात प्रूव कर रहा हूं, एक-एक चीज रेट कांट्रैक्ट के माध्यम से खरीदी गई है। जीरो टोलरैंस के तहत तहत एक-एक चीज खरीदी गई है। एक पैसे का भी घोटाला यहां पर नज़र नहीं आ रहा है। इस सरकार में आपको घोटाले नहीं बल्कि फायदे नज़र आएंगे। जहां आप 8 दवाइयां देते थे, आज वहां पर हम 40 दवाइयां दे रहे हैं। आपको इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए कि आज कौन सी सरकार काम कर रही है कौन सी सरकार ने काम नहीं किया है। आपने यहां पर कर्ज़े के बारे में कहा...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, आपको भी चर्चा में बोलना है इसलिए उस समय आप बोलें। यहां पर कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आपके टाइम की बजट स्पीच बोलती है the State has remained committed towards fiscal consolidation as a pre-requisite for good public finance management. Our huge debt burden and debt servicing has remained a matter of concern for a long time. Our debt burden on 31st March, 2016 is Rs. 38,568 crore and in 2017-18 our interest outgo is likely to be Rs. 3,500 crore. You left the State reeling under debt of

11.03.2020/1435/JK/AG/2

Rs. 48,000/- crores. आप इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूट कर गए हो, आप इस प्रदेश का गला घोंट कर के गए हो, आप हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों का खून पी करके गए हो और तभी आप लोग वहां पर बैठे हो। तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है। अभी भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। जिस तरीके से आपने पांच साल लोन लेने की प्रथा और लोन से हिमाचल की पीठ को तोड़ना ये सारे-का-सारा आपका डाला हुआ ज़ाल है। यह आपका बुना हुआ ज़ाल है। इस ज़ाल के अन्दर हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता रो रही है। सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आप केबिनैट में नहीं थे इसलिए मैं मुकेश अग्निहोत्री जी को पूछ रहा हूं। मैंने पहले भी इनको पूछा था कि आपकी रिसोर्स मैनेजमैंट कमेटी की मीटिंग

कितनी बार हुई थी, जो केबिनैट की सब-कमेटी बनाई गई थी। आपने पांच साल तक कमेटी बना के रखी। आप आज भी गला फाड़-फाड़ कर के रिसोर्स मैनेजमैंट की बात कर रहे हैं। अपनी सरकार में आपने पांच साल में सब-कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं की और आज आप रिसोर्स मैनेजमैंट की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला है और मैं जहां पर हूं, बहुत खुश हूं। मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से इन्होंने हर मैटर को गोल-मोल कर दिया। Who is responsible for fiscal deficit and financial management? We are not responsible. In two years, we are not responsible. अगर कोई जिम्मेदार है then only you are responsible for that. जिस तरीके से आपने हिमाचल प्रदेश का फाइनैंशियल का गला घोंटा है, जिस तरीके से आपने हिमाचल प्रदेश के फाइनैंस का मिसयूज किया है, आप लोग कमाल करते हैं, आप लोग 2-2 हजार इन्स्टिच्युशन्ज़ खोल करके चले गए, पैसा क्या हमारे ---(***)--- ने देना है?

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

11.03.2020/1440/SS-AS/1

श्री राकेश पठानिया क्रमागत :

आप कमाल करते हैं। जिस किस्म से ...(व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के कुछेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात रखने लगे।)

Sh. Rakesh Pathania : Hon'ble Speaker, Sir, I am taking my words back

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप सुनिये। प्लीज़ बैठ जाईये।

श्री राकेश पठानिया : आपको इसी बात का इंतजार था। ...(व्यवधान) पेन हुई न, आपको दर्द लगी न? ...(व्यवधान) I said, I am taking my words back.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं। इसलिए आप बैठिये।

श्री राकेश पठानिया : जनाब, मैंने अपने शब्द वापिस लिये हैं।। apologize, कमाल है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं और दूसरा इन शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जायेगा। आप (विपक्ष से) इतने ज्यादा आक्रोश में क्यों आ जाते हैं? सुनिये, यह मेरे नोटिस में आ गया और माननीय सदस्य स्वयं कह रहे हैं कि वे अपने शब्दों को वापिस लेते हैं। सुक्खु जी, आप बैठिये। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये और इन्हें बोलने दीजिए।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने शब्द वापिस ले लिये हैं और अब इनको नहीं पच रहे तो मैं क्या करूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इनके आखिरी बजट के टूरिज्म के ऊपर चार लफ्ज़ पढ़कर सुना रहा हूं। इन्होंने बड़ा स्पष्ट किया "The State Government is promoting sustainable tourism in the State. To endeavour the State, Government is extending all modern facilities to the tourists to make their stay memorable". इनके किसी भी पांच साल के बजट में इसके अंदर एक भी पैसे का प्रावधान नहीं है। यह बजट बुक आपके सामने है। ये सारी बजट बुक्स मैं लेकर आया हूं, इसमें एक भी नई फूटी कोड़ी नहीं है। इसमें आप बड़ा क्लीयर मान रहे हैं that the Growth Rate is about 5.24% हमारे को

11.03.2020/1440/SS-AS/2

जी0डी0पी0 का ग्रोथ रेट टूरिज्म के माध्यम से मिलता है। आप जब एक तरफ मान भी रहे हैं और उसके बाद उसके लिए एक फूटी कोड़ी का इंवैस्टमैंट नहीं कर रहे। अब आप लोग बड़ा गला फाड़-फाड़ कर बोले - एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट नहीं कोई खुदा का जिन्न बाहर निकल कर आ गया। अरे भाई, एक अंधा और अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझता है कि connectivity is the biggest problem faced by the Himachal Pradesh ठाकुर साहब, आप भी तो उद्योगपति हैं। Connectivity is the biggest problem which Himachal Pradesh Tourism is facing...(व्यवधान) फिर वही बात आ

गई। बैठे-बैठे फिर बोलने की बीमारी शुरू हो जाती है। in the whole of their Budget Speech इन्होंने कभी एक फूटी कोड़ी टूरिज्म के लिए नहीं रखी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहले ही बजट में 50 करोड़ रुपया रख दिया तो क्या कोई पाप कर दिया? दूसरे बजट में पैसा रख दिया तो क्या पाप कर दिया? इस बजट में कोई 1000 करोड़ रुपया रख दिया तो क्या कोई पाप कर दिया? पाप तो आप लोगों ने सारी उम्र किया है। ...(व्यवधान) हर्षवर्धन जी, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं। हमें तो गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आपकी सरकार किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का गला काटती रही और आप भी कुछ न बोलें, हमें इस बात की शर्म आ रही है बाकी तो चलो ठीक है सब चलता है।

अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म के ऊपर मैंने बात कही। ...(व्यवधान) मेरा नम्बर लगे या न लगे परन्तु तुम्हारा नम्बर पक्का नहीं लगना। आप मेरी चिन्ता न करें और आपके नम्बर की कोई बारी नहीं है। आपने फिर गला फाड़-फाड़ कर कहा। I am agree with what Shri Harshwardhan ji has said, I will try to control my voice. But the way Shri Mukesh Agnihotri ji was shouting in the House, Investors Meet, Investors Meet, और मेरे बड़े भाई मुकेश जी आप भी पांच साल तक मंत्री रहे। For five years you were the Industries Minister, आपने अपने सवा घंटे के भाषण में कोई एक प्वाइंट तो बोला होता कि आपने इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए यह किया है। आपके दो बजट की बुक्स मेरे सामने पड़ी हैं। As the Industries Minister in the Cabinet of Virbhadra's Government, what have you done for the Industries एक बड़ा सीरियस एफर्ट्स इंवैस्टर मीट को लेकर हुआ और holding of the Investors Meet in the Dharamsala on 7th and 8th November, 2019 फिर आपको एक और बात की बड़ी चिन्ता हुई कि प्रधान मंत्री

11.03.2020/1440/SS-AS/3

जी आए। This is blessing for the State कि एक प्रधान मंत्री हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में आकर इंवैस्टर्ज़ और 200 डैलीगेट्स को यह बोले कि मैं भी मूल रूप से हिमाचली हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आओ हिमाचल में निवेश करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या इतनी बड़ी बात कोई प्रधान मंत्री किसी स्टेट में जाकर बोलता है? क्या यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय नहीं है? आप लोग कमाल कर रहे हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2020/1445/केएस/एएस/1

श्री राकेश पठानिया जारी----

...(व्यवधान) मुकेश जी, मैं बार-बार वही तो पूछ रहा हूं, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, क्या आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई? ...(व्यवधान) आप ज़रा ध्यान से सुनें।

अध्यक्षः मैं विपक्ष के माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि मैंने इस चेयर से पहले ही व्यवस्था दी थी और लीडर ऑफ अपोजीशन लगभग 55 मिनट बोले हैं। इसलिए राकेश पठानिया जी को भी बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) आपको हमेशा ठीक समय दिया जाता है। ...(व्यवधान) कृपया आप लोग बैठिए।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, यह जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है it is an Incentive Bonanza and much more. Invest in Himachal Pradesh to Make Dev Bhoomi Your Karam Bhoomi, In MSME, there is a provision of Concession of lands in easy installments, . एम.एस.एम.ई. में 50 परसेंट, स्टैम्प ड्यूटी में 50 परसेंट, प्लॉट अलॉटमैंट में 60 परसेंट, स्टैम्प ड्यूटी में 70 परसेंट, प्लॉट अलॉटमैंट के अंदर 70 परसेंट और स्टैम्प ड्यूटी के अंदर फिर से 80 परसेंट यानि इतना कन्सैशन। ये एम.एस.एम.ई. क्या है? आज आप दो-तीन साल के लिए अपना प्रोजैक्ट शुरू करो, परमिशन्ज़ आती रहेंगी। क्या कभी उद्योग मंत्री रहते हुए आपने इतना बोल्ड स्टैप उठाया? यह हमने एक इनविटेशन दिया है। एम.एस.एम.ई. में कौन आएगा? हिमाचल प्रदेश का युवा इसमें सबसे ज्यादा आएगा।...(व्यवधान) सुन लीजिए। आपने किया कुछ नहीं, अब जब होने लगा तो आपको तकलीफ़ हो रही है। मैं आज एक बात के लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। ...(व्यवधान) जो होगा, वह भी आपके सामने आएगा और जो नहीं होगा, वह भी आपके सामने आएगा But I must appreciate and congratulate my Chief Minister for a very sincere and a very, very good effort by doing the Investors Meet in Himachal Pradesh. आज तक आपमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई इतनी बड़ी मीट करवाने की, इन्वैस्टर्ज़ मीट में 200 डैलिगेट्स आए। More than 11 ambassadors of different countries were present in that Meet. ड़े-बड़े औद्योगिक

घराने वहां पर आए। इतने अच्छे वातावरण में सब कुछ हुआ लेकिन आप लोग भी तो विधायक हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी के हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश के विधायक हैं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के विधायक हैं। आप सभी को कार्ड दिए गए लेकिन आप में से एक भी उस मीट में नहीं आया क्योंकि आप

11.03.2020/1445/केएस/एएस/2

देवभूमि के विरोधी हो। ...(व्यवधान) अगर आप हिमाचल प्रदेश के हितैषी होते तो आपमें से कम से कम एक आदमी तो वहां पर आता। आप हर जगह पोलिटिकल लैंग्वेज में बात करते हैं। इतनी बड़ी इन्वैस्टर्ज़ मीट हुई और our Government was so transparent to invite all of you आप सभी को वहां पर बुलाया गया परन्तु आप में से एक भी विधायक वहां नहीं आया। ...(व्यवधान) सुक्खु जी, आप बताओ क्या आप वहां आए थे? जब मुकेश जी, नेता प्रतिपक्ष बने तो उस दिन भी आपको कार्ड लेट ही मिला था। आपको हमेशा कार्ड लेट ही मिलता है, यह आपका दुर्भाग्य है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। ...(व्यवधान The State Government organized MoUs Signing Ceremony at Peterhoff on 25th February, 2019 in which 160 के करीब उसमें एम.ओ.यूज़. साइन हुए worth INR 17,000 Crore were signed. Himachal Pradesh Became the first state to do such a Ceremony. अब इस बात पर भी आपको शर्म आ रही है। on allotment of land यह सारा जो इसका कन्सैशन्ज़ आया, मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमैंट पॉलिसी अभी आई। टूरिज्म सैक्टर पॉलिसी अभी आई। आई.टी.ई.एस. एण्ड ई.एस. डी.एम. पॉलिसी अभी आई। आयुष पॉलिसी अब आई, फिल्म पॉलिसी अब आई, आप पांच साल क्या करते रहे? उद्घाटन करते रहे, फट्टे लगाते रहे, लोगों का बेवकूफ बनाते रहे। फिर आप माइनिंग के बारे में इतना रोते हैं। 80 परसेंट लाइसैंस तो मुकेश जी, आपकी सरकार के दिए हुए हैं। हमारे समय के तो 20 परसेंट भी नहीं हैं। और आज आप बैठे-बैठे माइनिंग के बारे में यहां पर इतना बोलते हैं। माइनिंग माफिया लाने वाले आप लोग हैं। माइनिंग माफ़िया के कर्ता-धर्ता आप लोग हैं।

...(व्यवधान) मैं वही बात बोल रहा हूं। आपका 20वां बजट और हमारे मुख्य मंत्री जी का तीसरा बजट। आपके 20 बजट पर हमारी सरकार का यह तीसरा बजट भारी पड़ रहा है क्योंकि हर फील्ड के ऊपर मुख्य मंत्री जी ने इस बजट स्पीच के अंदर he has covered every department.

हिंदी अ0व0 की बारी में..

11.03.2020/1450/AV-DC/1

श्री राकेश पठानिया-------- जारी

...(interruption) मुख्य मंत्री जी, ये लोग जो बार-बार बात कर रहे थे, regarding this the World Economic Outlook published by the International Monetary Fund (IMF) in January 2020 has estimated that the world economy will grow at the very slow rate of 2.9 percent. This is global recession. जबकि उसके अंदर हिमाचल प्रदेश की growth rate is more than 5 percent and we are the best right now in the whole Country. I agree that the growth rate has come down because of complete international global came-down, but at the same time the way proposals have been mooted in this Budget, we will have very sustained growth in the coming years. I am sure in the next one year you will see that the GDP will grow in Himachal Pradesh with new initiatives. हम लोग कोई घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, ...(व्यवधान) इसलिए नहीं गिरी है, वह इसलिए गिरी है कि पूरे ग्रो में इंफ्लेशन चल रहा है, यह केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ...(व्यवधान) आशा जी, जब आपको समय दिया जायेगा आपने तब बोल लेना, मैं आपको बोलने से नहीं रोकूंगा। मेरा केवल यही निवेदन रहेगा कि दिनांक 6 मार्च, 2020 को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर जो बजट बुक पेश की है उसके माध्यम से लगभग हरेक पहलू को टच किया गया है और इनके दो बजट से यह क्लीयर लगता है। लेकिन अपने कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में

आपने राजनीतिक तौर पर लूट-खसूटकर करके ...(व्यवधान) इतनी घोषणाएं करने के बावजूद भी आप 21 आए और यदि वे घोषणाएं नहीं की होती तो शायद 1 या 2 ही रह जाते। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट की सराहना करने के साथ-साथ यह उम्मीद भी करता हूं कि यह बजट हिमाचल प्रदेश को नई दिशा और ऊंचाइयों पर लेकर जायेगा। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2020/1450/AV-DC/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी को आधे घंटे का समय दिया गया इसलिए विपक्ष के सदस्यों को भी आधे-आधे घंटे का समय दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा है, आप यह बताइए कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो कितना समय दिया गया? इसलिए इस चेयर को भी कुछ निश्चित करने दीजिए। ...(व्यवधान) आप लोग डिक्टेट न करें। ...(व्यवधान) नहीं, इस चेयर को बोलने का हक है और हम आपको संरक्षण देंगे मगर आप डिक्टेट करेंगे तो वह अच्छी बात नहीं होगी। आप बैठ जाइए।

अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किए गए बजट अनुमानों पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया है। ...(व्यवधान) जो धन्यवाद करने लायक बातें हैं मैं उसके लिए धन्यवाद भी करूंगा। मुख्य मंत्री महोदय ने नाबार्ड के तहत 105 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब आपका यह बजट पास होगा तो उसमें इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ आपने हमारी जो विधायक क्षेत्र विकास निधि बढ़ाई है, मैं उसके लिए भी आपका

धन्यवाद करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसको भी 1.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम-से-कम दो या अढ़ाई करोड़ रुपये किया जाए। इसके अतिरिक्त आपने ऐच्छिक निधि बढ़ाई है मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने दिनांक 6 मार्च, 2020 को आपका पूरा बजट भाषण सुना और पढ़ा। लेकिन बाकी मुझे इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर सकूं और यह बोलूं कि आपका यह बहुत अच्छा बजट है।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2020/1455/TCV/DC-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा.... जारी

इस बजट को पढ़ने और सुनने से ऐसा लगा जैसे आपने पूर्व की भांति यह बजट भी पेश किया है। इस बजट में कोई विशेष बात नहीं कही गई है। आपने अपने पहले-दूसरे पैराज़ से ही इन्वैस्टर मीट पर जोर दिया है। आप इससे बड़ी वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपके सामाने तथ्य हैं, आपने इस इन्वैस्टर मीटर पर करोड़ों रुपये खर्च किए और इसकी आउटपुट जीरो है। अभी तक तो इस इन्वैस्टर मीट की आउटपुट जीरो है लेकिन यदि भविष्य में होगी तो उस समय आपका धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा आपका जनमंच पर बड़ा फोकस है, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था या इस बजट भाषण की बात है। आप अक्सर जनमंच की बात करते रहते हैं। आपके 15 दिन तो प्री-जनमंच में लग जाते हैं और इससे अधिकारियों की भी प्रताड़ना होती हैं। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से लोगों के फोन आते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी तक 2 जनमंच लगे हैं, एक मैं माननीय परिवहन मंत्री जी और दूसरे में माननीय बरागटा जी आए थे। उस व़क्त लोगों को बड़े आश्वासन दिए गए कि आपका काम हफ़्ते या 15 दिन में हो जाएगा लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुए हैं।। say, it is total misuse of funds.

दूसरा, मुख्य मंत्री महोदय, आपके भाषण में शेरो-शायरी ज़रूर सुनने को मिली। मैं इस बजट भाषण पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने इस बारे में काफी

डिटेल में चर्चा की है। इसमें आउटसोर्स, दवाइयों की खरीद-फ़रोख्त व अन्य बातों पर काफी विस्तार से चर्चा की गई। मैं अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहूंगा।

(माननीय सभापति, श्री राकेश पठानिया जी पदासीन हुए)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने इससे पहले जो 2 बजट यहां पर पेश किए, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को उसमें कुछ भी नहीं दिया गया लेकिन मैंने सोचा था कि शायद इस बजट में कुछ मिल जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने मेरे

11.03.2020/1455/TCV/DC-2

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया है। इस बजट में हमें कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने व आपका धन्यवाद करने में असमर्थ हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अपनी बात कहना चाहूंगा। आपने इस बजट में बेरोज़गारों को रोज़गार देने की कोई बात नहीं की है। इस तरह से बेरोज़गारों व युवाओं को ठगा गया है। आपने वॉटर कैरियर, वॉटर गार्ड या किसी अन्य के 100-200 रुपये या 300 रुपये ज़रूर बढ़ाये हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात के समान है। आपने दिहाड़ी सिर्फ़ 25 रुपये बढ़ाई है और दूध का दाम 2 रुपये बढ़ाया है। किसानों व बागवानों के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके इस बजट की प्रशंसा करूं या इसका समर्थन करूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। चाहे प्रदेश की सरकार हो या आपकी केन्द्र की सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं कि गडकरी जी 69 नेशनल हाईवे कहां गये? आज महंगाई चरम-सीमा पर पहुंच गई है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

11.03.2020/1500/RKS/HK-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा... जारी

केंद्र सरकार ने कहा था कि हम हर वर्ष बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ झूठ पर झूठ बोलने का काम चला हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार पूरी तरह फेल है। चाहे रेप केस हो, मर्डर हो या फर्जी डिग्रियों की बात हो, आज कानून-व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शुभम नाम का एक लड़का 30 नवम्बर, 2019 से लापता है। वह अपने मां-बाप का इकलौता लड़का था परंतु उसकी गुमशुदगी का आज तक कोई पता नहीं चला। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से कई बार डेप्युटेशन मिल चुके हैं परंतु आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ ले चुकी है और 1160 करोड़ रुपये का कर्ज़ और लेने जा रही है। यह सरकार कर्ज़ की सरकार है और जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने भी ऐसा ही किया था। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप उसी तर्ज़ पर जाना चाहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप हमारे स्थान में बैठेंगे और हम आपके स्थान पर होंगे। सरकार पूरी तरह फिजूलखर्ची में डूबी हुई है। माननीय इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने आज आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। यह ठीक है कि आउटसोर्स में पहले से भर्तियां हो रही हैं। आज बहुत से लोग आउटसोर्स में कार्य कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो और इस नीति में एस.सी., , एस.टी. के लिए भी प्रावधान किया जाए। मैंने आज माननीय जल शक्ति मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि आपके दो वर्ष के कार्यकाल में रोहड़ू डिविजन में कितने डंगों के टैंडर हुए? आपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि ' पिछले दो वर्षों में 123 डंगों के टैंडर हुए हैं।' यह कौन-से डंगे हैं, किस ठेकेदार ने इनका टैंडर लिया, यह सब अंडर टेबल टेंडर हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं मानता हूं कि आपके विभाग का पहला कर्तव्य हर आदमी को पानी मुहैया करवाना है परंतु इसके अलावा और भी कार्य हैं जिन्हें आपको करना है। यहां पर कुछ दिन पहले यह प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान सरकार द्वारा कितने लोगों को एक्सटैंशन, री-इम्प्लॉयमैंट दी गई। इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि ज्यादातर पटवारियों को री-इम्प्लॉयमैंट दी गई है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

11.03.2020/1505/बी.एस./एच.के./-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

मेरा आज भी प्रश्न लगा था उस जवाब में मेरे चुनाव क्षेत्र में पटवारियों के पद खाली पड़े हैं। यदि उन पदों को भी इसी तरीके से भर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज मेरे चुनाव क्षेत्र की ऐसी स्थिति है कि वहां पर एक एस.डी.एम. है। जुब्बल में एक अन्य एस.डी.एम. का पद सृजित किया गया है परंतु मेरे एस.डी.एम. को दो दिनों के लिए जुब्बल जाना पड़ता है। उसके पास रोहड़ू में पहले ही बहुत ज्यादा कार्य है। मेरे कहने का यह मतलब यह नहीं है कि आप रोहड़ू में अपने यह पद क्यों सृजित किया या वहां पर आप एस.डी.एम. को न भेजें। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि जुब्बल के लिए आप नया एस.डी.एम. भेज दो, ताकि राहड़ू वाले एस.डी.एम. को ज्यादा काम न पड़े और लोगों के कार्य समय पर हो सकें। इसी तरह तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हाल है। वहां पर छह-सात महीनों से कोई भी नहीं है। ये पोस्टे खाली पड़ी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि सरकार जिस तरह से बड़े-बड़े वायदे करती है उस तरीके से कोई काम नहीं हो रहे हैं। आपने दो वर्षों में कुछ नहीं किया यही कारण है कि मेरे चुनाव क्षेत्र का आज यह हाल है।

आजकल स्वास्थ्य विभाग भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास है इसलिए मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ बातें करना चाहूंगा। मेरा सिविल अस्पताल रोहड़ू है। यह अस्पताल रोहड़ू चुनाव क्षेत्र को ही नही अपितु वहां पर जुब्बल और उत्तराखण्ड के मरीज भी वहां पर आते हैं। जब मैंने वहां पर प्रतिदिन ओ.पी.डी. नम्बर की जानकारी ली तो शायद थोड़ा ही फर्क होगा अन्यथा वह दीनदयाल उपाध्याय, अस्पताल, शिमला के बाराबर है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वहां पर डॉक्ट्र्ज की बहुत कमी है। वहां पर सैंक्शन्ड सन्ट्रैन्थ 30 की है परंतु आज वहां पर कितने डॉक्ट्र्ज हैं? कभी 12 कभी 13 और कभी 14 यानी 15 से ज्यादा संख्या वहां कभी नहीं गई। वहां पर रेडियोलॉजिस्ट कई वर्षों

से नहीं आया। अगर छोटा-मोटा एक्स-रे भी करवाना हो तो गरीब लोगों को प्राइवेट में जाना पड़ता है। हर गरीब यह खर्चा नहीं कर सकता, नहीं तो उन्हे शिमला आना पड़ता है। इसी तरह एनथिज़िया का डॉक्टर भी हमारे वहां पर नहीं है। जनरल सर्जन के बिना हमारा सारे-का-सारा अस्पताल अपंग है। पिछले सत्र में भी मैंने इस माननीय सदन में एक मामला उठाया था जिसमें मैंने कहा था कि वहां पर 22 वर्ष की एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त भी यह पद नहीं भरा गया था और आज भी नहीं भरा गया है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें (घण्टी) ।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : इसी तरह माननीय सभापति महोदय, यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जितनी भी मेरे चुनाव क्षैत्र में अध्यापकों की खाली पोस्टें पड़ी हैं उनको भी जल्दी-जल्दी भरने की कृपा करें। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा कि आपने अब तक क्यों नहीं भरी और क्या कारण रहा।

सभापति : माननयी सदस्य विषय पर बोलें, कृपया वाईंडअप करें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : सभापति महोदय, 30 मिनट प्लीज। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपकी सरकार बनी आपने सबसे पहले क्या काम किया, जो हमारा ठियोग-कोटखाई-खड़ा पत्थर- रोहड़ू हाटकोटी का काम चला हुआ था उसे बंद करवा दिया। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। Reasons are best known to you why you have stop the work, why you have descended the work? मुझे उस पर नहीं जाना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है और जो 8-9 प्रतिशत कार्य बचा हुआ था उसका जल्द से जल्द कार्य शुरू होना चाहिए। यह मेरा आग्रह रहेगा। आपने इसे किन कारणों से बंद किया मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। दूसरी बात सब्जी मण्डी मैंहदली में बहुत अच्छा कार्य चला हुआ था।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

11.03.2020/1510/DT/YK-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा द्वारा जारी

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय , मेंदली में जो सब्जी मण्डी है वहां 2 वर्षों तक बढ़िया काम चला । मैं हर सत्र में प्रश्न लगाता हूं कि सब्जी मण्डी, मेंदली का कार्य कब शुरू होगा? हर बार यही जवाब मिलता है कि इसका कार्य जल्द शुरू किया जा रहा है। कभी कहतें हैं कि लगभग 20 करोड़ रूपये की डी0पी0आर0 इस सब्जी मण्डी के लिए बनाई गई और इसमें तीन-चार मंजिल का भवन बनाया जाना है। मेरा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय व माननीय कृषि मन्त्री महोदय से आग्रह है कि इसका काम शीघ्र शुरू होना चाहिए। एक बहुत आवश्यक बात मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि सीविल हस्पताल रोहडू का भवन लगभग चार-पांच माह में बनकर तैयार हो जायेगा और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह जाता है हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री, श्री वीरभद्र सिंह जी को। उनकी बदौलत यह भवन बन रहा है। जब भी यह भवन बनकर तैयार होगा तो आप उसका उद्घाटन करने आयेंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आईये और उसका उद्घाटन करिए और जल्दी-से-जन्दी करिए। मैं तो चाहूंगा कि आप कल ही इस भवन का उद्घाटन करने रोहडू आ जाओ। साथ ही मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि इस अस्पताल का उद्घाटन आप तब तक न करिए जब तक आप उस हस्पताल में सारी सुविधाऐं प्रदान न कर सकें, नहीं तो बाद में आप ही कहेंगे कि कांग्रेस सरकार के समय ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं ज्यादा फालतू की बातें नहीं करूंगा। सब को पता है कि बजट में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। हमने भी बजट को सुना और पढ़ा है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तारीफ के काबिल हो। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आपके पास लोक निर्माण विभाग भी है। आज लोक निर्माण विभाग की स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र में ठीक नहीं है। इसकी

बहुत ही दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति इस कारण है क्योंकि वहां की सड़कों की हालत ठीक नहीं है। चाहे हमारी रोहडू से चिड़गांव सड़क की बात करें, चाहे हम खसधार सड़क की बात करें, बडियारा-खटियाली सड़क बात करें लगभग सभी सड़कों की स्थिति दयनीय है। वहां के लोक निर्माण विभाग के जितने भी अफसर है उनका काम है की सरकार ने जो अपने चार -पांच वर्करों के नाम दिये

11.03.2020/1510/DT/YK-2

हुए हैं जिनको ठेका देना है, उनको ठेका दिया जाता है और उनकी पेमेन्ट कैसे करनी है यही काम इन अफसरों का है। डोडरा-क्वार एक दूर-दराज़ का क्षेत्र है। वहां पर अलग से लोक निर्माण विभाग का एक डिवीजन बनाया गया है। इस डिवीजन में न तो जे0ई0 है, न तो एस0डी0ओ0 है न ही एक्सीयन है। यह सब रोहडू में बैठे रहतें हैं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय अगर कभी आप वाया रोड डोडरा-क्वार जायेगे तो आप को पता चलेगा कि वहां की रोड की स्थिति क्या है? मैं अब बिजली के सम्बन्ध में थोड़ी बात करना चाहूंगा । हि0प्र0राज्य विद्युत बोर्ड का ऐसा हाल रोहडू में है कि अगर फाल्ट इस साइड में है तो लाइट किसी और साइड की चली जायेगी। थोड़ी हवा चली लाइट के बूरे हाल हो जाते हैं। कई जगह बोल्टेज की दिक्कत बहुत ज्यादा है। मैं यही कहना चाहूंगा की आज स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह सारी चीजें मैंने आपके ध्यान में इसलिए लानी थी क्योंकि आपके पास यह सारे विभाग हैं। पार्किंग की भी रोहडू में बहुत प्रोबलम है। माननीय सभापति महोदय आपने मुझे माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं समर्थन करूं।

सभापतिः माननीय जल शक्ति मन्त्री आप कुछ कहना चाह रहें हैं।

माननीय सभापति महोदयः माननीय सदस्य ने जो बात कही कि रोहडू के आई0पी0एच0 मण्डल के अन्दर कुछ वर्क आर्डर हुए है, निश्चिततौर से हुए हैं और इनके प्रश्न भी लगें हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जार

11-03-2020/1515/वाई.के.-एन.जी./1

जल शक्ति मंत्री जारी.....

और हम उनकी विधिवत रूप से जांच करवा रहे हैं। जिसने गलत किया होगा वह भुगतेगा। हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि इतने ज्यादा डंगे लग जाएं, इतने ज्यादा वर्क आर्डर दिए जाएं, उसमें बाकायदा हमने जांच बिठाई हुई है और जांच के जो भी परिणाम होंगे वे हम हाऊस में रख देंगे।

सभापति (श्री राकेश पठानिया): अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी भाग लेंगे।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 06-03-2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस माननीय सदन में एक सर्व-स्पर्शी, समता-युक्त और कर-मुक्त और अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया है इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथ ही प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ न डालते हुए एक ऐसा विकासोन्नमुखी बजट प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी विधायक क्षेत्रिय विकास निधि को बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख रुपये कर दिया है। माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र में तरह-तरह के विकास की छोटी योजनाओं के बजट की आवश्यकता पड़ती है और ये ऐसी योजनाएं होती हैं जो गांव के आम व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं लेकिन विधायकों के पास बजट कम होने के कारण उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लगातार दुसरी बार

विधायक क्षेत्रिय विकास निधि में बढ़ोतरी करके जहां माननीय विधायकों का मनोबल बढ़ाया है वहीं क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही विधायकों को विकास के लिए पहले 105 करोड़ रुपये की सीमा तय थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसे भी बढ़ा कर 120 करोड़ रुपये कर दिया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही माननीय विधायकों की एच्छिक निधि को भी बढ़ा कर प्रति वर्ष 10 लाख रुपये कर दिया गया है और इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

11-03-2020/1515/वाई.के.-एन.जी./2

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने और देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रदेश के पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहूंचे इस प्रकार के प्रयास किए हैं। चाहे 'उज्ज्वला योजना' हो, चाहे 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना' हो, चाहे वह शौचालयों के निर्माण की बात हो, चाहे वह 'जनधन योजना' की बात हो

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

11/03/2020/1520/MS/YK/1

श्री राजिन्द्र गर्ग जारी-----

या फिर गरीब लोगों के लिए बहुत ही कम प्रिमियम के ऊपर यानी 12/-रुपये के ऊपर "दुर्घटना बीमा योजना" लाने की बात हो, चाहे 330/-रुपये पर "जीवन बीमा" की बात हो। जो बड़े-बड़े लोग बड़ा प्रिमियम देकर अपने लिए जीवन बीमा खरीदते हैं उनके समान हमारे समाज का जो पिछड़ा, गरीब और दलित वर्ग है, ऐसे सब लोगों को भी बड़े लोगों के समकक्ष खड़ा करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने ऐसी योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं के कारण आज हमारे तथाकथित छोटे या निचले स्तर के समाज का जो व्यक्ति है, उसको भी बड़े लोगों के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। आज काफी सारी योजनाएं गरीब और पिछड़े लोगों के लिए हैं। जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह अपनी बीमारी को छिपाता है क्योंकि पैसों

का जेब में अभाव होता है और उसके कारण वह गरीब अस्पताल जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। अगर कोई हिम्मत करके अस्पताल जाते भी हैं तो वे अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं या साहूकारों के पास गहने रखते हैं और जब तक वे लोग अस्पताल से वापिस आते हैं तब तक साहूकारों का मीटर जो घूमता है, उसको भी हम सब लोग भली-भांति जानते हैं। इसलिए इस सारे दर्द को देश के प्रधान मंत्री जी ने समझा और उनके लिए "आयुष्मान भारत" जैसी योजना लाए जिससे आज देश का छोटे-से-छोटा और गरीब-से-गरीब व्यक्ति भी बड़े-से-बड़े अस्पताल में अपना उपचार करवा सकता है। यह अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने और आगे बढ़ाते हुए, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो या गृहिणी सुविधा योजना हो, को चलाकर आज 276000 परिवारों को गैस का कनैक्शन पहुंचाया है। इतना ही नहीं जब एक सिलेण्डर उनका समाप्त होगा तो दूसरा सिलेण्डर जो रिफिल होगा, वह भी प्रदेश की सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी बजट में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर और परिवार भी ऐसे सामने आएंगे, जैसे परिवारों से अलग-अलग और परिवार बनते जाते हैं तो उनको भी यदि रसोई गैस की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें भी प्रदेश सरकार फ्री में कनैक्शन देगी। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का संकल्प है। इन्होंने एक साल के भीतर-भीतर इसको करके दिखाया है और हिमाचल प्रदेश को देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की है जो धुंआ-मुक्त राज्य बना है। महोदय, हिमाचल प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना प्रधान मंत्री जी ने चलाई और प्रधान मंत्री जी के साथ हमारे

11/03/2020/1520/MS/YK/2

तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस योजना को साकार रूप दिया, जिसके कारण आज 60 करोड़ लोगों को इसका लाभ देश के अंदर पहुंच रहा है। यह इतनी आबादी है कि अमरीका जैसे देशों की जनसंख्या भी अगर मिला दें तो उतनी जनसंख्या नहीं बनेंगी जितनी संख्या में आज भारत के लोग "स्वास्थ्य बीमा योजना" का लाभ ले रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने इस योजना को हिमाचल प्रदेश में और आगे बढ़ाते हुए यह ऐलान किया है कि मेरे प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गरीब है जिसके पास

पैसा नहीं है और वह उपचार नहीं करवा सकता है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का इस योजना के अंदर आएगा। साथ में यह कहा कि छोटे-से-छोटे और गरीब-से-गरीब व्यक्ति के अलावा मध्यम वर्ग का व्यक्ति या जो इन्कम टैक्स अदा करता है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। उनको केवल 1000/-रुपये प्रिमियम के रूप में एक साल के देने होंगे। उनके परिवार के सदस्य भी पांच-पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं। इतनी बड़ी योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाई है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है।

महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 90 प्रतिशत लोग हमारे गावों में रहते हैं और अधिकतर लोग किसान हैं इसलिए जब तक किसान का विकास नहीं होगा, किसान की उन्नति नहीं होगी, तब तक किसी भी देश या प्रदेश का विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे किसानों की आय जो प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है,
जारी जे0के0 द्वारा----

11.03.2020/1525/JK/AG/1

श्री राजिन्द्र गर्गः----------जारी----

माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाई है, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि 90 प्रतिशत हिस्सा हमारा गांवों में रहता है और अधिकतर लोग किसान हैं, जब तक किसान का विकास नहीं होगा, किसान की उन्नति नहीं होगी तब तक किसी प्रदेश या देश का विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के अन्दर हमारे किसानों की आय जो प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक दो गुणी हो, इसके लिए कृषि कोष योजना चला कर जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 20 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने का एलान किया है, उसके लिए भी हम माननीय मुख्य

मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्दर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हींग व केसर जैसी खेती के लिए कदम उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हींग व केसर अच्छी इन्कम वाली फसलें हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के अन्दर इन चीजों को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित रूप में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक रूप से बहुत बड़ी छलांग होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बजट में जब चर्चा आई तो हमारे विपक्षी बन्धुओं ने कर्ज़े की बात कही कि कर्ज़ा लिया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि कर्ज़ा लिया जा रहा है, यह बोल कर बात नहीं बनेंगी। अगर हिमाचल प्रदेश को स्वावलम्बी बनाना है,हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए कुछ सार्थक कदम भी उठाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के अन्दर हींग व केसर जैसी खेती की बात कही गई है, ये बहुत ही अच्छे कारगर कदम सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभापति महोदय, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो प्राकृतिक खेती है, उस प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। पिछले वर्ष ही हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 60 हजार किसान अगर प्राकृतिक खेती करने के लिए कदम उठाते हैं तो वह कोई

11.03.2020/1525/JK/AG/2

छोटी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश होने के बाद अगर एक वर्ष के भीतर-भीतर 60 हजार किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे कुछ बन्धु प्राकृतिक खेती कह कर मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन केवल किसी बात को या समस्या को उठाना यही काफी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे सामने कोई समस्या है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के अन्दर छोटी-छोटी उम्र के बच्चों को, छोटी-छोटी उम्र के लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हिमाचल प्रदेश में ग्रसित कर रही हैं। तरह-तरह की खबरें आज हम सुनते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी दूषित खेती है, रसायन की खेती है, वह सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अगर इन सारी बातों को फेस करना है, इन

सारी बातों को चुनौती के रूप में स्वीकार करना है तो हमें सार्थक कदम उठाने बहुत आवश्यक है। इसलिए प्राकृतिक खेती का जो मुद्दा है, प्राकृतिक खेती जैसा जो कदम है, जो हिमाचल प्रदेश के अन्दर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों का रूझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। आवश्यकता है कि ज्यादा-से-ज्यादा किसानों को इसके लिए मोटिवेट करने की आवश्यकता है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा इसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट सुरक्षित रखना यह एक अहम बात है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। हिमाचल प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की जो प्राकृतिक खेती है, इसके लिए जो एक साल का लक्ष्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लाख किसानों तक पहुंचाने का रखा है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

11.03.2020/1530/SS-AS/1

श्री राजिन्द्र गर्ग क्रमागत :

माननीय सभापति महोदय, जब हमारे प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती का अभियान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो चुनौतियां आज हमारे समाज में हैं जिसके कारण लोगों को तरह-तरह की बीमारियां ग्रसित कर रही हैं और खेती-बाड़ी हमारी महंगी हो रही है, हमारा किसान केवल सब्सिडी की ओर देखता है, उसकी धारा को मोड़ने के लिए आज प्राकृतिक खेती करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो लोग आज प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वे बहुत अच्छे ढंग से आज अपनी उपलब्धि और सफलता को अन्य मंचों पर बखूबी बता रहे हैं तथा वे गर्व से कहते हैं कि हमको इस खेती का लाभ हो रहा है। हमारी बचत हो रही है और हमारी इन्कम भी बढ़ रही है जोकि हमारा लक्ष्य है।

महोदय, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा आगामी बजट के लिए 1024 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है वह भी विभिन्न सिंचाई योजनाओं

को आगे बढ़ाने और नयी-नयी योजनाएं चलाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। तभी हमारे किसानों की आय बढ़ेगी।

सभापति महोदय, इसी प्रकार बागवानी के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2020-21 के लिए 536 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों को अच्छी किस्म के फलदार पौधों लगाने की ओर रुझान बढ़ाने की आवश्यकता है। उसमें हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों को दूध के ऊपर दो रुपये समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की है। उसके कारण भी हमारे किसानों को प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं।

सभापति महोदय, आज बेरोज़गारी हमारे प्रदेश के अंदर एक चुनौती के रूप में है और इसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है। लेकिन केवल चर्चा करने से और सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने उठाये हैं। महोदय, चुनौती ज़रूर है लेकिन कहा गया है कि :

11.03.2020/1530/SS-AS/2

"कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होता है,
एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो।"

यह पत्थर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उछाला है और निश्चित रूप से जो बेरोज़गारी की समस्या है उसको हल करने के लिए इंवैस्टर मीट जैसा एक कदम उठाया है। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक दिशा दी है, एक संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोज़गार हेतु जो कदम उठाये जा रहे हैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कितने प्रयास किये हैं। उसकी वजह से आज लगभग 13000 करोड़ रुपये की इंवैस्टमैंट धरातल पर आई है वह भी अपने आप में इंवैस्टर मीट की एक बहुत बड़ी सफलता है। आने वाले समय में भी इसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं।

महोदय, इसके साथ ही स्वावलम्बन योजना बेरोज़गारों के लिए शुरू की।

श्री राकेश पठानिया, सभापति : माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

श्री राजिन्द्र गर्ग : स्वावलम्बन योजना हिमाचल प्रदेश की एक बहुत अच्छी योजना है। जिसके कारण हमारे प्रदेश के युवाओं को इधर-उधर भटकने के बजाय अपने घरद्वार पर उद्योगों के यूनिट लगाकर, छोटे-मोटे कारोबार करके जो मुख्य मंत्री की सोच है कि वह नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, उसमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे छोटे-से-छोटे तबके को, चाहे वह मिड डे मील वर्कर है, चाहे वह जलवाहक है, चाहे वह अन्य योजनाओं के अंतर्गत छोटी-मोटी इकाइयों में काम कर रहा है, उन सबका मानदेय बढ़ाने के लिए जो कदम उठाये हैं उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सारे समाज के सभी वर्गों के लिए विचार किया है।

11.03.2020/1530/SS-AS/3

श्री राकेश पठानिया, सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री राजिन्द्र गर्ग : महोदय, जो हिमकेयर योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाई है उसका लाभ आज हजारों लोगों को मिल रहा है और विशेष करके जो सहारा योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है उसमें भी अब उन्होंने जो 2000 रुपये ऐसे बन्धुओं को मिलता था, उसको 3000 रुपये कर दिया है।

जारी श्रीमती के0एस

11.03.2020/1535/केएस/एएस/1

श्री राजिन्द्र गर्ग जारी---

इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि

आने वाले समय में इस प्रस्तुत बजट में प्रदेश का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2020/1535/केएस/एएस/2

सभापतिः अब श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2020-21 का जो बजट इस माननीय सदन में 6 मार्च, 2020 को पेश किया, मैं उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश की जनता को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के 50वें वर्ष के अवसर पर दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया और आज हिमाचल प्रदेश राज्य की गणना अगर विकसित राज्य के रूप में हो रही है तो उसमें कांग्रेस सरकार का भी योगदान है। हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के 50वें वर्ष पर वर्ष 2020-21 को हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कहा गया कि पहाड़ी राज्य की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश role model State के रूप में विकसित हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा प्रदेश role model State विकसित हुआ है तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकारें रही हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे यशवन्त सिंह परमार जी हों, राम लाल ठाकुर जी हों, राजा वीरभद्र सिंह जी हों, भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार जी या धूमल जी हों, जितने भी मुख्य मंत्री यहां पर रहे हैं, उन सभी का इसमें योगदान रहा है। क्रेडिट लेना कि यह सब कुछ दो सालों में ही हुआ, मुझे लगता है कि यह तर्कसंगत नहीं है। इसी तरह यहां पर कहा गया कि प्रशासनिक व्यवस्था में structural परिवर्तन हुए हैं एवम् work culture में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। लेकिन जब हमारे लोग प्रशासनिक अधिकारियों के पास काम करवाने के लिए जाते हैं,

चाहे एस.डी.एम. लैवल की बात हो, जिलाधीश लैवल की बात हो, उनको वहां बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और तब भी काम नहीं होता। तो इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए ताकि जनता के काम हो सके।

11.03.2020/1535/केएस/एएस/3

सभापति महोदय, यहां पर कहा गया कि वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जीत हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं के कारण नहीं हुई। यह नरेन्द्र मोदी के नाम से जीत हुई है। यहां पर कहा गया कि हमारे जो दो उप-चुनाव थे, उनमें हमारी जीत हुई। यह खुशी की बात है क्योंकि जो जीत कर आए, ये भी हमारे साथी ही हैं। अच्छी बात है लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह लगता है कि यह जीत उनके कारण हुई है तो ये गलत फ़हमी में हैं।

सभापति महोदय, यहां पर जनमंच की बहुत चर्चा की गई कि जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जनमंच किए गए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी 4 जनमंच किए गए। ठाकुर महेन्द्र सिंह जी, नरेन्द्र ब्राक्टा जी, सरवीन चौधरी जी और सुरेश भारद्वाज जी वहां पर आए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2020/1540/AV-AS/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा-------- जारी

वहां पर लोग बड़े उत्साह के साथ आए मगर बाद में लोगों के हाथों निराशा लगी। वहां पर बहुत बातें की गईं, लोगों के काम करने की बातें की गईं। मगर बाद में जनता के कार्यों को वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने गम्भीरता से नहीं लिया और लोगों के काम नहीं हुए। यहां पर सी0एम0 हैल्पलाइन और ई-समाधान के लोकप्रिय होने की बात की गई, मगर

वास्तव में ग्राउंड में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर धर्मशाला में आयोजित हुई इंवैस्टर मीट की बात भी की गई जिसमें बताया गया कि जब प्रधान मंत्री मोदी जी यहां पर आए थे तो उन्होंने यह कहा था कि "मैं मेहमान नहीं हूं , आप लोग मेरे मेहमान हैं और मैं हिमाचल का रहने वाला हूं"। इसमें कोई दो राय नहीं है; मोदी जी हिमाचल प्रदेश के काफी लम्बे समय तक प्रभारी रहे हैं इसलिए उनकी यह बात ठीक है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हमारे प्रदेश में तीन बार आए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार उनसे कोई नया पेकैज नहीं ले पाई। इंवैस्टर मीट के दौरान यहां पर कितना निवेश हुआ; आप लोग उसकी भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह दृष्टि पत्र को सरकार का नीति दस्तावेज़ मानकर विकास को आगे बढ़ाने की जो बात की गई है। उस दृष्टि पत्र में जो कहा गया है उसके संदर्भ में तो इसमें काफी कम बातें सम्मिलित की हैं। अगर आपने दृष्टि पत्र लाँच किया है तो उन बातों के ऊपर सरकार द्वारा गौर किया जाना चाहिए तथा वे बातें पूरी होनी चाहिए। यहां पर नशे के बारे में ज़ीरो टोलरैंस की बात कही गई है। लेकिन नशा हिमाचल प्रदेश में दिन-रात पैर पसार रहा है और हमारे नौजवान नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं। हमारे बी0बी0एण्ड डी0ए0 में चिट्टा, अफीम, भुक्की, चरस, गांजा इत्यादि नशे की चीजें मिलना आम बात हो गई है। उसके ऊपर किस ढंग से अंकुश लगे; सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के नशे के कारोबारी हिमाचल प्रदेश की ओर अपने पैर पसारते जा रहे हैं तथा हमारे नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है। इसलिए उनको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में नशा छुड़ाने के

11.03.2020/1540/AV-AS/2

लिए बहुत सारे नशा निवारण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे नालागढ़ में भी खोले गए हैं मगर उनको भी चैक किया जाना चाहिए कि वे नशा लगा रहे हैं या छुड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त जांच होनी चाहिए जो इस तरह के गलत कार्य कर रहे हैं। यहां पर विधायक प्राथमिकता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 105 करोड़ रुपये से

बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया गया है, यह अच्छी बात है और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। इससे हमारे विधायकों की सिंचाई, पेयजल, सड़कें या बिजली बोर्ड से संबंधित कार्यों की बहुत सारी योजनाएं पूरी होंगी और इनसे आम जनता को लाभ होगा। इसी तरह से विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी 1.50 करोड़ रुपये से 1.75 करोड़ रुपये किया है; हम इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य से हमारा लोकतंत्र मज़बूत हुआ है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक निधि को भी 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है; यह भी अच्छी बात है। विधायक अपनी ऐच्छिक निधि से गरीब, बीमार या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकता है। इसके अलावा यहां पर सामाजिक पेंशन की बात की गई है जिसके अंतर्गत विधवा, वृद्ध, दिव्यांग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वॉटर गार्ड, फीटर और पंचायत चौकादारों का मानदेय 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया है, यह भी अच्छी बात है। इनके मानदेय में डेढ़ सौ रुपये की वृद्धि हुई है परंतु यदि इसमें दो सौ रुपये की वृद्धि होती तो ज्यादा अच्छी बात होती। मगर जो किया है वह भी ठीक है, गरीब लोगों के लिए किया है, अच्छा किया है; हम इसकी भी प्रशंसा करते हैं।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2020/1545/TCV/DC-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा.... जारी

लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी पंचायत के जो प्रधान, उप-प्रधान, मैंबर, बी.डी.सी., जिला परिषद् के सदस्य, म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान, मैंबर हैं, उनको भी कुछ-न-कुछ राशि पेंशन के रूप में मिलनी चाहिए। वे भी समाज में दिन-रात काम करते हैं, चुनाव हारना-जीतना अलग प्रक्रिया है लेकिन उनको सम्मान राशि के रूप में कुछ-न-कुछ मिलना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा व्हीकल ट्रकिंग डिवाइस महंगे दामों पर लगाये जा रहे हैं और लोगों से 15000-16000 रुपये वसूले जा रहे हैं। जबकि दूसरे राज्य में 4000-5000 रुपये में वह डिवाइस लग जाती है। इस प्रकार की मनमानी पर रोकथाम लगाना

बहुत ज़रूरी है। मेरे नालागढ़ डिपो में 117 बसें हैं जबकि हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पर 4-5 लाख की आबादी हैं। वहां पर रोज़गार के लिए लोग बाहर से आये हुए हैं इसलिए वहां पर बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 22 बसें ऐसी हैं जो 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुकी हैं, वे बसें कंडम होनी चाहिए। इसी तरह से ड्राइवर 145 हैं और कंडक्टर 130 हैं जबकि ड्राइवर 167 और कंडक्टर 160 के करीब होने चाहिए। बसों के कुछ नये रुट मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किए जाने चाहिए। जिनमें नालागढ़-गुरुकुंड-जाबल-टपरियां-पहाड़ी चिकनी तथा साईं तक नई बस सेवा शुरू की जानी चाहिए। दूसरा, बघेरी-कालीबाडी-बटोली-अभीपुर-गुलरवाला तक नई बस सेवा लगाई जाये। इसी तरह से रामशहर-ज्यौरा-गरलोह-मितियां के लिए भी नई बस सेवा शुरू की जाएं। मेरे नालागढ़ ब्लॉक में मनरेगा का बहुत-सारा बजट लैप्स हो गया है। इसमें किसकी कमी रही, यदि बी.डी.ओ. की कमी रही तो उसके खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोग रोज़गार मांग रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और पैसा लैप्स हो रहा है। यहां पर चण्डीगढ़ से बद्दी के लिए रेल चलाने की बात कही गई है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो रेल की योजना बद्दी तक है इसको नालागढ़ तक किया जाना चाहिए क्योंकि सारी आबादी नालागढ़ तक फैली हुई है। नालागढ़ से आगे अगर आप इसको घनौली तक ले

11.03.2020/1545/TCV/DC-2

जाएंगे तो वहां पर पहले ही रेल लाइन का ट्रैक बना हुआ है और ज़मीन भी रेलवे विभाग के नाम हैं। अगर इस तरह से रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा तो हमारे गरीब किसानों व मज़दूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। बी0बी0एन0डी0ए0 में हैलीपोर्ट है, वहां पर एयर पोर्ट बनना चाहिए क्योंकि वहां पर 2600 से ज्यादा फैक्टरियां हैं। यदि वहां पर एयरपोर्ट बनता है तो जो इंडस्ट्रिलिस्ट्स हैं, आम लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा। 'मुख्य मंत्री आर्दश ग्राम योजना' के तहत ग्राम पंचायत मंझोली के गांव लखनपुर, ग्राम पंचायत लुनस के ग्राम बाड़ा व चिरंगी के लिए 15-15 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे लेकिन

अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र दिया जाये। बी0बी0एन0डी0ए0 में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, वहां हर दिन चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे अप्रिय घटनाएं होती रहती है। इसका कारण यह है कि वहां पुलिस बल बहुत कम है। बी0बी0एन0डी0ए0 में जो एस0डी0ओ0 लगे हुए हैं,उनको ही चैक करने की ऑथोरिटी है और पार्टियों को चैक भी वही देते हैं। अगर आप उन लोगों को वहां पर रखेंगे तो वहां पर कार्य की क्वालिटी ठीक नहीं होंगी। इसलिए उनको कहीं अन्य जगह भेजा जाये ताकि काम सही ढंग से हो सके। बड़े दुःख की बात है,

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी ।

11.03.2020/1550/RKS/HK-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा... जारी

हम कहते हैं कि 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ'। नालागढ़ क्षेत्र में एक आशा नाम की लड़की आई.टी.आई. में ट्रेनिंग करती थी जिसने 11 जुलाई, 2019 को आई.टी.आई. से निकलकर नहर में छलांग लगा दी। उसने सुसाइड नोट में आई.टी.आई. प्रबंधन पर आरोप लगाए लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसके लिए एस.आई.टी. गठित की जाए ताकि दोषियों के ख़िलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। यहां पर यह बात की गई कि 10 डैडिकेटिड माइनिंग चैक पोस्ट स्थापित की जाएगी। माननीय उद्योग मंत्री जी हमारे मित्र हैं और यह आपकी अच्छी सोच है। यहां पर बार-बार खनन का मुद्दा उठता है और आप चाहते हैं कि खनन को जड़ से खत्म किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन जोरों पर हो रहा है। नालागढ़ में सारी नदियां छलनी कर दी गई हैं और 20-25 फुट तक नीचे चली गई हैं। वहां पर पुलिस और माइनिंग विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अवैध खनन की रोकथाम हेतु सख्त कदम उठाये जाएं। एक ट्रैक्टर को 15,000 रुपये और एक ट्रक को 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जाना चाहिए

ताकि अवैध खनन पर जो अंगुलियां उठ रही हैं, वे उठना बंद हो जाएं। सरकारी संस्थानों में बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। उद्योगों में भी हमारे बेराजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार ने कहा था कि उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचल के लोगों को दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए विधान सभा की ओर से एक कमेटी का गठन किया जाए और वह कमेटी चैक करे कि जो उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को देने का कानून बनाया गया है, क्या वे कंपनियां उस क्राइटेरिया को पूर्ण कर रही हैं या नहीं? यदि, नहीं तो उन कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को क्राइटेरिया के हिसाब से रोजगार के साधन उपलब्ध हों।

11.03.2020/1550/RKS/HK-2

वर्ष 2012-2017 में जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल व कॉलेज खोले गए। अगर हम यह चर्चा करें कि यह स्कूल, कॉलेज गलत खुले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि स्कूल और कॉलेज जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और यह सुविधा जनता को मिलनी चाहिए। जो बहुत सारे शिक्षा संस्थान खोले गए थे उसके लिए हम पूर्व सरकार की तारीफ करते हैं। पूर्व सरकार के समय कई एस.डी.एम. ऑफिस, तहसीलें, और सब-तहसीलें भी खोली गई हैं।

नालागढ़ में एक चंगर एरिया है और मेरी सरकार से मांग है कि उस एरिया में एक कॉलेज खोला जाए। इस क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं खुला है और कॉलेज खोलने से वहां 20-25 पंचायतों को फायदा होगा।

'हिम केयर योजना के तहत 68,222 लोगों को लाभ बताया गया', 'सहारा योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति देने की बात की गई', 'आयुष्मान भारत योजना में 52,992

लोगों को 53 करोड़ रुपये की दवाइयां देने की बात कही गई'। '10 मोबाइल हैल्थ सैंटर खोलने की बात कही गई'। प्रदेश में 108 एम्बुलैंस की संख्याः 198 हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है इसलिए 108 एम्बुलैंस की संख्या को और बढ़ाया जाए ताकि लोगों को इनको फायदा मिल सके। जब वर्ष 2016 में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने नालागढ़ क्षेत्र में एक ट्रॉमा सैंटर खोलने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक वह ट्रॉमा सैंटर नहीं खोला गया है। जब लोगों के एक्सिडैंट होते हैं तो उन्हें उपचार हेतु पी.जी.आई. जाना पड़ता है। आधे आदमी तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर जल्द-से-जल्द ट्रॉमा सैंटर खोला जाए। इसी तरह वर्धमान फैक्टरी ने सी.एस.आर. के तहत 65 लाख रुपये नालागढ़, अस्पताल के इमरजंसी वार्ड को मॉडर्न बनाने हेतु स्वीकृत किया था लेकिन अभी तक उस पैसे की स्वीकृती नहीं हुई है। उस पैसे की स्वीकृति आनी चाहिए ताकि उस वार्ड का काम पूर्ण हो सके।

11.03.2020/1550/RKS/HK-3

सभापतिः माननीय सदस्य आपका सारा विषय आ गया है, कृपया वाइंड-अप करें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष जी, नालागढ़ में सड़कों की हालत बहुत खराब है। मेरी सरकार से मांग है कि कि गर्मियों के दिनों में नालागढ़ क्षेत्र की सभी सड़कें ठीक करवाई जाए। यहां पर 69 नेशनल हाइवेज की बात की गई। मेरे नालागढ़ क्षेत्र में भी दो 2 नेशनल हाइवेज पड़ते हैं। एक घनोली-नालागढ़ वाया रामशहर- कुनिहार- शिमला।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

11.03.2020/1555/बी.एस./एच.के./-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा जारी...

दूसरा-भरतगढ़-पंजैरा-ब्रूना-बझेरी-गरामूड़ा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर काम जल्द शुरू किया जाए। जो पंचायतों की सड़के हैं उनको भी लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेना चाहिए ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कत न हो।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें, (घण्टी)।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : सर, मैं एक एक्स-सर्विस मैन के बारे में जरूरी बात करना चाहता हूं। हमारे नालागढ़ क्षेत्र में 3000 हजार के करीब इनकी संख्या है। उनको कालका आर्मी कंटीन के लिए जाना पड़ता है। उनके लिए भी नजदीक से व्यवस्था की जाए। हमारे वहां सामुदायिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध है, पीछे आदरणीय परमजीत सिंह पम्मी जी ने भी उसके लिए पांच लाख रुपए दिए थे मैंने भी पैसे दिए थे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उसके लिए पैसा भी दे और केन्द्र सरकार एक्स-सर्विस मैन समुदाय भवन बनाने के लिए पैसा प्रदान करें और जो आर्मी कंटीन है उसके लिए भी रक्षा मंत्री जी से बात करें।

मैं यहां पर पैट की बात करना चाहता हूं, वर्ष 2003 से ले करके वे कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। जे.बी.टी. की ट्रेनिंक सरकार ने करवाई है परंतु उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है न ही पी.टी.ए. के लिए कोई पॉलिसी बनी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनका शोषण न किया जाए। एक अच्छी पॉलिसी इनके लिए बने ताकि ये अपनी सेवाएं अच्छे ढंग से दे सकें। यहां पर आउट सोर्स की बात हुई है। जो यहां पर बजट पेश किया गया है इसमें मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें, (घण्टी) बहुत हो गया सारी बातें आपकी इसमें आ गई है।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : सभापति महोदय, आपने समय से पहले ही घण्टी बजा दी है। परंतु कोई बात नहीं आप हमारे पुराने साथी हैं। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2020/1555/बी.एस./एच.के./-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह (चिंतपूर्णी) : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपना तीसरा बजट कर मुक्त पेश किया, मैं आपके माध्यम से उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री द्वारा यह जो बजट पेश किया गया है यह धरातल पर ठीक उतरने के लिए, गरीब का उत्थान करने के लिए और उनके हित में नई-से-नई योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछली दो वर्ष की योजनाएं हैं उन योजनाओं को और सुदृढ़ करके गरीबी दूर करने के लिए इस बजट में इन्होंने काफी कुछ दिया है मैं इन सब के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक नेता प्रतिपक्ष जी बजट की चर्चा पर हिस्सा लेते हुए अपनी बात रख रहे थे सुने के बाद मुझे लगा कि वे ख्याली पुलाव में रहते हैं, कल्पनाओं की बात करते हैं, आशंकाओं की बात करते हैं परंतु बजट में यदि कोई आलोचना की बात करनी हो तो उसे भी नहीं करते हैं। उनका कहना था, क्या होगा, कहां से कितना पैसा आएगा, कौन ले करके आएगा? जैसे उन्हें लगता है कि यह जो सरकार चल रही है यह बिना पढ़े लिखों की ही है और इसे आता ही कुछ नहीं है। सारा कुछ उन्होंने इस तरह से पेश किया। मैं जानता हूं कि वे मेरे भाई, जिला ऊना के हैं। वे अपने आपको काबिल भी समझते हैं और होने भी चाहिए। परंतु मैं समझता हूं कि वे अपने दल में ही प्रतिस्पर्धा में फसे हुए हैं, वे अपनी प्रतिस्पर्धा को आगे करने के लिए यहां पर जो बातें रखते हैं वे उनकी अपनी होती हैं और हमें सुनाते हैं। मैं उनको सचेत करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में काबिलियत की कोई पूछ नहीं है। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ है, वह इनके साथ भी हो सकता है। यह सच्चई है यह कोई झूठी बात नहीं है।...(व्यवधान) मैडम वे भी बजट से परे की बाते कह रहे थे, कृपया मुझे भी तो थोड़ा बोलने दीजिए, मुझे भी अधिकार है, मैं उन्हें सचेत कर रहा हूं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया चेयर को संबोधित करें।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

11.03.2020/1600/DT/ YK -1

श्री बलबीर सिंहः सभापति जी, मै उनको सचेत कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में कोई काबिल आदमी को नहीं पूछता। वह हमारे ऊना के भाई हैं इसलिए मैं उनको सचेत कर रहा हूं। सभापति महोदय, उन्होंने वित्तीय अराजकता की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय अराजकता फैली है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वित्तीय अराजकता उस वक्त थी जब किसी निजी एजैंसी से कर्ज लेने के लिए किसी निजी व्यक्ति को कमीशन दिया जाता था और यह कांग्रेस पार्टी करती रही है। आप कर्ज के लिए हमारे को क्या सीखा रहे हैं? इस प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो कर्ज लेना होगा। आज पंजाब की बात करो तो लगभग पौने दो लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा कर्ज वहां की सरकार के ऊपर है। माननीय आशा कुमारी जी वहां की प्रभारी हैं। मैडम जी, आप पता कर लेना यह झूठी बात नहीं है। हरियाणा के ऊपर भी कर्ज है, हर प्रदेश के ऊपर कर्ज है ...(व्यवधान) आप भी उसी में शामिल हैं, आप बाहर नहीं हैं, आप दूर नही हैं। ...(व्यवधान) आपकी सरकार ज्यादा कर रही है। हर प्रदेश पर कर्ज है।

सभापतिः माननीय सदस्य कृपया चेयर को अड्रैस करें।

श्री बलबीर सिंहः हर प्रदेश अपने प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए कर्ज उठाता है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को भी कर्ज उठाना पड़ता है। जो वित्तीय अराजकता वाली बात इन्होंने कही है मैं इसको झूठलाता हूं। अगर कहीं अराजकता हुई है तो वह इनके राज में हुई है। इन्होंने निजी एजैंसियों को कमीशन दे करके इस देश और और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, मैं उसकी आलोचना करता हूं। सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि Kangra Co-operative Bank खत्म हो गया, वह एन.पी.ए. में चला गया। हम समझते हैं कि वह एन.पी.ए. में कब गया? इस समय को भी हमें याद रखना होगा। मेरे ऊना गगरेट में एक इंडस्ट्री जिसको बिना नियमों के, नियमों को ताक पर रखकर 19

करोड़ के करीब कर्जा दिया गया। मैंने उससे पूछा की आपको कर्जा कैंसे मंजूर हो गया, गरीब आदमी को कर्ज नहीं मिलता है, आपने यह कैसे कर लिया? उसने सीधे-सीधे कहा की जो अध्यक्ष हैं उनके रिस्तेदार मेरे साथ सांझी हैं। मेरे चिंतपूर्णी विधान साभ क्षेत्र में एक Co-operative Society में साढ़े आठ करोड़ रुपये का घपला है। मैंने पूछा कि यह घपला कब हुआ? यह ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष के समय हुआ था। अंधे हो कर हमारे

11.03.2020/1600/DT/ YK -2

लिए बंदर बाट का नाम लेते हैं जबकि यह खुद बंदर बांट करते रहे हैं। 11 करोड़ 70 लाख रुपये का घपला दियोली गगरेट चुनाव क्षेत्र में हो गया है। वह भी जब हुआ तब इनकी पार्टी का व्यक्ति मीडिया प्रभारी का अध्यक्ष बना। नियमों को तोड़ करके, नियमों को ताक पर रख कर जब उस सोसायटी का अध्यक्ष बना तो 11 करोड़ 70 लाख रुपये का घपाला हो गया। सभापति महोदय, ये सब कुछ करवाते हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि ये उधर जा कर कैसे ज्ञानवर्धन हो जाते हैं। जब यहां होते हैं तो यह ज्ञान कहां होता है? यह सारी बातें अगर कोई इतिहासकार लिख रहा होगा तो वह अपने इतिहास में लिखेगा कि जब-जब भी कोई बड़ा घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं बरती गई हैं तो वे कांग्रेस के वक्त में बरती गई हैं। उच्च मार्ग की बात भी यहां पर कही गई है। यह कहा गया कि 65 हजार करोड़ रुपये कहां गया? यह हमारे मंत्री ने घोषणा की है और हम इन नेशनल हाइवेज को धरातल पर लाएंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं कि आप गगरेट और चिन्तपूर्णी में घूम कर देख लो। चिन्तपूर्णी में भरवाईं से लेकर टैरस तक नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवाया था। नैश्नल हाईवे से पैसे लिये बिना हमने सी.आर.एफ. के तहत इतना अच्छा रोड़ बना कर दिया है। जो आपके समय के विधायक थे वे तो मंत्री को बुलाते ही नहीं थे। वे कहते थे कि मंत्री न तो गगरेट आये और न ही चिन्तपूर्णी आये। हम कहते हैं कि आप आइए और आपका स्वागत है। जब आप मुबारकपुर से तलवाड़ा की ओर जाएं तो जो दौलतपुर नेशनल हाईवे था वहां पर भी अच्छा काम हो गया है। जो रोड काहलुवाल से लेकर दौलत पुर चौक तक था वह रोड नेशनल हाइवे से भी बढ़िया है। ऐसी तीन सडंकें तो मैंने ही निकाल दी हैं। जो आप 70,69 ,65, सड़कों की चर्चा करते हो, 25 सड़कों की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है और तीन मैंने अपने चुनाव क्षेत्र की

बता दी है। सभापति महोदय, एक बद्दी में सैंटर की चर्चा हो रही है। हमने एक सैंटर बनाया और आपने उसे पौने 2 लाख में एक लाले को दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका विजन क्या था? उस सैंटर को बनाने के लिए आपकी दूर-दृष्टि क्या थी? यह सैंटर किस लिए बनाया था? आपने हरोली में भी ऐसा ही किया। खड्ड में करोड़ों रुपये का एक बहुउद्देश्यीय भवन बना दिया गया और उसकी चाबी एक वर्कर के पास दे दी गई। वहां पर कोई आदमी नहीं रहता है और न ही उस भवन को कोई किराये पर लेने को तैयार है।

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

11-03-2020/1605/वाई.के.-एन.जी./1

श्री बलबीर सिंह जारी.....

अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री कांगड़ गए थे वहां पर टूरिज्म का सैंटर ऐसी जगह पर बना दिया गया है जहां पर टूरिस्ट जा ही नहीं सकता। टूरिस्ट उस रास्ते से आता भी नहीं है और वहां पर इनके द्वारा फ़िजूल पैसा खर्च किया गया है। लेबर डिपार्टमैंट के नाम पर करोड़ों रुपये का भवन हरोली में बना दिया गया जिसके लिए इनका कोई विज़न ही नहीं था कि इस भवन का क्या करेंगे। जब हमारी सरकार आई और हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि उस भवन को किराए पर लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है और उस भवन का क्या किया जाए, उसमें किसको बिठाया जाए। बहुत विचार करने के बाद हमने कहा कि इस भवन को कामगार लोगों को जो मशीनें या अन्य कोई सामान देते हैं उसके सामान के लिए स्टोर बना दिया जाए। सभापति महोदय, उसका भी किराया ज्यादा पड़ रहा है यदि मुझे हरोली से कोई सामान लाना हो तो उसके लिए गाड़ी का किराया ही बहुत ज्यादा पड़ता है। अपने आप इनका कोई विज़न नहीं था और पांच साल बिना विज़न के ये लोग काम करते रहे। इन्हें बद्दी की बहुत अधिक चिंता हो रही है कि हमारा सैंटर लाला जी को पौने दो लाख रुपये में दे दिया। भ्रामक बाते करना, झूठी बात पर सनसनी क्रिएट करना इनकी आदत में शुमार है। सभापति महोदय, ये लोग कोई भले वाली बात नहीं करते और

बार-बार कह रहे हैं कि उद्योग खिसक रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब यह मंत्री थे उस समय चिन्तपूर्णी और गगरेट में 16 फैक्टरियों को तारपीन का तेल बनाने के लिए लगाया गया था और 16 में से 1 भी नहीं चली जोकि इनके समय में ही भाग गई थी। वर्धमान ग्रुप हिमाचल में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता था और उस समय माननीय मंत्री जी और उनके पी.ए. पर आरोप लगे थे कि वे कमीशन मांगते हैं, जिस कारण वह इंडस्ट्री नहीं लग पाई। हीरो होण्डा भी यहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहता था वह भी यहां से चली गई।

11-03-2020/1605/वाई.के.-एन.जी./2

गगरेट में शुगर मिल लगाने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री एक डाकु को पकड़ कर ले आए और उससे वहां पर किराए में कमरे दिलवा दिए उसके बाद वह लोगों से पैसा लेकर भाग गया और शुगर मिल कागज़ों में ही चलती रही।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गरीब से लेकर हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आदरणीय सिंघा जी यहां पर बैठे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि श्री सिंघा जी और इनका दल बहुत मेहनत करता है। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साहयिका की सैलरी 100 रुपये भी बढ़ानी हो तो ये लोग माननीय हाई कोर्ट से लेकर पैदल मार्च करते थे परन्तु फिर भी पैसे नहीं बढ़ते थे। वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने माननीय सिंघा जी का रोज़गार छुडवा दिया है और अब बिना मार्च किए, बिना एजिटेशन किए उन बहनों की सैलरी 500 रुपये बढा दी है जो धरातल पर विकास का काम करती हैं। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिकाओं की सैलरी भी 300 रुपये बढ़ा दी गई हैं और आशा वर्करों की सैलरी भी 300 रुपये बढ़ा दी गई है। इस बजट के माध्यम से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और मैं इस बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं जिसे हम स्वर्ण ज्यन्ति के रूप में मना रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में कोई नए स्कूल खोलने की बात नहीं कही है, कोई नई संस्थाएं खोलने की बात नहीं कही है परन्तु उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं विद्यमान हैं उनमें गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए, लोगों

को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पढ़ाया जाए। ''स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेश्ठ विद्यालय योजना (ज्ञानोदय)'' के माध्यम से 100 स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं देने के लिए प्रस्ताव किया है। इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा विभाग में ही "नई स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना" की घोषणा की गई है

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

11/03/2020/1610/MS/YK/1
श्री बलबीर सिंह जारी-----

और इस योजना के प्रथम चरण में हर विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में जहां पर 500 या उससे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का प्रस्ताव है। वहां पर उन स्कूलों में सारी सुविधाएं देने की बात है। इसके लिए भी 30 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा 9 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रूप में विकिसत करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को पुनः बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा 50 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं चलाने की बात है यानी इसका भी प्रस्ताव है। इसी तरह से सी0वी0 रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना 106 संस्थानों में चल रही है तथा और भी संस्थानों में इसको चलाने का प्रस्ताव है जहां पर अध्यापक कम हैं। जिन महाविद्यालयों में अध्यापक कम हैं, वहां पर डिजिटल एजुकेशन देने का इस योजना के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। B.Voc प्रायोगिक तौर पर 12 महाविद्यालयों में शुरू किया गया है तथा अगले साल से 6 महाविद्यालयों में और शुरू करने की बात की गई है। इसी तरह से स्वर्ण जयन्ती सुपर-100 योजना आरम्भ करने की बात है। इसके तहत दसवीं में सर्वाधिक नम्बर लेने वाले 100 विद्यार्थियों को जो व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए प्रतिस्पर्धा में खर्च नहीं कर सकते थे, जिनको गरीबी आड़े

आती थी, उन 100 बच्चों को 1-1 लाख रुपये अनुदान देने की बात है । इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। शिक्षा विभाग में भी पिछले दो सालों में 10700 अध्यापक भरने की बात की गई है। अभी 4000 अध्यापकों के पद भरे जा चुके हैं और अगले साल लगभग 5000 अध्यापकों के पदों को भरने का प्रस्ताव है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और वर्ष 2020-21 में 8016 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

सभापति जी, आयुष्मान भारत में 52922 लाभार्थियों ने 53 करोड़ रुपये का लाभ लिया है और हिम केयर योजना में 68222 लाभार्थियों ने 63 करोड़ रुपये का लाभ लिया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तड़प रहे थे कि सवा सौ करोड़ रुपये की

11/03/2020/1610/MS/YK/2

तबाही हो गई क्योंकि इतना तो राशन ही नहीं लगता। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मान लो मेरे परिवार का सदस्य गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो क्या 5 लाख रुपये का उपचार ऐसे ही हो जाता है? पी0जी0आई0 में जाकर ईंट भी पैसा मांगती है। वहां पर बहुत खर्च होता है। वहां पर क्या यह देखा जाता है कि हमारा एक साल का इतना राशन नहीं लगता इसलिए इतने पैसे न खर्च किए जाएं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि गरीब की सहायता के लिए अगर सवा सौ करोड़ रुपये की जरूरत है तो इन्होंने खर्च किए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा गरीब पर खर्च हुआ है और यह कोई हेराफेरी वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है कि भ्रामक बातें करना और सनसनी क्रिएट करना इनकी आदत में शुमार है।

सभापति जी, क्षयरोग के उपचार के लिए पहले 1500/-रुपये की सहायता दी जाती थी लेकिन अब इस सहायता को भी आगे बढ़ाने की बात है। पहले हमारे प्रदेश में कैंसर के रोग को चैक करने के लिए बड़े अस्पतालों के अलावा जिला अस्पतालों में कोई मशीन नहीं थी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने मेमोग्राफी मशीन लगाने की बात की है जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। सहारा योजना में लगभग 8188 लोग हैं जिनमें से 5580 लोगों को आपने 2000/-रुपये प्रति मास के हिसाब से उनका सहारा बनने का प्रयास किया है और इस अनुदान को 3000/- रुपये तक अगले साल बढ़ाने का प्रयास है। इसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देता हूं।

सभापति जी, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए; हालांकि इनके मन में कभी कल्पना भी नहीं हो सकती है कि ऐसा भी होना चाहिए लेकिन मुख्य मंत्री जी ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आयुर्वेद की हर दवाई मुफ्त में देने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी 2702 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है और आयुर्वेद विभाग में 307 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इस सबके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मैं सबसे ज्यादा बधाई कृषि कोष के लिए देना चाहता हूं जिसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसमें सभी दलों की एक कमेटी बनाने का

11/03/2020/1610/MS/YK/3

प्रस्ताव है जो देखेगी कि यदि कृषि योग्य भूमि में कोई खेती-बाड़ी नहीं करते हैं, वह व्यर्थ पड़ी है तो वह कमेटी फैसला करेगी कि उन खेतों में भी खेती-बाड़ी की जाए। यह बहुत अच्छा प्रयास है। सभापति जी, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का प्रयास किया भी है। मेरे मित्र ने गांव अकरोट में यह शुरूआत की है। उन्होंने पिछले साल मेडिसनल प्लांट लगाए हैं और लगभग 55 लाख रुपये के पौधे बेचे यानी प्राकृतिक तौर पर पौधे तैयार करके उन मेडिसनल प्लांट्स को बेचा है। आपके नुरपूर और पंजाब में श्तावर और सर्पगंदा के ये पौधे थे। उन्होंने अंजीर के पौधे भी इटली से मंगवाकर वहां पर स्थापित किए हैं।

जे0के0 द्वारा----

11.03.2020/1615/JK/AG/1

श्री बलबीर सिंहः----जारी-------

चाय के पौधे वहां पर लगाए हैं। वे वहां पर बहुत अच्छी खेती-बाड़ी कर रहे हैं। एक और डॉ0 गुलिया जी आए हैं, उन्होंने 600 कनाल जगह जिसमें लोग कुछ भी नहीं बीजते थे, उसको किराये पर ले कर प्राकृतिक आधार पर खेती करने की शुरूआत कर दी है। मैं

सरकार से भी निवेदन करता हूं कि कृषि विभाग को और भी सशक्त किया जाए ताकि वे भी वहां से सीखें। किताबों में पढ़ने से कुछ नहीं होता। वहां जा कर भी देखना पड़ता है कि खेत में किस चीज की जरूरत है, खेत में किस मौसम में कौन सी फसल लगाई जाए। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि अनुसूचित जाति तक के लिए आपने प्रावधान किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो सोचती थी कि हम ही अनुसूचित जाति के खैर-ख्वाह हैं, हमारी पार्टी नहीं है। लोग भूल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 तक गरीबों के लिए मकानों के जितने भी केस लम्बित हैं, उन सभी को मकान देने का प्रस्ताव है। इस देश के प्रधान मंत्री जी चुनौती लेते हैं कि वर्ष 2022 तक किसी भी ऐसे परिवार को जिसकी अपनी छत नहीं है, उसको छत मुहैया करवाएंगे। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी प्रधान मंत्री जी के कदमों के साथ चलते हुए प्रदेश में ऐसा कोई परिवार न छूट जाए जिसका अपना घर नहीं है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार नए अभ्यार्थियों को लाभ देने का प्रस्ताव है। स्वर्ण जयंती आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को 5100 आवास देने का प्रस्ताव है। मुख्य मंत्री आवास योजना में 3100 मकान देने का प्रस्ताव है। प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में 1000 मकान देने का प्रस्ताव है। प्रधान मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में 800 मकान देने का प्रस्ताव है। इसके लिए 160 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं इन सब के लिए मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

11.03.2020/1615/JK/AG/2

अध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री राजेन्द्र राणा जी भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार का यह तीसरा बजट है। मैंने पिछले दोनों बजट पर भी नज़र दौड़ाई है। ठीक है, कुछ नई चीजें पेश करने की कोशिश हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो बजट है यह cut & paste की तरह पेश किया गया है। पुराना जो बजट है, पुरानी जो प्रथा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। कहते हैं कि:

नए किरदार आते जा रहे हैं,

मगर नाटक पुराना चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बजट बुक को पढ़ने से पता चलता है कि जो वर्ष 2018 में बजट पेश किया गया था, अभी वे चीजें धरातल पर नहीं उतरी हैं। जो घोषणाएं उस बजट में हुई थीं, वे जमीन पर अभी नहीं उतरी हैं और जो घोषणाएं थीं वे घोषणाएं ही रह गई हैं। दूसरे, जो वर्ष 2017 में दृष्टि-पत्र था, उस दृष्टि-पत्र पर भी हम अपनी नज़र दौड़ा रहे हैं। देखना यह है कि इस दृष्टि-पत्र की जो दृष्टि है, सरकार ने जो वायदे किए थे, उससे आम जनता पर कितनी दृष्टि पड़ी है। इसमें मैं अभी पढ़ रहा था कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पैंशन हेतु सरकार केन्द्र सरकार से परामर्श हेतु मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में पैंशन योजना समिति का गठन किया जाएगा। वेतनमान के लिए 4.9.14 के स्केल का अनुपालन किया जाएगा। कर्मचारियों के भुगतान से सम्बन्धित समस्याओं के लिए वेतन विभाग निवारण समिति का गठन किया जाएगा।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

11.03.2020/1620/SS-AS/1

श्री राजेन्द्र राणा क्रमागत :

कर्मचारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा, ऐसी बहुत सारी लम्बी लिस्ट है। पंचायतों में ग्राउंड बनाये जायेंगे, हर जिला पर स्टेडियम बनाया जायेगा, ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं अपने साथियों को यह ज़रूर कहना चाहूंगा किः-

"यह कहना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं,
यह कहना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं;
हम मशरूफ ज़रूर हैं पर बेखबर नहीं।"

इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है वह उम्मीद कर रही है कि हमारे से आपने कुछ वायदे किये थे उन पर आप काम करें।

दूसरा, बजट बुक का पहला पैराग्राफ है, हम भी बधाई देते हैं कि हमारे प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 वर्ष हो रहे हैं। गोल्डन जुबली है और इसको मनाया जायेगा तथा इसमें चर्चा भी हुई है। प्रदेश ने 50 साल में विकास व हर दृष्टि से लम्बी छलांग लगाई है। यह ठीक है कि हर सरकार का अपना योगदान रहता है। जो-जो सरकारें आईं, उन्होंने इसमें अपना-अपना योगदान दिया। अगर इस बजट बुक में यह भी चर्चा होती कि उस समय हमारे देश की जो प्रथम महिला प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं उसमें उनका भी धन्यवाद कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि प्रदेश के लोग उसकी तारीफ करते। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगर इसकी चर्चा बजट अभिभाषण में होती तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा होता। यह इसमें कमी रह गई है। बाकी बजट में बेरोज़गारी, महिलाओं पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। मुझे लग रहा है कि आज प्रदेश व पूरे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा बेरोज़गारी का है। बेरोज़गार दिन-प्रतिदिन बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। उनको कारोबार में सैट करने व उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करने हेतु सरकार अपना क्या योगदान दे रही है उस पर ज्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी।

11.03.2020/1620/SS-AS/2

दूसरा, इस बजट में कर्मचारियों के प्रति कोई नज़र नहीं दौड़ाई गई है। मैं चर्चा कर रहा था कि कर्मचारियों के साथ बहुत वायदे हुए और यह भी वायदा किया गया था कि यह जो

अनुबंध का समय तीन साल है इसे घटाया जायेगा। क्योंकि 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अनुबंध सिस्टम चालू हुआ। सबसे पहले 8 साल का समय था। फिर यह 6 साल का हुआ। फिर इसको 5 साल किया गया और उसके बाद राजा साहब ने इसको 3 साल किया। अब दो साल करने का जो वायदा था, उसमें चर्चा करते और उस वायदे को निभाते तो ज्यादा अच्छा होता। ....(व्यवधान) वह तो पेंशन वाला विषय था। 2008 में अनुबंध पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू हुई थी, इसका मेरे पास रिकॉर्ड है।

यहां पर बहुत चर्चा आई कि 1013 करोड़ रुपये मंडी हवाई अड्डे के लिए एलोकेट किये गए। अच्छी बात है, हवाई अड्डा बनना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : यह सिर्फ मंडी के लिए नहीं है बल्कि सारे हवाई अड्डों के लिए है।

श्री राजेन्द्र राणा : सुनिये, मैं आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूं कि 1013 करोड़ रुपया हवाई अड्डों के निर्माण के लिए रखा गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हवाई अड्डे बनाना केन्द्र सरकार का काम है, रेलवे लाइनें बनाना केन्द्र सरकार का काम है। प्रदेश में पिछली सरकार में भी कर्ज़ा लिया जा रहा था और कर्ज़ा लेने में आपने भी दौड़ लगाई है। पहले ही हम कर्ज़ा लेकर चल रहे हैं, प्रदेश कर्ज़े में डूबता जा रहा है और प्रदेश के खजाने से अगर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करेगी तो मुझे लग रहा है कि बाकी के काम रुकेंगे।

ऊना से हमीरपुर रेल लाइन के लिए बार-बार चर्चा आ रही है। हमारे जो माननीय सांसद साहब हैं वे पिछले 12 साल से ऊना से हमीरपुर रेल लाइन की बात कर रहे हैं। पिछली बार उनकी एक स्टेटमैंट आई कि 2800 करोड़ रुपये का प्रावधान हो गया, हालांकि प्रावधान नहीं हुआ था, बाद में उन्होंने उसे क्लैरीफाई किया। कहते हैं कि सर्वे हो गया। अब चर्चा यह हो रही है क्योंकि...

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2020/1625/केएस/एएस/1

श्री राजेन्द्र राणा जारी---

अगर हम चुने हुए लोग वायदा करते हैं तो जनता उम्मीद करती है कि हम उसको पूरा करेंगे। क्यों धीरे-धीरे लोगों का विश्वास पोलिटिकल सिस्टम से उठ रहा है? अब चर्चा आ रही है कि 50 परसेंट प्रदेश सरकार देगी। प्रदेश सरकार के पास तो वेसे ही पैसा नहीं है, वह कर्जा ले कर चल रही है। सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, डवलपमैंट के लिए पैसा नहीं है, कर्जा ले कर हम लोग चल रहे हैं तो रेलवे लाइन के लिए कहां से पैसा दे देंगे? मेरा कहना यह है कि यह जो डबल इंजन वाली सरकार है, आप कोशिश करिए, अपने इंजन को भी स्टार्ट करिए और जो केन्द्र में इंजन है, उस पर भी थोड़ा सा सैल्फ मारिए ताकि वहां से कुछ पैसा मिले और केन्द्र सरकार की जिम्मेवारियों को भी सरकार निभाए।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सत्ता पक्ष के हमारे साथियों ने सरकार के इस बजट की तारीफ़ की है । इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए परन्तु पुल भी बांधे हैं, फ्लाई ओवर भी बांधे हैं, यह प्रैक्टिस बड़े लम्बे समय से चली आ रही है । इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में 5.6 परसेंट विकास दर हिमाचल प्रदेश में अनुमानित है। ऑल इंडिया लैवल पर हमारे देश में विकास दर 4.5 परसेंट है और हम आलोचना करते हैं अपने पड़ौसी देशों की कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया। आप बांग्लादेश देखिए, वहां की विकास दर 8.2 है और पाकिस्तान की 5.5 है। हम कहां जा रहे हैं, आज देश के हालात क्या है? आज देश में 176 लाख करोड़ रुपया जो आर.बी.आई. के पास पड़ा था, केन्द्र सरकार उसको ले गई। रिज़र्व पैसा था और रिज़र्व पैसा इसलिए रखा जाता है कि विदेशों से कोई भी एफ.डी.आई. में इन्वैस्टमैंट करता है, तो देखता है कि देश के खजाने में क्या भरा है? तो वे खजाने तो खाली कर दिए गए हैं। अभी और पैसा लेने की बात कर रहे हैं। आर.बी.आई. के गवर्नर धीरे-धीरे एक के बाद एक छोड़ता गया, उसका कारण क्या

था? आज इस बात की चर्चा हो रही है कि आर.बी.आई. के गवर्नर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दवाब बनाया जाता है कि आप गलत काम करिए। देश की

11.03.2020/1625/केएस/एएस/2

इकोनॉमी की तो क्या बात करें। आज हिन्दुस्तान की इकोनॉमी इस तरीके से गिर गई है, आज हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। वे इसलिए बंद हुई क्योंकि देश में नोटबंदी हुई। नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कहते थे कि नोटबंदी से आतंकवादियों की फंडिंग रुक जाएगी लेकिन वह तो नहीं रुकी। आप कहते थे कि इसमें जाली करंसी ...(व्यवधान) यह बजट से जुड़ी है। भारद्वाज जी, आपके साथी तो दुनिया भर की चर्चा कर रहे थे, हम तो बजट से जुड़ी हुई बात ही कर रहे हैं। ...(व्यवधान) देश की वित्तीय स्थिति क्या है? आप सुनिए, सुनने में क्या है? ... (व्यवधान) मैं तो देश की बात कर रहा हूं। आपने केन्द्र सरकार का इस बजट में ज़िक्र किया है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, आपको क्या लगता है कि नोटबंदी से जाली करंसी मार्किट में आना बंद हो गई? नहीं हुई, वह तो और भी ज्यादा हो गई और मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आज हज़ारों की तादाद में हिन्दुस्तान में उद्योग बंद हो गए और उससे करोड़ों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए। ...(व्यवधान) मैं एक आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आप ज़रा सुनिए तो। जब कोई छोटी सी आलोचना हो रही हो तो उसको पॉज़िटिवली लेना चाहिए। अगर हज़ारों की तादाद में उद्योग बंद हुए हैं तो उसके क्या नुकसान हुए हैं? उससे बेरोज़गारी और बढ़ गई और भारत सरकार को जो टैक्स आने थे, वे बंद हो गए। तभी तो आपकी सरकार घाटे में जा रही है। गलत नीतियों के कारण।आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आज देश में बैंक बूरी तरह फेल हो रहे हैं। लोगों अपने खून-पसीने की कमाई को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। ...(व्यवधान) आज इस सरकार में अगर इंडस्ट्री चल रही है, ...(व्यवधान) भारद्वाज जी, आप कृपा करके सुनने की भी थोड़ी हिम्मत रखें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

म11.03.2020/1630/AV-dc/1

श्री राजेन्द्र राणा-------- जारी

...(व्यवधान) हमारे देश में आज अगर इंडस्ट्री बंद हो रही है तो आम आदमी की इंडस्ट्री बंद हो रही है और केवल 4-5 औद्योगिक घरानों की इंडस्ट्री फ्लोरिश हो रही है जिनकी आमदनी कई गुणा बढ़ गई है। इस बजट बुक में यह चर्चा भी आई है कि महंगाई पर नियंत्रण कर लिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों को लग रहा होगा कि महंगाई पर नियंत्रण कर लिया गया है। अगर आप आम जनता के बीच में जायें तो पायेंगे कि लोग महंगाई से ग्रस्त है। यहां पर यह भी कहा गया है कि किसान की आमदनी को दो गुना बढ़ाया जायेगा और उनको 6,000 रुपये वार्षिक दिए जायेंगे। यदि आपको यह लग रहा है कि 500 रुपये प्रति माह देने से आप लोग किसानों को अमीर कर देंगे तो आप इस तरह की गलतफहमी में मत रहना। यहां पर स्मार्ट सिटी की चर्चा भी आई। प्रदेश में धर्मशाला और शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी मगर अभी तक उस स्मार्ट सिटी के नाम पर एक नई ईंट नहीं लग पाई। मैं बजट बुक पढ़ रहा था और मैंने पाया कि जिला हमीरपुर तो विकास की दृष्टि से गायब ही हो गया है। इस बजट बुक में इस बात की बिल्कुल चर्चा नहीं है कि जिला हमीरपुर भी कोई नाम है। यदि मण्डी जिला के दो या तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं और उससे आप लोगों को लगता है कि पूरे प्रदेश में विकास हो गया; तो मुझे लगता है कि आप लोग गलतफहमी में जीने की कोशिश कर रहे हैं। इस बजट बुक में दिखाया गया है कि 7,272 करोड़ रुपये का घाटा है; इस घाटे को कहां से पूरा करेंगे आप उसके बारे में भी बता देते। लेकिन उसके बारे में इस बुक में कोई चर्चा नहीं है। यहां पर कर्ज़ के बारे में बहुत बातें की गई हैं और कहा गया कि कर्ज़ तो पिछली सरकार के कार्यकाल में भी लिया गया। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि पिछली सरकार ने कर्ज़ लिया और हम इस बात को मानते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान आप लोगों

ने हर मंच पर यह बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्ज़ लेकर चलती रही; तो आप कर्ज़ नहीं लेते। अगर आप ऐसा करते तो हम लोग भी आपकी पीठ थपथपाते कि आपने डबल ईंजन से काम चला लिया परंतु आज आप भी

11.03.2020/1630/AV-dc/2

कर्ज़ ले रहे हैं। मैं यहां पर यह चर्चा भी जरूर करना चाहूंगा कि सुजानपुर में धौलासिद्ध प्रोजैक्ट अब शुरू हुआ है और उसके लिए ज़मीन भी खरीदी जा रही है तथा हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु अफसोस इस बात का है कि लोगों के बार-बार एजिटेशन करने के बाद भी सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। वहां पर एक रिटायर्ड एच0ए0एस0 अधिकारी को लगाया गया है। वहां लोगों को डरा-धमकाकर ज़मीन खरीदी जा रही है। वहां पर लोगों का यह कहना है कि यदि सरकार फैक्टर-iv की बात करती है तो हमारी ज़मीन एक्वायर करती। लोगों का नुकसान किया जा रहा है तथा वहां पर लोगों को डरा-धमकाकर ज़मीन खरीदी जा रही है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र में नाबार्ड के अंतर्गत प्रोजैक्ट्स पर 70 करोड़ रुपये के लगभग व्यय हुआ है। सरकार को चाहिए कि नाबार्ड के पास जो डी0पी0आर्ज0 पड़ी हैं उनको परसू करें और सुजानपुर का जो हिस्सा बनता है वह उसको दिलाएं तथा प्रोजैक्ट्स के लिए पैसा भिजवाएं। जब बाकी के निर्वाचन क्षेत्र 105 करोड़ रुपये क्रॉस कर गये हैं तो सुजानपुर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इस सरकार के कार्यकाल में तो सुजानपुर में एक ईंट भी नहीं लगी; अगर कहीं लगी है तो आप बताएं कि सुजानपुर में भाजपा की सरकार ने फलां-फलां ईंट लगाई है। वहां पर टाउन हॉल के लिए पिछली सरकार ने 75 लाख रुपये की राशि दी थी मगर अढ़ाई वर्ष की समयावधि बीत जाने के बाद भी वहां पर एक ईंट तक नहीं लग पाई। सुजानपुर में मैडिकल और पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन तथा सिविल हॉस्पिटल के लिए एडिशनल बिल्डिंग स्वीकृत हुई थी परंतु उसके नाम पर भी एक ईंट नहीं लगी। वहां पर उन बिल्डिंग्ज को गिराने के लिए विभाग कुछ नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त आंशला में अढ़ाई वर्ष पहले 33 के0वी0 स्टेशन का

शिलान्यास रखा गया था मगर उसका काम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। इस सरकार को बनाने में सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का भी योगदान है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां की जनता की अनदेखी न की जाए।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2020/1635/TCV/DC-1

श्री राजेन्द्र राणा.... जारी

इस बजट में कुछ चीजों को छोड़कर सारी-की-सारी पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। यह ठीक है कि पुरानी योजनाएं भी आगे बढ़नी चाहिए लेकिन नई योजनाएं भी होनी चाहिए। कुछ नई योजनाएं भी हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। विधायक निधि की राशि जो 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये की गई है और जो 2.0 लाख रुपये ऐच्छिक निधि के बढ़ाये हैं, उसकी हम तारीफ़ करते हैं और इनका स्वागत भी करते हैं। यहां पर ज़िक्र किया गया कि 4.66 करोड़ रुपया सी0आर0एफ0 में आया है लेकिन 225 करोड़ रुपया एक ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र में चला गया। सरकार को चाहिए कि सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को समानता की दृष्टि से पैसा डिस्ट्रिव्यूट करें ताकि लोगों में रोष प्रकट न हों। यहां पर चर्चा हुई कि दवाइयां फ्री में दी जा रही हैं, कांगड़ा में दवाइयों के लिए 11.50 करोड़ रुपया खर्चा गया, अध्यक्ष महोदय, यह आपका जिला है। अच्छी बात है, गरीब लोगों को दवाइयां मिलनी चाहिए। ऊना जिला में 11 करोड़ रुपये दवाइयों पर खर्च किए गये और हमीरपुर में सिर्फ 4 करोड़ रुपये दवाइयों पर खर्च किए गये। सरकार को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए कि कहीं गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। इस हाउस में सारे लोग चुनकर आये हैं, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है और सरकार का यह प्रैरोगेटिव है कि उनको कैसे इंप्लीमैंट करना हैं? कहते हैं कि :-

लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है,
जबकि भी उठेंगे तो तूफ़ान बनकर उठेंगे,
बस अभी उठने की ठानी नहीं है।

अभी आप अढ़ाई साल गुजार लो और खुशी-खुशी गुजार लो। उसके बाद आपकी ट्रांसफर होने वाली है। बड़े-बड़े लोग इस गलतफ़हमी में चले गये, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार लोगों के पास है और यह अधिकार जनता के पास ही रहना

11.03.2020/1635/TCV/DC-2

चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में 'नई बोतल और पुरानी शराब' जैसा हाल है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार सभी चुनाव क्षेत्रों में अपनी दृष्टि दौड़ाये और जो घोषण-पत्र है, उस पर भी दृष्टि दौड़ाये ताकि अगली बार आपके बारे में लोग कुछ सोचें। आप अच्छा काम करेंगे तो लोग ज़रूर सोचेंगे अगर वायदा-खिलाफ़ी करेंगे तो लोग उस दृष्टि से सोचेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2020/1635/TCV/DC-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने निर्धारित समय में अपनी बात पूरी की है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भाग लेंगे। कृपया आप भी निर्धारित समय में अपनी बात पूरी करें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने इस माननीय सदन में हिमाचल प्रदेश विधान सभा का जो बजट 6 मार्च, 2020 को पेश किया है, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट इस माननीय सदन में पेश हुआ है जिसमें किसी के ऊपर कोई कर नहीं लगाया गया है। आज तक के इतिहास में जब भी इस सदन में बजट पेश होते हैं, किसी-न-किसी वर्ग को कर का बोझ झेलना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्राप्त करने के 50 वर्ष के अवसर पर मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि यह वर्ष 'हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती वर्ष' के रूप में मनाया

जाएगा। इसके अलावा इन्होंने प्रशासनिक सुधार में भी बहुत-सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसका रिजल्ट इस प्रदेश की जनता को विकास की दृष्टि से मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो लोक सभा के इलैक्शन हुए थे

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

11.03.2020/1640/RKS/HK-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

तो उस चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे मित्रों को सब कुछ दिखाया लेकिन इन्हें अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। ये वर्ष 2022 का इंतजार कर रहे हैं। लोक सभा चुनाव में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है और प्रदेश की जनता ने 69 प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाले हैं। इस तरह आदणीय जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास बनाया है। इस प्रदेश में जो 6 बार मुख्य मंत्री रहे हैं वे भी आज तक सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में लीड नहीं दिला पाए हैं और न ही इतना ज्यादा वोट प्रतिशत दिला सके हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने आदरणीय जय राम ठाकुर जी की कार्य-प्रणाली स्वीकार की है और उस पर अपनी मोहर लगाई है। इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'जनमंच कार्यक्रम' शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत एक माइक किसान बागवान, शोषित और वंचित लोगों के पास होता है, एक माइक मंत्री के पास होता है और एक माइक डी.सी., एस.पी. और जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है जो लोगों की शिकायतों का जवाब देते हैं। हमने ऐसी कार्य-प्रणाली राम राज्य में सुनी थी। आज तक के इतिहास में किसी भी स्टेट ने इस प्रकार की कार्य-प्रणाली शुरू नहीं की थी। यह कार्य-प्रणाली पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। इस प्रणाली के तहत प्रदेश की जनता द्वारा 47,848 शिकायतें की गई थी जिनमें से 43,548 शिकायतों का निवारण प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने ई-समाधान भी लाया है। इसमें लोग अपनी किसी भी समस्या की

शिकायत कर सकते हैं और अधिकारी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके घर जाते हैं या उनसे दूरभाष द्वारा कॉंटैक्ट करते हैं। ई-समाधान के तहत लोगों की बहुत सारी समस्याएं हल हो रही हैं। इसमें 37,990 शिकायतों का संतोषजनक निवारण किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 7-8 नवम्बर को धर्मशाला में इन्वैस्टर मीट का आयोजन किया गया था जिसका अध्यक्षता देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र

11.03.2020/1640/RKS/HK-2

मोदी जी ने की थी। 13,656 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन 27 दिसम्बर, 2019 को ग्राउंड लैवल में लागू किया गया है। इस इन्वैस्टर मीट से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इस इन्वैस्टर मीट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे उद्योग स्थापित होंगे और जो प्रदेश सरकार को रेवेन्यू मिलेगा उससे कई वर्षों के ऋण से भी छुटकारा मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में चौथा नारा माननीय मुख्य मंत्री ने यह जोड़ा है- भ्रष्टाचारियों का विनाश। माननीय मुख्य मंत्री ने भ्रष्टाचारियों के विनाश के लिए ऐसे दृढ़ संकल्प लिए हैं जिसमें पूर्व सरकार के समय हुए भ्रष्टाचारों को खत्म करने व प्रदेश में दोबारा भष्टाचार न हो, के लिए कठोर कदम उठाये गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2019-20 में लगभग 210 लाख करोड़ रुपये (3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) के करीब है। जिन्होंने हिन्दुस्तान में राज किया, हम उनसे भी आगे यानी यूनाइटिड किंगडम एवं फ्रांस से भी आगे पहुंचे हैं। भारत अब विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गई है और यह हम सबके लिए गौरवान्वित की बात है। माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक इस अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बनाना है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

11.03.2020/1645/बी.एस./एच.के./-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

आने वाले समय में हिन्दुस्तान विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था वाला देश होगा ऐसी योजना देश के प्रधान मंत्री जी ने बनाई है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी किसानों को आज तक कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, किसान वंचित एवं शोषित थे, वे अपनी दो वक्त की रोटी के लिए जूझते थे। जब फसल आंधी-तूफान से उड़ जाती थी और फसल का कोई नुकसान होता था तो उनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी घर में नहीं होती थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने "किसान सम्मान निधि योजना" इस देश के अंदर लाई है जिसमें करोड़ों किसानों को इसका फायदा हो रहा है। सब किसानों को छह हजार प्रति वर्ष दिया जा रहा है जिससे उन्हें अपने खेत और अपने सोने को गिरबी रखने की आवश्यकता नहीं है। "प्रधान मंत्री श्रम योजना" इसे भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ले करके आए हैं। "प्रधान मंत्री आवास योजना", "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना", इस देश में किसानों की आय दोगुनी हो इसके लिए देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री कृषि योजना लाई है। जैसा मेरा चौपाल का क्षेत्र है यह बहुत ही दूर-दराज वाला क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र को पहली बार 32 करोड़ रुपए की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना मिली है। आजादी से ले करके 70 वर्ष में कभी भी सिंचाई के लिए हमारे को करोड़ों में पैसा नहीं मिला। इस योजना के तहत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पहली बार मेरे चुनाव क्षेत्र में इतना पैसा मिला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने "गृहिणी सुविधा योजना" एक ऐसी योजना प्रदेश के अन्दर लाई है और देश के अन्दर आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सरकार ने "उज्ज्वला योजना" लाई है। जिसमें 8 करोड़ के करीब देश की गरीब जनता को चूल्हा एवं सिलेंडर मिला था। हिमाचल प्रदेश के अन्दर 2.75 लाख लोगों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत इसका लाभ मिला है। जो महिलाएं दिन को काम करती थीं और उसके बाद गीली लकड़ियां ला करके अपने परिवार का खाना बनाती थी और उस गीली लकड़ी से इतना धुंआ उनके पेट में जाता था जिससे हजारों बीमारियां होती थी उन बीमारियों से निजात पाने के लिए सभी गांव की महिलाएं आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी का गुणगान गाती हैं और बहुत ब्लेसिंग्ज देती

11.03.2020/1645/बी.एस./एच.के./-2

हैं कि मुख्य मंत्री जी ने हमें सैंकड़ों बीमारियों से बचाया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसान ऐंटी हेल गन यहां पर योजना लाई है और नई खुशी नामक योजना से इसे चलाया है। हमारे बगीचों में जो नैट लगते थे उसमें बांस और परमानेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवैल्प करने के लिए भी पहली बार इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का सभी बागवानों की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इससे किसान एवं बागवानों को काफी लाभ मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश में गो-सदन खोलने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने योजना लाई है। पहली बार गो- मोबाइल वैटरिनरी योजना आरंभ की है। यह एक सेवा है क्योंकि पशुओं ने सराकर को कोई वोट नहीं देना, पशुओं से सरकार को कोई फायदा नहीं होना परंतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के अंदर जो एक सेवा भाव है इससे उस बात का अवश्य पता चलता है। उस भावना से यह कार्य इन्होंने शुरू किया है। "पर्वत धारा नई योजना" इस प्रदेश के अन्दर जो हमारे पानी के स्त्रोत थे उनके जीर्णोद्धार प्रवाह सिंचाई परियोजना में 20 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार खर्चेगी। जिससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होगा।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

11.03.2020/1650/DT/YK-1

यह योजना वर्तमान सरकार द्वारा लाई गई है। इसके लिए भी माननीय मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। पंचायती राज्य संस्थाओं में पंचायत के बी0डी0सी0 मेम्बरज़, जिला परिषद मेमरज़ इनके लिए पहली बार 429 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पहले सरकार के द्वारा बहुत छोटा बजट प्रोविजन इसमें रखा गया था जिससे सभी तक यह पैसे नहीं पहुंचते थे। जब चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के बीच जाने का मौका मिलता था तो उनके दिल में कुछ-न-कुछ जनता की सेवा करने की भावना होती थी, पर उनके पास

बजट नहीं था। इसके लिए पंचायती राज के सभी प्रतिनिधि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं की उन्होंने इस पंचायती राज क्षेत्र में भी इस प्रकार से धन उपलब्ध करवाया है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी किसान या बागवान ने अगर ट्रेक्टर खरीदना है और अगर उस ट्रेक्टर की कीमत 6 लाख रूपये है तो उसको 3 लाख रूपये की सब्सीडी वर्तमान जयराम सरकार द्वारा दी जायेगी। हिमाचल प्रदेश के किसानों को पहले 75 पैसे में पर युनिट बिजली दी जाती थी अब 75 पैसे से घटाकर इसे 50 पैसे पर-युनिट किया गया है। किसानों को इससे भी बहुत राहत मिलेगी। इसके लिए भी माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं। हमारे विपक्ष के मित्र कहतें हैं कि डबल-ईंजन का कुछ भी असर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। देश के अन्दर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो युनियन बजट 2015-16 में 90:10 अनुपात का जो स्टेटस था वह भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए दिया है। कोई भी सेन्टर की स्कीम आती थी उसमें पहले 60:40 को अनुपात होता था यह 90:10 अनुपात भी हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार के वर्ष 2015-16 के बजट के द्वारा दिया गया है। प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत दो साल में 2013-14 में 523 करोड़ रूपये प्रदेश को मिला है। वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश को 2415 करोड़ रूपये मिला है और यह पांच गुणा पैसा है

11.03.2020/1650/DT/YK-2

जो हिमाचल प्रदेश को मिला है सिर्फ दो साल के अन्दर। यह डबल ईंजन का ही प्रभाव है। प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना में चाहे रोहडू हो, चाहे ठियोग हो, चाहे चौपाल हो अगर यह प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना न आती तो अभी भी हमारी 50 प्रतिशत पंचायतें सड़कों से वंचित होती। हिमाचल प्रदेश के अन्दर जितने भी इन्टिरीयर है चाहे किन्नौर हो, चाहे भरमौर हो जितने भी हमारे इन्टिरीयर क्षेत्र हैं यहां सारी सड़के प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी है। प्रदेश में पच्चास साल और लगते अगर देश में भारतीय जनता पार्टी यह योजना न लाती। आज हिमाचल प्रदेश के अन्दर 65 पंचायतें ही सड़कों से वंचित हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो 37000 किलो मीटर सड़क बनी है उसमें लगभग

14000 कि0मी0 प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनी है। मेरे चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा सड़के आज की तिथि में 1106 कि0मी0 चौपाल में बनी हैं और मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 500 कि0मी0 सड़के प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हैं। अगर यह योजना न आती तो चौपाल में पच्चास साल बाद भी बहुत सारी पंचायतों में सड़कें पहुंचाने में बहुत दिक्कतें आती। पिछड़े क्षेत्रों के लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने ए0डी0बी0पी0 कार्यक्रम शुरू किया है इसमें जो क्षेत्र बेकवर्ड क्षेत्र में पहले नहीं आये हैं, जिस क्षेत्र में अभी भी विकास की दृष्टि से बेकवर्ड पंचायतें नहीं हैं जिसमें सड़क, स्वास्थ्य स्कूल की सहुलत नहीं है, ऐसे क्षेत्र को आइडेन्टीफाई करके इस योजना के तहत लाने का प्रावधान है, यह कदम भी काबिले तारीफ है। इसमें हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्र जो अभी भी बेकवर्ड की सूचि में नहीं हैं वह इसमें शामिल किये जायेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने विधायक प्राथमिकता को 105 रूपये से बढ़ाकर जो 120 रूपये की है, यह कदम भी काबिले तारीफ है। इसमें मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से एक आग्रह करना चाहूंगा कि विधायक प्राथमिकता की जो योजना है हिमाचल प्रदेश के अन्दर 1996 में यह शुरू की गई थी और 1996 के बाद अभी तक किस क्षेत्र को कितना पैसा मिला इस तरह का प्रावधान नाबार्ड में होना चाहिए। अगर इसे 2014 के बाद लेंगे तो 2014 तक चौपाल में 15-16 साल में केवल 11 करोड़ मिले

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

11-03-2020/1655/वाई.के.-एन.जी./1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी.....

और मेरे कार्यकाल में 7 साल के दौरान चौपाल को लगभग 95 करोड़ रुपये मिले हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यदि इस राशि को नहीं बढ़ाते तो हमारे लिए विधायक प्राथमिकता की बैठक का कोई औचित्य ही नहीं रहता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक क्षेत्रिय विकास निधि को 1 करोड़ 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख रूपये कर दिया है जोकि बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में ''स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसमें 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में इस योजना के अन्तर्गत 68 स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा जिसमें फर्नीचर का प्रावधान, विद्यालय प्रांगण विकसित करना, खेल कूद सुविधाओं में सुधार, जिम, स्मार्ट क्लास तथा विज्ञान प्रयोगशालाएं, बेहतर शौचालय और पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों में अग्रीम शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1 लाख रुपये अनुदान साहयता देने की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसे वर्ग जिनसे कोई वोट का नाता नहीं है उनके लिए एक नई योजना ''स्वस्थ बचपन'' लाई है जोकि प्री-प्राईमरी स्कूलों के लिए है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में 'आयुष्मान भारत योजना' लाई थी जिससे देश के गरिबों का कल्याण हो रहा है। सारे देश के वंचित, शोषित और गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, उन्हें अपने इलाज के लिए अपने गहने, खेत आदि गिरवी रखने पड़ते थे, ऐसे लोगों के लिए देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'आयुष्मान भारत योजना' लाई थी।

11-03-2020/1655/वाई.के.-एन.जी./2

उसी योजना के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी 'हिम केयर योजना' लेकर आए जिसमें हिमाचल प्रदेश के 3 लाख 12 हज़ार परिवारों को लाभ मिला। हिमाचल प्रदेश में 'सहारा योजना' के तहत जिन परिवार के सदस्य कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं और उनके पास कोई भी सहारा नहीं है उन व्यक्तियों को सहारा योजना के तहत पहले 2,000 रुपये मिलते थे और इस बजट में इस धनराशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। हमारे विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपये खर्च करके उन गरीब परिवारों के लोगों का

इलाज क्यों किया गया? मैं इस माननीय सदन में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार विपक्ष के नेता ने यहां पर कहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि गरीब परिवार का इलाज करें, क्या उन्हें मरने दिया जाए, उनकी पीड़ा को न सुने और उसे दूर न किया जाए। जिस प्रकार विपक्ष के नेता ने इस माननीय सदन में कहा है उस प्रकार वह एक बार जनता के बीच में कह दें कि गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों का इलाज नहीं होना चाहिए। यदि उनकी ऐसी भावना है तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो वह विपक्ष में भी बैठे हैं लेकिन आने वाले समय में वह इस माननीय सदन के सदस्य भी नहीं रहेंगे यदि उनमें वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों की सेवा का भाव न हो, नियत और नीति साफ न हो और कर्म में पवित्रता न हो। इन्होंने जो बात कही है कि गरीब का इलाज नहीं होना चाहिए, उनके इलाज के लिए जो पैसा खर्च किया गया है वह क्यों किया गया है उससे सभी माननीय सदस्य बहुत आहत हुए हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंडअप करें क्योंकि चर्चा की समयावधि केवल पांच बजे तक है।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय दे दीजिए।

11-03-2020/1655/वाई.के.-एन.जी./3

अध्यक्षः माननीय सदस्य समयावधि पांच बजे तक ही है यदि समय बढ़ाना है तो बता दीजिए।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, कृपया 10-15 मिनट समय बढ़ा दीजिए।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्य कभी-कभी बोलते हैं इसलिए सदन का समय 10-15 मिनट बढ़ा दीजिए।

अध्यक्षः ठीक है, माननीय सदन की कार्यवाही का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

(माननीय सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया गया)

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, पहली बार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमैंट फंड को बढ़ाकर 454 करोड़ रुपये किया गया है जोकि 158 प्रतिशत अधिक है। पहली बार प्रदेश के अंदर इस तरह का बजट इतना बढ़ाया गया है। चौपाल चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत अभी बरसात में हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

11/03/2020/1700/MS/YK/1
श्री बलबीर सिंह जारी----

और 92 की 92 सड़कें बन्द हुई थीं। इस योजना से दूर-दराज़ के क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में कभी भी ऐसी आपदा आए तो इसके लिए सरकार के पास रैडी रेफ्रेंस में बजट होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने "स्वर्ण जयन्ती पोषाहार योजना" महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए लाई है, यह भी बहुत ही काबिले-तारीफ योजना है। इससे भी जो वंचित और शोषित गरीब महिलाएं/बच्चे हैं उनको काफी फायदा होने वाला है। प्रदेश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश में 15 अगस्त को "जल जीवन मिशन" नामक एक नई योजना शुरू की थी और इस योजना के तहत हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी और बहुत ही जुझारू और मेहनती मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को हिमाचल के इतिहास में इस विभाग में पहली बार इतने बजट का प्रावधान किया है। 2900 करोड़ रुपये से 327 परियोजनाएं लाभान्वित होंगी और इससे मेरे चौपाल जैसे दूर-दराज़ के क्षेत्र में जहां पर आज तक आजादी के 70 वर्ष के बाद भी 100 करोड़ रुपये क्या 50 करोड़ रुपये भी पानी के लिए नहीं मिले, एक-दो साल के अंदर ही आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में और आदरणीय जय राम जी की मेहनत से डी0पी0आर0 बनाई गई जिससे 105 करोड़ रुपये के करीब चौपाल चुनाव क्षेत्र को फायदा होने वाला है। इसके लिए चौपाल की ही जनता नहीं बल्कि प्रदेश की समस्त

ग्रामीण क्षेत्र की जनता आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी का और महेन्द्र सिंह जी का दिल की गहराई से धन्यवाद रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना" इस प्रदेश के अंदर लाई है जिसके तहत 18 से 45 वर्ष के नौज़वान को 60 लाख तक की ऋण सुविधा दी गई है जिसमें 25 परसेंट पुरूषों के लिए है और युवतियों/महिलाओं के लिए 30 परसेंट तथा 45 वर्ष तक की विधवाओं के लिए 35 परसेंट उपदान दिया है। इससे नौज़वानों को स्वयं तो काम मिला ही है लेकिन आगे भी उनकी काम देने की क्षमता बढ़ गई है। अब आगे भी वे किसी नौज़वान को काम दे रहे हैं। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के नौज़वानों को लाभ हो रहा

11/03/2020/1700/MS/YK/2

है फिर चाहे वह कुपवी क्षेत्र की बात हो या अन्य किसी पिछड़े क्षेत्र की बात हो, सभी जगह यह योजना पहुंच रही है और वहां के नौज़वान इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के अंदर 2000 लोकमित्र केन्द्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर "सामाजिक सुरक्षा पैंशन" के अंतर्गत वर्ष 2017 के अन्त तक इस प्रदेश के बुजुर्गों/विकलांगों/विधवाओं को 650/-रुपये मिलते थे। पहली बार 130 परसेंट वृद्धि अगर किसी पैंशन में किसी ने की है तो वह आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने की है और उन्होंने इसे सीधे 1500/-रुपये किया है। इस तरह से 70 से 80 साल के बुजुर्गों को इस योजना के अंतर्गत 1500/-रुपये मिल रहे हैं और इस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद आदरणीय जय राम ठाकुर जी को मिल रहा है तथा उनके आशीर्वाद से ही ये फल-फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।

इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जो हमारे दिहाड़ीदार हैं उनकी दिहाड़ी 250/-रुपये से बढ़ाकर 275/-रुपये की है। उस दिहाड़ी में एक दिन का 25/-रुपये बढ़ा है यह भी बहुत ही काबिले-तारीफ है और यह आज तक का रिकॉर्ड है।

हिमाचल प्रदेश के अंदर "स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना" के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के लिए 5100 आवास बनेंगे। ऐसी योजना अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं आई है। "मुख्य मंत्री आवास योजना" के

अंतर्गत भी 3100 आवास और प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)के अंतर्गत 1000 आवास तथा प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 800 घर बनेंगे।

बेसहारा लोगों के मुफ्त उपचार के लिए भी मुख्य मंत्री जी ने एक नई योजना लाई और इसकी भी शुरूआत माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप करें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने दो लाइनें कहना चाहता हूंः

अगर मरहम लगा सके तो किसी गरीब के जख्मों पर ही लगाना
क्योंकि हकीम बहुत है बाजारों में अमीरों के इलाज की खातिर॥

जारी जे0के0 द्वारा----

11.03.2020/1705/JK/AG/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत सारी योजनाएं इस प्रदेश के अंदर लाई हैं। गांव को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं इस बजट में लाई गई हैं। मैं अपने भाषण के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव वर्ष के आने पर सभी सरकारें बहुत सारी योजनाएं लाती हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहले वर्ष ही 30 योजनाएं लाई, दूसरे वर्ष भी लाई और तीसरे वर्ष अभी भी लगभग 25 नई योजनाएं लाई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को चंद शब्द कहना चाहूंगा किः-

दिल में गरीब का दर्द है, नीयत में खोट नहीं,
आपकी आंखे गरीबों को देखती हैं, उनके वोट नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 12 मार्च, 2020 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 11 मार्च, 2020 **सचिव ।**